खण्ड-272, अंक-10
शनिवार, 10 आषाढ़, शक संवत् 1889
(1 जुलाई, 1967 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 272 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६७

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | १–५ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. | ५–३५ |
| सर्वश्री लोटनराम, रामेश्वर सहाय, जगदीशसिंह तथा माधोनारायण मुद्गल के निधन पर शोकोद्गार .. .. .. | ३५–३७ |
| सदन के अवशिष्ट कार्य-क्रम को कार्य सूची में सम्मिलित न करने तथा सरकार के कथित वैधानिक रूप से गठित न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न .. | ३७–४३ |
| उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् परिषद् तथा न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों के लिये अवधि) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. .. .. .. | ४३ |
| उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. .. .. | ४३–४४ |
| उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. .. | ४४ |
| उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. .. .. | ४४ |
| उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पांचवां संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. .. .. .. | ४४–४५ |
| उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. | ४५ |
| उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. .. .. | ४५ |
| उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वेतन या मजदूरियों से कटौती करके किराये की वसूली के लिये अनुबन्ध) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. .. .. .. | ४५ |
| उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. .. .. | ४५–४६ |
| उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविधाओं और हस्तान्तरण–पत्रों का निष्पादन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. | ४६ |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) .. .. .. | ४६ |
| सदन के परिसर में कांग्रेस के अवंटित कमरे को यू० पी० सेक्रेटेरियट मिनिस्टीरियल) आफिसर्स एसोसियेशन की बैठक के लिये दिये जाने के संबंध में श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. .. .. | ४६–४८ |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

---

## उपस्थित सदस्य—३५८

अंगनलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झाँसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अशरफ अली खाँ, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कंधई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झाँसी))
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमला पति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरीलाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री

गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चतराम पचपेड़ा, श्री
चतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगपत सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द,श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जेजयाउर्रहमान, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
वित्त सिंह, श्री

झारखण्डे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पाती राम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारे लाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री

बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलबीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भोखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल आचार्य, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झाँसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खाँ, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर,श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री

राम अंजोर, श्री
रामअचलसिंह सेन्गर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रमचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलारे पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामनारायण, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रमबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूप नाथ, श्री
रूप नरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर, पाण्डेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
बिशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
बीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री

सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मतसिंह, श्री
हुकमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

---

## समाचार-पत्र में प्रकाशित स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हमारी एक इल्तजा है। हम लोग भी चुनकर आये हैं और बड़े बहुमत से आये हैं। हमारे क्षेत्र के लोग भी आशा करते हैं कि उनके बारे में भी हम लोग बातचीत करें। लेकिन हम लोगों के बार-बार उठक-बैठक करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, हमें भी मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दत्ता जी, आपकी जो इच्छा है वह स्वाभाविक है। हर माननीय सदस्य की ऐसी इच्छा अवश्य होगी और मैं जितना कर सकता हूं, अवश्य करूंगा।

श्री कृष्णानंदराय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आपने एक व्यवस्था दे रखी है कि जब सदन चलता रहे तो मंत्री लोग नीति संबंधी या महत्वपूर्ण वक्तव्य सदन के बाहर न दें और जब हम लोग मंत्रियों से संबंधित प्रिविलेज का मोशन मूव करते हैं तो श्रीमन्, अस्वीकार कर देते हैं। कल की घटना है कि स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रतापसिंह जी ने बहराइच में ओछी और उच्छृंखल बात कांग्रेस दल के बारे में कही और महत्वपूर्ण घोषणा की अस्पताल की दवाओं के बारे में और भवन निर्माण के बारे में कि कितना खर्च होना चाहिये। आज के "स्वतंत्र भारत" में उनका भाषण निकला है। उन्होंने यही नहीं किया, बल्कि श्रीमन्, इस सदन में जो कांग्रेस का विरोधी दल है और बहुत बड़ी संख्या में डेमोक्रेटिक तरीके से काम करता है, बहुत ही उच्छृंखल और ओछे ढंग से (व्यवधान) आप अपनी व्यवस्था दें।

(श्री कृष्णानन्द राय—बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष—

मैं इस तरह से कैसे व्यवस्था दे सकता हूं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझा नहीं कि आप क्यों बैठ गये। आपसे मैंने बैठने को नहीं कहा था। आप अपने आप बैठ गये।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, लोग खड़े हो गये तो मैं बैठ गया।

श्री राजराजेश्वर (जिला खीरी)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले बैठिये। जब एक व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है तो बीच में व्यवस्था का दूसरा प्रश्न नहीं उठ सकता।

श्री राजराजेश्वर—

श्रीमन्, 'उच्छृंखल और ओछे' शब्द असंसदीय हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी देखता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं समझता हूं कि मंत्री लोग जिन शब्दों का प्रचार कर रहे हैं असंसदीय नहीं हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस पर रूलिंग आपकी नहीं होगी, मेरी होगी।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं समझ नहीं रहा हूं। माननीय सदस्य मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अगर सारे माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान से बोलेंगे तो सदन का कार्य नहीं चल सकेगा। आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मंत्रियों के जो नीति संबंधी वक्तव्य सदन के होते हुये बाहर हो रहे हैं...।

श्री अध्यक्ष—

इस समय क्या शिकायत है ?

श्री कृष्णानन्दराय—

मैं यह कह रहा था कि आपने यह व्यवस्था दे रखी है कि वह सदन के प्रति अशिष्ट व्यवहार माना जायगा लेकिन प्रिविलेज का मोशन हम मूव नहीं कर सकते। इस व्यवस्था के बावजूद यह लोग उसी प्रकार का अशिष्ट व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिये ३० जून को बहराइच में जैसा माननीय प्रतापसिंह ने किया। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आप प्रिविलेज मोशन लाने नहीं देते हैं और यह लोग रोज आपकी व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, तो हम लोग क्या करें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मैं उसका आशय ठीक से समझ नहीं पाया लेकिन जितना समझा हूं उसके अनुसार उनकी शिकायत यह है कि मेरी एक व्यवस्था हुई थी कि मंत्रिमंडल के सदस्य सदन के बैठते हुये बाहर नीति संबंधी वक्तव्य नहीं देंगे। मैंने यह भी कहा था कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हो सकता। वह अशिष्ट व्यवहार है।

श्री कृष्णानन्द राय—

रोज हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से "रोज हो रहा है" कहना अत्यन्त अशोभनीय है। मैं बात कह रहा हूं, बीच में आपकी कमेंटरी चल रही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि कम से कम आप मुझे अवसर दें। अशिष्ट व्यवहार हुआ, उसके बारे में मैं तब कह सकता था जब उस स्टेटमेंट को जिस को वह कहते हैं कि मेरी इस व्यवस्था के बाद हुआ, उसको मेरे पास भेजने की कृपा करते। अब अगर भविष्य में कोई इस प्रकार का वक्तव्य हो जो नीति संबंधी हो, उसको कोई माननीय सदस्य मेरे पास भेजेंगे तो जो उचित बात होगी, मैं करूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

किस नियम के अन्तर्गत भेजें?

श्री अध्यक्ष—

जिस नियम के अन्तर्गत आपने खड़े होकर मुझ से पूछ लिया उसी में आप भेज सकते हैं। आपने एक हाइपाथेटिकल बात कह दी कि ऐसा रोज हो रहा है। उस पर मैं अपना मत कसे व्यक्त कर सकता हूं? पहले मैं देखूं कि वह अशिष्ट व्यवहार की परिधि में आता है अथवा नहीं। अगर आता है तो कम से कम मैं अपनी राय व्यक्त करूंगा लेकिन जब वह तथ्य मेरे सामने आयेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जरा आप बैठ जायं। एक प्रश्न और उठाया था, एक माननीय सदस्य ने कहा था कि माननीय कृष्णानन्द राय ने दो शब्द प्रयोग किये "उच्छृंखल" और "ओछा"। मैं इसके विषय में यह कहना चाहता हूं कि कोई शब्द अपन में असंसदीय नहीं होता है। उसका प्रसंग और प्रयोग उस को संसदीय या असंसदीय बनाता है। यह जो शब्द "ओछा" था, वह बहुत उचित नहीं था, चाहे संसदीय हो या असंसदीय, लेकिन वह अशोभनीय है। उसका प्रयोग नहीं होना चाहिये। लेकिन "उच्छृंखल" उतना असंसदीय नहीं दिखाई पड़ता।

श्री कृष्णानन्द राय—

आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। लेकिन कांग्रेस दल जो इस सदन का एक बहुत ही स्वस्थ और जिम्मेदार विरोधी दल है, उसके बारे में माननीय मंत्री ने जन सभाओं में "ओछा" शब्द का प्रयोग किया है।

श्री अध्यक्ष—

सदन के बाहर किसने क्या प्रयोग किया है उस पर मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन सदन के सामने ऐसा शब्द प्रयोग हो जो ठीक न हो तो, उसके बारे मे मैं जरूर मत व्यक्त कर सकता हूं।

श्री रमावल्लभ मिश्र (जिला बरेली)—

मान्यवर, कांग्रेस पक्ष के लोग क्या उसी प्रकार चिढ़ रहे हैं जैसे "काना" शब्द से काने को चिढ़ हुआ करती है?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि कल खाद्य मंत्री ने माननीय चन्द्रबली के भाषण क संबंध में उत्तर देते हुये कुछ पार्टियों की मान्यता के सिलसिले में जिक्र किया था। उसमें उनकी भी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी के बारे में भी जिक्र किया था और वह खाद्य समितियों के मामले में था। चन्द्रबली सिंह जी सोशलिस्ट पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं। तो पार्टियों के सिलसिल में मान्यता तो श्रीमन् आप देते हैं, यह आपके अधिकार की बात है। इसके पूर्व भी जहां तक मने देखने और समझने की कोशिश की, पूर्वगामी अध्यक्षों की व्यवस्था आप देखें तो आप यह पायेंगे कि जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न उठे·····

श्री अध्यक्ष—

आपकी कठिनाई क्या है, पहले उसको बतला दीजिये, और फिर अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश कीजिये ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

कल जब उनकी स्पीच हुई तो माननीय कृष्णानन्द राय ने यह भी पूछा था कि और पार्टियों को तो एलेक्शन कमीशन से मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन जन-कांग्रेस को तो वह भी नहीं, फिर भी उनकी पार्टी सब जगह मान्य बनी बैठी है। तो श्रीमन्, आप देख लें—सोलशिस्ट पार्टी को यदि मान्यता मिलती है तो उसके सदस्यों को भी खाद्य समितियों में जाने का अधिकार होगा, जिस प्रकार अन्य पार्टियों के सदस्यों को खाद्य समितियों में जाने का अधिकार है। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि उनकी पार्टी को भी खाद्य समिति में जाने का अधिकार हो जाय इससे यह भी बात पैदा होती है कि इस सदन में मान्यता की बात करने का अधिकार आपको है न कि किसी मंत्री को, इसलिये आप अपनी व्वयस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ जी ने जिस बात की ओर ध्यान दिलाया मैं उसके बारे में यही कहना चाहता हूं कि यदि मैं उनकी बात को मान लूं तो संस्दीय इतिहास में कुछ नये पन्ने जोड़ने पड़ेंगे। केवल किसी मंत्री के संसदीय भाषण पर व्यवस्थायें होने लगें तो व्यवस्थाओं का कहीं अन्त नहीं होगा। कल का प्रसंग बिलकुल दूसरा था और खाद्य मंत्री ने सदन के अन्दर एलेक्शन कमीशन से मान्यता और दूसरे बारे में कुछ इस प्रकार की बात की। मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी से यह चाहूंगा कि पहले वह उसको ठीक से पढ़ लेते और कोई विशिष्ट बात होती तो मुझे लिखकर सूचित कर देते तो अधिक अच्छा हुआ होता। यह ठीक ही उन्होंने कहा कि इस सदन में किसी पार्टी को मान्यता देना मेरा अधिकार है और मैं उसे भली प्रकार करूंगा। जन कांग्रेस का भी मामला मरे पास आया था, मैं उस पर भी नियमों के अनुसार विचार करूंगा।

(श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' के खड़े होने पर)

राकेश जी आपका क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

लगभग वैसा ही है।

श्री अध्यक्ष—

लगभग वैसा नहीं, अगर बिलकुल हो, तो कहिये।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

ऐसा ही समझ लीजिये। मंत्री लोग जो भाषण करते हैं उनके लिये विरोधी पार्टी के लोग ओछापन और उच्छृंखलता की बात करते हैं। तो क्या मंत्री लोग यह कहा करें कि कांग्रेस सरकार

ने २० साल में बड़ा अच्छा काम किया है और देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया है ? (व्यवधान) हम भी डकैतों को भड़काने वाले, चोरबाजारिये और लुटेरे कह सकते हैं। विशेषाधिकार के नाम पर अपने काले पापों को छिपाना कोई अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननी : अश्वनी कुमार जी से मैं ऐसी आशा करता था खड़े होने से पहले कि यदि व्यवस्था का प्रश्न हो तभी खड़े हों और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिलाया लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य अभी दिया है मैं उसे अनुचित समझता हूं और आगे के लिए कहना चाहता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न का दुरुपयोग करेंगे तो मुझे फिर व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और या तो व्यवस्था के प्रश्न को लिखित लेना पड़ेगा या फिर मैं उन्हें व्यवस्था के बीच में आमंत्रित ही नहीं करूंगा जो व्यवस्था के प्रश्न का इस तरह दुरुपयोग करेंगे।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मैंने व्यवस्था नहीं, लगभग व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न। इस सदन की व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि विभिन्न दलों के नाम इस सदन में जो स्वीकृत हुए हैं उनकी जानकारी सभी माननीय सदस्यों को हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माननीय सदन में आपने किन-किन दलों को मान्यता दी है।

श्री अध्यक्ष—

अभी तक जो एक सूचना इस कार्यालय से प्रसारित हुई है उसको माननीय सदस्य कृपा करके देख लें। अभी तक उसमें जो कुछ लिखा है उतनी मान्यता मानी जाय और उसके बाद जो मामले मेरे सामने हैं वह विचाराधीन हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सभी दलों को आपकी आज्ञा से कार्यालय के लिए स्थान मिला है तो मैं ऐसा मानूं कि मान्यता प्राप्त सभी दलों के पास अपने कार्यालय हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसमें भी मेरी कठिनाई है। संयुक्त विधायक दल को मुझे एक स्थान देना चाहिए था। उसके देने में मैं असमर्थ रहा बहुत दिनों तक और अब दे पाया हूं। जब मैंने उनको दे दिया तब व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या यह सही है कि मान्यवर ने एक ऐसे भी दल को आज्ञा दी है और क्या उस दल ने प्रार्थना की है कि जिसे इस भवन में मान्यता प्राप्त नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

यहां पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

व्यवस्था का प्रश्न है। ११ बजे सदन में आप पधारे और कार्यवाही आपने प्रारम्भ की। उस समय माननीय कृष्णानन्द राय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया जिसका संबंध इस सदन के

[श्री भगवती सिंह विशारद]

बाहर किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार से था। उसी समय कल्पनाथसिंह जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और फिर हेमवतीनन्दन बहुगुणा जी ने उठाया।

श्री अध्यक्ष—

आपने भी उठाया। यह सही है कि थोड़ी देर से उठाया ?

श्री भगवती सिंह विशारद—

मैं तो उसी समय उठाना चाहता था। तो मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई कार्यवाही चल रही हो उसके बीच में कोई व्यवधान की बात पैदा हुई हो उसी समय व्यवस्था का प्रश्न पैदा होता है। बाहर का प्रश्न लाकर आपके सामने प्रश्न आ जाता है और आपकी सहमति प्राप्त हो जाती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमको भी आप अधिकार प्रदान कर रहे हैं कि जब हम कोई प्रश्न प्रस्तुत करना चाहें तो व्यवस्था के नाम पर प्रस्तुत कर सकें ?

श्री अध्यक्ष—

विशारद जी ने जो प्रश्न उठाया है वह अपनी जगह पर महत्व रखता है। यह तो मैं पहले ही कह चुका कि व्यवस्था के नाम पर कोई और प्रश्न उठाना उस अधिकार का दुरुपयोग है। अब दूसरा प्रश्न आपका यह होता है कि वह किस समय उठाया जाता है उसके लिए कोई प्रतिबन्ध नियमों में ही नहीं है। आज प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में नहीं था और पहला आइटम जो आता है जिसको मुझ लेना है वह विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय से संबंधित है और माननीय कृष्णानन्द राय जी ने विशेषाधिकार के प्रश्न से संबंधित प्रश्न उठाकर ऐसी कोई बहुत गलत जगह प्रश्न नहीं उठाया था।

## श्री अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना के दो प्रस्ताव आये हैं, श्री हुकमसिंह परिहार द्वारा। एक तो माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के खिलाफ और दूसरा अध्यक्ष के खिलाफ। अध्यक्ष के खिलाफ जो प्रस्ताव है उस पर मैं चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा इसलिए कि अध्यक्ष के खिलाफ न किसी परंपरा के अनुसार इस विधान सभा में न और कहीं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रस्ताव आ सकता है। अध्यक्ष पद पर बैठने वाले व्यक्ति को अपना कर्त्तव्य निर्वहन करने में ऐसी बातों को करना पड़ता है जो कभी-कभी माननीय सदस्य को अच्छी नहीं लगती हों, लेकिन उस पर अगर माननीय सदस्यों को विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध लाने की अनुमति प्राप्त होती तो फिर वह सदन की गरिमा को बढ़ाता नहीं। इसलिए मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है।

इसके बाद दूसरा प्रश्न विशेषाधिकार की सूचना का माननीय मंत्री महोदय के विरुद्ध दिया है जिसमें वह कहते हैं कि मेरे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को आपने दिनांक १ अप्रैल, ६७ को मंत्री के वक्तव्य के लिए स्वीकार किया था। प्रस्ताव में २,००० वैक्सीनेटरों, जिनको उस समय की सरकार ने सेवा मुक्त कर दिया था, पुनः सेवा की मांग की गई थी और प्रदेश में फैली चेचक की महामारी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था। संबंधित मंत्री जी ने इस संबंध में आज तक कोई वक्तव्य नहीं दिया है। इस प्रकार उन्होंने सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है।

अब इसमें इसी विषय पर पहली अप्रैल को माननीय मुल्तान सिंह जी ने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था। उस पर मैंने यह आदेश दिया था कि इस विषय पर कई बार नियम ५१ को

सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री को आवश्यक ध्यान हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं। पुनः प्रेषित। यह मैंने लिखकर भेज दिया था। इनको वक्तव्य के लिए स्वीकार नहीं किया गया था। मंत्री जी के पास मैंने केवल कार्यवाही के लिए भेजा। माननीय सदस्य का कर्त्तव्य था कि वह संबंधित मंत्री से मिलते और जानते कि उस पर क्या आवश्यक कार्यवाही हुई है। इसके पश्चात् उनको यह अधिकार भी था कि वह सदन में प्रश्न कर सकते थे। यदि मैंने वक्तव्य के लिए भी दिया और उस पर मंत्री जी देर से अपना वक्तव्य देते, तब भी यह विशेषाधिकार की अवहेलना का विषय नहीं बनता।

## १९६७-६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रताप सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के अन्तर्गत होनेवाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,१२,०८,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मैं आपकी आज्ञा से राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,९४,१४,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने भाषण को दो हिस्सों में बांटता हूं। इस समय एक संक्षिप्त भाषण दूंगा ताकि बाद में माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जो अपने अमूल्य सुझाव देंगे, उनसे लाभ उठा सकूं और बाद में उनका उत्तर देने का मुझको अधिक अवसर प्राप्त हो।

मान्यवर, जिस विभाग का मैंने आज अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि प्रदेश में यह एक ऐसा अकेला विभाग है जिसका प्रादुर्भाव ही सेवा करने के लिए हुआ है। मान्यवर, सेवा करना ही इस विभाग का पुनीत कर्त्तव्य है। यही हमारा उद्देश्य है। यही हमारी नीति है। स्वास्थ्य विभाग की नजर पिछले बीस सालों में बराबर ऊंचे लोगों की तरफ ही जाती रही है। हमने प्रयत्न किया है कि जो प्रदेश के धूल धूसरित लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं जिनकी चिकित्सा की ओर अभी तक ध्यान नहीं जा पाया है, उनकी ओर इस विभाग का ध्यान आये। हमने बन्थम के सिद्धांत—बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय—को इस विभाग के लिए स्वीकार किया है। दूसरे शब्दों में कहूं तो "मैक्सिमम फैसिलिटीज टू दि रूरल एण्ड पुअर पीपुल" हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लकर हम आगे बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, हमारे प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का १६·८१ प्रतिशत है। हमारे प्रदेश की जनसँख्या आज साढ़े आठ करोड़ के लगभग है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन कराना और उसके स्वस्थ्य जीवन की व्यवस्था करना एक कठिन काम है और माननीय सदस्य चाहे प्रतिपक्ष के हों अथवा सरकार के पक्ष के, सभी इस बात से सहमत होंगे कि साढ़े आठ करोड़ जनता के लिए १५ करोड़ का स्वास्थ्य और चिकित्सा का बजट बहुत कम है। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं। केंद्रीय सरकार के अन्तर्गत जो नियोजन विभाग बना है, जब उसने सारे प्रदेश का प्लान कट किया तो हमें भी अपने सीमित साधनों से ही अपने उद्देश्य की पुर्ति करनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

है। हम चाहते हैं कि हमें इस दिशा में अधिक से अधिक बल मिले और इस हेतु में अपने विभाग की नीति बतलाना चाहता हूं ।

मैंने देखा कि पिछले बीस सालों में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की साइड में अधिक ध्यान दिया गया है। देहातों में हमने चिकित्सा का प्रबन्ध किया है, वहां दवाइयों को भी हमने पहुंचाया है लेकिन हमें देहातों में कम खर्चीले मकानों की व्यवस्था करनी है। हमारी कोशिश ऐसी भी है कि गांवों के आदमी अपनी इमारतें हमें इस काम के लिए दे सकें ताकि इस मद में हम पैसा बचा कर उसे दवाइयों और चिकित्सा पर अधिक से अधिक लगा सकें और गांव वालों की इस प्रकार अधिक सेवा कर सकें। इसके अतिरिक्त, जैसा माननीय सदस्यों को पता है, यह सही है कि डाक्टरों की कमी है। हमारा फर्ज है कि हम इस कमी को जल्द से जल्द पूरा करें। इस ढाई महीने में इस कमी को दूर करने के लिए हमने एक पांच सूत्री कार्यक्रम बनाया है, जिसके अनुसार पहले हम जो मिलिटरी के रिटायर्ड डाक्टर्स हैं और जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हैं उन की एक लिस्ट हमारे पास आ गयी है। हमारी कोशिश है कि हम उनकी सेवायें लें। दूसरे कबाल टाउन्स में अस्पतालों में रिजर्व ड्यूटी में बहुत से डाक्टर्स रहते हैं। हमारी कोशिश है कि उनको वापस बुला कर उनको जिला अस्पतालों में भेजा जाय और जब तक डाक्टरों की बहुत कमी है तब तक के लिए प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की भी सेवायें हम इस काम के लिए लेना चाहते हैं। तीसरे एक जोशी कमेटी रिपोर्ट है। उसकी सिफारिश है कि जो मिक्स्ड कोर्स के डाक्टर्स हैं उनको बी क्लास डिस्पेंसरीज में लगाया जा सकता है। इस को भी हम करने जा रहे हैं। चौथे, मलेरिया विभाग में हमारे डाक्टरों और अधिकारियों ने बड़ा अच्छा काम किया है। उसमें बहुत से डाक्टर काम में लगे हुए हैं और मैंने अपने विभाग के एक्सपर्ट्स की राय मांगी है और उस के अनुसार डाक्टरों के अलावा टेक्निकल आदमी भी वह काम कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि उन डाक्टरों को ले कर हम दूसरी डिस्पेंसरीज में भेजें जहां डाक्टरों की कमी है। पांचवां जो कार्यक्रम है मैंने कोशिश की कि कौनसा प्रदेश ऐसा है जहां डाक्टर्स बहुतायत में हैं। तो मद्रास में जहां हमारी एक बहन डायरेक्टर है उनके सामने मैंने अपनी दिक्कत रखी जब मैं इस पद पर आया। ३०० डाक्टर्स उनके यहां सरप्लस में हैं। तो मैंने मौखिक रूप से उनसे कहा था और उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमने लिख दिया है और हमें उम्मीद है कि १०० डाक्टर्स हमको मद्रास से मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमारे जो मेडिकल कालिज हैं उनमें हम छात्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले जमाने में अधिक से अधिक डाक्टर्स तैयार कर सकें।

एक शिकायत यह भी है कि देहातों में डाक्टर्स नहीं जाते हैं। जब वह लखनऊ और इलाहाबाद की ग्लेयर में रहेंगे तो धारचूला, आजमगढ़, बलिया और देवरिया आदि सुदूरवर्ती स्थानों में कौन जाना पसन्द करेगा ? तो हमने केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री से बात-चीत की थी। मैंने कहा कि मैं दो रूरल मेडिकल कालिज खोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कोई योजना इस प्रकार की आयेगी तो हम मदद करेंगे। एक तो पर्वतीय क्षेत्र में और एक पूर्वी क्षेत्र में मैं चाहता हूं ताकि देहात वालों के लिए प्राथमिकता दी जा सके देहाती वातावरण में कालिज का स्टाफ रहे और इस प्रकार देहात और शहर के रहन-सहन में जो फर्क है और जिस कमी के लोग शिकार हैं वह हम दूर कर सकें। यह विभाग की ऐसी नीति है जिसको सभी सदस्य मानेंगे।

उसके अलावा हमने इस साल यह सोचा है कि गरीब छात्र जो मेडिकल कालेज में आते हैं, उनका खर्चा नहीं चल सकता तो उनको छात्र-वृत्ति अधिक से अधक देने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों उनसे केवल यही आश्वासन लिया जाता था कि देहात में जाकर काम करेंगे लेकिन जब वह देहात में नहीं जाते थे तो किसी कानून के अन्तर्गत ऐक्शन नहीं ले सकते थे। अब एक स्टाम्प पेपर पर बाण्ड भरवायेंगे जिसके अनुसार वह ३ साल तक देहात में काम करेंगे और जो

भी खर्चा सरकारी उन पर हुआ हो वह देना पड़ेगा, अगर नहीं जायेंगे। इस तरह से देहातों में डाक्टरों की कमी पूरी हो जायगी।

आज सबसे बड़ा सवाल, जिसको मैं डेंजर जोन कहता हूं, वह हमारी बढ़ती हुई आबादी है। सदस्यों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि एक घण्टे में ४०० बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक घण्टे में अन्दर एक गांव पैदा हो रहा है, एक दिन के अन्दर एक पंचायत पैदा हो रह है और एक सप्ताह के अन्दर एक विकास क्षेत्र तथा ५ महीने के भीतर एक सारा जिला पैदा हो रहा है, यानी एक जिले की आबादी हो जायगी, उस समय १४,४०,००० आबादी ५ महीने में पैदा हो जायगी। क्या यह खतरनाक बात नहीं है?

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

इसे रोक दो, रोक दो।

श्री प्रतापसिंह—

मैं माननीय राममूर्ति का आभारी हूं जो कह रहे हैं कि "रोक दो"। यह तो सेवा का विभाग है और हम सभी को संकल्प लेना चाहिए और मुझे आशा है कि अध्यक्ष जी इसमें साथ देंगे कि हम संकल्प करें कि हम आज के बाद से ज्यादा बच्चे पैदा करने का प्रयास नहीं करेंगे और इसमें मदद करेंगे जिसमें आबादी रुक सके। मुझे खुशी है कि ५० फीसदी लोग तो अभी आश्वासन देने लग गये हैं।

इसके बाद मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सौ प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वीकृति दे दी है। ५०० केंद्र हो जायेंगे। ग्रामीण केंद्रों की संख्या ८७१ है, उनमें ४०० की वृद्धि और की जायगी ताकि परिवार नियोजन की हर गांव में व्यवस्था हो सके। सारे क्षेत्र में तो आवश्यकता इस समय १९० केंद्रों की है, लेकिन ७२ केंद्र ही इस समय खुल सकेंगे।

यह जो परिवार नियोजन विभाग है इसके द्वारा पिछली सरकार के जमाने में उतना काम नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। हमने इसको फिर से रिआर्गेनाइज किया है। हमने कोशिश की है कि हमारा खर्च कम हो, और प्रसार अधिक हो। हाल ही में सूचना विभाग द्वारा इसके प्रसार के लिए एक ऐसी फिल्म तैयार की गयी है, मैंने खुद उसको देखा है, उसको देख कर बड़ी खुशी होती है, जिसको देखने के बाद एक अनपढ़ व्यक्ति भी यह महसूस करने लगता है और उस को यह विश्वास हो जाता है कि परिवार नियोजन परिवार को सुखी बनाने वाली एक योजना है। पहले लोग समझते थे कि यह सरकार की नीति है, लेकिन आज वे समझते हैं कि वास्तव में वह परिवार को सुखी बनाने वाली चीज है।

इसके लिए हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक जिले में एक नसबन्दी ब्यूरो की स्थापना हो। ५१ जिलों में यह कार्य हो चुका है। चमोली, उत्तरकाशी, और पिथौरागढ़ आदि जिले रह गये हैं, वहां भी इसी वित्तीय वर्ष में इसकी स्थापना हो जायगी। इनकी स्थापना से जनता को यह मालूम हो सकेगा कि परिवार नियोजन की क्या महत्ता है।

हमारे यहां नर्सेज की भी बहुत कमी है। मद्रास से हमारी बहनें आकर हमारी सेवा कर रही हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस कमी को पूरा करने के लिए हम २१ आक्जीलरी नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं। उसमें हम आपकी मदद चाहते हैं। गांव की बहनें उसमें ट्रेनिंग लेकर हमारे राज्य में काम कर सकेंगी। रीजनल बेसिस पर भी दो ऐसे इन्सीट्यूशन्स बनाये जायेंगे जिनमें उसी रीजन की लड़कियां वहां ट्रेनिंग लेकर वहीं सेवा कर सकेंगी। इसके अलावा ४ जनरल नर्सेज ट्रेनिंग सेंटर्स, ३ मिड वाइव्ज सेंटर्स भी खोले जायेंगे।

[श्री प्रतापसिंह]

यह भी मांग होती रही है कि कानपुर तथा इलाहबाद आदि में डिग्री कोर्स इनफार्मेसी होना चाहिए। सरकार इस पर विचार कर रही है कि कानपुर में डिग्री कोर्स इनफार्मेसी तथा इलाहाबाद और मेरठ में डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, आपके आशीर्वाद से और माननीय सदस्यों के सहयोग से जब से यह विभाग मुझे मिला, मैंने इस बात पर विचार किया कि हमारे प्रदेश में जो भी भिन्न भिन्न चिकित्सा की पद्धतियां हैं उनको प्रोत्साहन मिलता चाहिए। जो भी पद्धति अच्छा काम करेगी, जनता उस तरफ जायेगी, उसी को अपनायेगी। किसी एक पद्धति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने सोचा है कि आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और यूनानी चार सिस्टम्स को प्रोत्साहन दिया जायगा। इसके लिए हमारी योजना है कि हम होम्योपैथिक अस्पताल भी खोल रहे हैं, आयुर्वेदिक भी खोल रहे हैं तथा और दूसरी पद्धति वाले भी खोल रहे हैं। लेकिन अर्थ-व्यवस्था की जो हमारे प्रदेश में दिक्कत है वह आपको विदित है, हम चाहते हैं कि हमारी चिकित्सा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि कम पैसा लगे और अधिक लोगों का इलाज हो। मान्यवर भी कई आयुर्वेदिक कालिज चला रहे हैं, इसके लिए मैं मान्यवर को धन्यवाद देता हूं। नेशनल होम्योपैथिक कालिज के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि इसको हम अपने हाथ में लेंगे।

आयुर्वेदिक चिकित्सा में विश्वास रखने वाले लोगों और उनके डाक्टरों की सेवाओं को देखते हुए हमने यह भी निश्चय किया है कि इन डाक्टरों को जितना वेतन मिलता था वह कम है। स्टेट आयुर्वेदिक सर्विसेज जो हमने बनायी है उनका ग्रेड २५० से ७५० रुपये तक का रखा है। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे। मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि इन तीन महीनों के भीतर जब से हमने यह कार्यभार सम्भाला है, हमने क्या कार्य किया है, हमारी सरकार की जो नीति थी क्या वह इन तीनों महीनों के अन्दर कागजों पर ही रही या उसका प्रतिपादन हुआ, इसके बारे में आप देखेंगे कि पुरानी सरकार के जमाने में जो अस्पताल दस बजे खुला करते थे अब वे सात बजे खुलते हैं। इसके अलावा सारे प्रदेश में ऐसे अस्पताल हैं, और इसी लखनऊ में भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं जहां अस्पतालों में बीस वर्ष तक प्राइवेट क्लिनिक चलते थे वहां अब सरकार में आने पर ही वे क्लिनिक गायब हो गये हैं। एक बहुत बड़ी जगह है जहां क्लिनिक चल रहा है, डाक्टर साहब वहां अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें बड़े आदमियों का सहारा है तो वे क्लिनिक चलेंगे ही परन्तु जब आपने छोटे आदमियों को मिनिस्टर बना दिया तो वे क्लिनिक गायब होंगे ही। उनकी दवाईयां बाजार में बिकती रही हैं। हमने सी० आई० डी० से सम्पर्क स्थापित किया और आपको खुशी होगी कि जिन अस्पतालों में पहिले दवाइयां बिकती थीं उनको उन्होंने घेर लिया है। जिन स्टाल्स में वे दवाइयां आती थीं अब उनमें नहीं आ रही हैं। मान्यवर, बांदा का कांड आपको याद होगा। इस प्रदेश में और भी कई इस प्रकार के बांदा होंगे। वहां तो ऐसी दवाइयां निकलीं जो आउट आफ डेट थीं और जिनको छिपाकर रक्खा गया था, ऐसी दवाइयां निकाली गईं। कम से कम उधर के बहुत से लोगों की ओर से इस सरकार को बधाई मिलनी चाहिये थी परन्तु हमें दुखः हुआ जबकि वहां के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि इट इज ए फुलिश ऐक्ट और यह कहा कि हमने बेवकूफी का काम किया है। मैं तो यह कहता हूं कि अगर हमारे बेवकूफी के काम से जनता को फायदा होता है तो वह काम करना चाहिये।

(माननीय कृष्णानन्द राय के खड़े होने पर)

श्री प्रतापसिंह—

आप बैठिये

श्री कृष्णा नन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जिस प्रकार इन्होंने व्यवहार किया है हमको नहीं करना चाहिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृष्णानन्द राय जी से जो बात माननीय मंत्री जी ने कही अगर कोई काम माननीय सदस्य गलत करते हैं तो दूसरें माननीय सदस्य उस काम को जिसको वे गलत समझते हैं स्वयं न करें। माननीय मंत्री महोदय ने जो संबोधित किया है वह गलत है, वह मुझे कहना चाहिये था, उनको नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसे अनुचित कह दिया।

(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये थी। लेकिन मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि सदन की कुछ परम्परा है और जिस लेविल से माननीय सदस्य बात करना चाहते हैं उस लेविल से मैं बात नहीं करना चाहता। मैं यह चाहूंगा कि जितनी देर मैं बोलूं, आप मुझे सुनें और मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं आपके सुझावों को आमंत्रित करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने छिपी हुई दवाइयों की तलाश की। हमारे एक वरिष्ठ सदस्य की तरफ से कहा गया कि मैंने बांदा में यह कह दिया कि कांग्रेस ने इस देश को भुखमरा बना दिया। यह बात सही है कि मैंने यह जरूर कहा था कि कांग्रेस के प्रशासन ने इस देश का नंगा बना दिया। आज हमारे पास ५५४ से ज्यादा डाक्टरों की कमी है। ढाई महीने में हम जा तो नहीं कर सकते लेकिन यह बात सही है कि जिनके हाथ में २० साल तक सत्ता रही है उन्होंने देहात की जनता की उपेक्षा की और बड़े आदमियों की तरफ ही देखा।

उधर के बैठे हुये माननीय सदस्य जहां इस कोशिश में हैं कि कुछ चन्दा इकट्ठा हो जाय किसी भले काम के लिये, तो मैं चाहता हूं कि वे हमारा साथ दें ताकि चन्दा इकट्ठा करके हम टी० बी० क्लीनिक खोल सकें और कानपुर की मजदूर गलियों में अस्पताल खोल सकें।

जिन डाक्टरों के ऊपर बड़े बड़े आदमियों का साया रहता था, डाक्टर का कसूर नहीं था, डाक्टर से कहा जाता था कि तुमको जन्म भर यहीं रहना होगा, हमने इस संबंध में कुछ नियम बनाये। यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा रहें, लेकिन नियम रहेंगे जब तक उनमें संशोधन नहीं किया जायगा। हमने हर डाक्टर के लिये १ साल के लिये पहाड़ पर जाने का नियम बनाया है। जब तक हम प्राइवेट प्रैक्टिस को बिलकुल समाप्त नहीं कर देते हैं, तब तक अगर पहला एप्वाइन्टमेंट नान प्रैक्टिसिंग में होगा तो दूसरा प्रैक्टिसिंग में होगा। जेल, पी० ए० सी० और पुलिस फोर्स में तबादले होते रहेंगे और जिनको ५ साल से ज्यादा किसी अस्पताल में हो गये उनको हमने बदल दिया। हमें खुशी है कि जिस डाक्टर को जहां भेजा गया वहां वह गया। १० साल और उससे अधिक के अनुभव के डाक्टर जिला हेडक्वार्टर पर और ५ साल के अनुभव के तहसील हेडक्वार्टर पर रहेंगे। जिन डाक्टरों की किसी जमाने में उपेक्षा होती थी वे आज खुश हैं और मिशनरी जील से काम कर रहे हैं।

महिला डाक्टरों के लिये हमने नियम बनाये हैं कि अगर एक अस्पताल में उनको ५ साल से ज्यादा हो गये हैं तो दूसरे अस्पताल में उसी शहर में उनको भेजा जायगा जब तक बाहर जिले में जाने के लिये स्वयं न कहें। जो महिला डाक्टर स्वयं अपने वर्तमान स्थान से दूर जाना चाहेंगी उनके कैरेक्टर रोल में स्पेशल एंटी की जावेगी जो भविष्य में उनके प्रोमोशन में गिनी

[श्री प्रतापसिंह]

जायगी। इसी तरह से हम इस कार्य को, चिकित्सा के कार्य का, वार फुटिंग पर लाकर जनता को लाभ देना चाहते हैं। केवल मैटीरियलिस्टिक गेन ही बड़ी चीज नहीं है। डाक्टरी पेशे का प्रादुर्भाव सेवा के लिये हुआ है।

देहातों के लिये इलाज की व्यवस्था में हम सुधार करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग डिसपैंसरी और मोबाईल डिसपैंसरी में लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज करते हैं। मोबाईल डिसपैंसरी वहीं चल सकती हैं जहां सड़कें हैं। लेकिन ट्रैवलिंग डिसपैंसरी जहां यातायात के साधन नहीं हैं वहां हम रखेंगे और वहां से वे लोगों को साधारण चिकित्सा करने के बाद सीरियस केसेज का तहसील और जिला हेडक्वार्टर्स पर पहुंचा सकेंगे।

एक बात और जिसे सुनकर माननीय सदस्यों को प्रसन्नता होगी। पहली बार जिले के सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि वे हफ्ते में एक दिन जाकर देहात में जनता के मुफ्त इलाज की व्यवस्था करें और उनको सलाह दें। इस तरह से एक जिले के अधिकारी दो दिन देहात में जा सकेंगे। इससे एक तो चिकित्सा का प्रबन्ध होगा और दूसरे डाक्टरों और देहाती क्षेत्रों में मिशनरी जील पैदा होगा कि कोई हमको देखने आता है। यह व्यवस्था पहली बार की गई है।

मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का और माननीय हेमवतीनन्दन बहुगुणा जी के जिन्होंने कट मोशन रखा है, और सबके सुझावों का इन्तजार करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो सुझाव आयेंगे उन पर हम गौर करेंगे और हमारे डाक्टर लोग उनको कार्यान्वित करेंगे। जो अब तक उपेक्षित रहे हैं हमें उनकी सुव्यवस्थित चिकित्सा करनी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम आपका सहयोग चाहते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर वह नहीं देना चाहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। २६ मई के लखनऊ के सभी समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि लखनऊ के एक सिविल अस्पताल से महिला कर्मचारियों के पीटे जाने की जितनी भी ऐवीडेन्सेज हैं, जैसे पेशेंट चार्ट, एक्सरे प्रिन्ट, उन्हें गायब किया गया और उसमें माननीय मंत्री जी का हाथ था? क्या इसकी निष्पक्ष जांच मंत्री जी करा देंगे?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री अगर कुछ कहना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।† कमी करने का उद्देश्य—

(१) चिकित्सा प्रणाली को सस्ता तथा जन साधारण को सुलभ करना।

(२) होम्योपैथिक, यूनानी तथा आयुर्वेदिक शिक्षाओं को सुलभ तथा एलोपैथिक के समकक्ष बनाने हेतु डाक्टरों के वेतन-क्रमों में सुधार करना।

(३) देहाती क्षेत्रों में डाक्टरों की नियुक्तियां करना तथा मेडिकल कालेजों से निकले हुए छात्र तथा छात्राओं के लिये एक समय नियत करना जिससे देहातों में रह कर उपचार कर सकें।

---

†अन्य कटौती के प्रस्ताव के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे ९०१–९०२ पृष्ठ पर।

(४) सरकारी अस्पतालों के डाक्टरो को प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर सुविधायें प्रदान करना जिससे हर समय वे जनता के लिये अस्पतालों में सुलभ हो सकें।

(५) देहाती क्षेत्रों के अस्पतालों में अनुदान में बढ़ोत्तरी कर दवा को ग्राम जनता हेतु सुलभ कराना ।

महोदय, अभी मैंने बड़े ध्यान से माननीय मंत्री जी का भाषण सुना । वह नवयुवक हैं, बड़े हंसमुख हैं और मैं आशा करता हूं कि इस विभाग में उनको काम करने का अवसर मिला है तो अपनी शक्ति का वह अच्छे कामों में सदुपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस ढाई महीने के अल्पकाल में उन्होंने बहुत सी बातें कीं। उन्होंने कहा कि बांदा में अस्पताल में उन्होंने एक बहुत बड़ा तीर मारा कि दवाइयों का बहुत सा डैड स्टाक उन्होंने पकड़ा। इसके बारे में उन्होंने बड़े जोर से कहा। और दूसरी बात मैंने वह देखी कि उन्होंने बहुतायत से डाक्टरों के तबादले किये हैं। मैं नहीं समझता कि डाक्टरों के तबादले करना भी कोई उचित बात है। दरोगा और डिप्टी कलेक्टरों के तबादले नियत समय पर हों, यह बात तो समझ में आती है लेकिन डाक्टरों के तबादले की बात अच्छी है, यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि डाक्टर जहां पर काम करते हैं वहां पर अपना एक विश्वास पैदा कर लेते हैं। मरीज भी उससे परिचित हो जाते हैं और वह भी मरीजों से परिचित हो जाता है। एक बात यह कि विश्वास दवा से अधिक काम करता है। इस लिये पूरे प्रदेश में डाक्टरों को इधर-उधर करना योग्य डाक्टरों का अनाप शनाप की गई तबादला कर देना ठीक नहीं है, यह कोई अकलमन्दी का काम नहीं है।

श्रीमन्, अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने विस्तार से इस बात को कहा कि वे इस प्रदेश में डाक्टर की कमी को दूर करना चाहते हैं। डाक्टरों की कमी का हाल यह है कि आज भी देहात के अस्पतालों में ५-५, ६-६ सालों से कोई डाक्टर नहीं है। यह बड़ी ज्वलन्त समस्या है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसके उपाय भी बताये। उन्होंने कहा कि रिजर्व ड्यूटी में से और मलेरिया के डाक्टरों से काम लिया जायगा।

**श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)—**

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष—**

(अनेक सदस्यों के बोलने पर)—मैं इधर के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, कि जैसा मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहा, कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी माननीय सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने से रोके।

**श्री चेतराम पचपेड़ा—**

मैं आपकी आज्ञा से यह व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि "अनाप-शनाप जगह डाक्टर भेजे जाते हैं," इसका वे स्पष्टीकरण कर दें कि इससे उनका क्या मतलब है?

**श्री अध्यक्ष—**

"अनाप-शनाप" शब्द पूर्णतया संसदीय है, इस पर कोई आपत्ति नहीं उठायी जा सकती।

**श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—**

उससे मेरा तात्पर्य यह था कि डाक्टरों की क्षमता के अनुसार उनको ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिये जिससे वह जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। डाक्टरों की कमी को दूर करने का एक उपाय मंत्री जी ने यह भी बताया कि वे दूसरे राज्यों से डाक्टरों को मंगा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने इसी सदन में कहा कि मद्रास और मैसूर से डाक्टर आ तो रहे हैं

[श्री रघुवेन्द्र प्रताप सिंह]

लेकिन अभी उनकी शर्तें तय नहीं हुई हैं। उससे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा रिआयतें देकर डाक्टरों को बाहर से मंगाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में इतने मेडीकल कालेज हैं उनसे जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं, वे कहां चले जाते हैं। उनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता। मेरे जिले में एक लड़के ने एम० बी० बी० एस० की और उसके बाद शिशु चिकित्सा में विशेष योग्यता प्राप्त की। मैं समझता था वह कहीं प्रदेश में होगा लेकिन जब पिछले दिनों वह मुझे मिला तो मालूम हुआ कि वह जयपुर में है। इस तरह से अपने यहां के डाक्टर बाहर क्यों चले जाते हैं, इसको सरकार इलाज क्यों नहीं सोचती है ? और वे तभी यहां रह सकते हैं जब एक आकर्षक सेवा की शर्तें उनको यहां मिलेंगी और वे समझ सकें कि हम सरकारी सेवा में रह कर अच्छे ढंग के काम कर सकते हैं। जब तक कि इसका कोई उपचार न होगा तब तक कभी भी यहां के डाक्टर यहां रहना पसन्द नहीं करेंगे और यही कारण है कि आज देहातों में डाक्टर जाना नहीं चाहते। आप देखें कि आज देहात में डाक्टरों की क्या दुर्दशा है, कोई प्रबन्ध नहीं है कि वह एक सुरक्षित अवस्था में वहां काम कर सकें। आप के प्राइमरी हेल्थ सेन्टर कायम हैं, उनका डाक्टर जो अपने विषय का योग्य व्यक्ति होता है वह बी० डी० ओ० के अन्दर में रहता है, अगर वह कोई प्रस्ताव भेजेगा तो वह बी० डी० ओ० के माध्यम से भेजेगा। आप समझें कि डाक्टर के सामने बी० डी० ओ० की क्या हैसियत है, इससे वह अपने को अपमानित फील करते हैं। अगर कोई प्रभावशाली आदमी किसी सिम्पल इन्जरी को सीरियस लिखवाना चाहे तो डाक्टर की पोजीशन वहां पर बड़ी कठिन हो जाती है और उसे डर होता है कि अगर ऐसा न करेगा तो पिटवा दिया जायगा। इस तरह से उनके स्टेटस को उठाने का और उनकी सुरक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध अभी तक नहीं किया गया है ताकि वह अपने को बी० डी० ओ० के मातहत न समझें। आप ऐसी सुविधायें उनको यहीं दें ताकि वे बाहर जाने की बात न सोचें और बाहर न जायं। बाहर के लोगों का यहां बुलाना कोई समस्या का उचित समाधान नहीं है बल्कि वह तो केवल अपने मन को झुठलाना मात्र है। इस तरह के प्रयास सफल नहीं हो सकते। रिजर्व ड्यूटी वाले, मलेरिया वाले या मिलिटरी वालों को लेकर सूबे की जरूरत को आप पूरा नहीं कर सकते जब तक कि ऐसा प्रयास न हो कि उन की दशा सुधरे और डाक्टर स्वयं ही देहात में जाने में अपना हित और सौभाग्य समझें। मैं समझता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे कि ऐसे लोगों को बुलाकर रखना जो इस प्रदेश के लोगों की भाषा भी नहीं समझते और देहात का मरीज क्या कह रहा है, इतना भी जब नहीं समझेंगे कि क्या उसका कष्ट है तो फिर वह क्या उसका इलाज कर सकेंगे।

दवाओं के बारे में भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह बड़े जोर से रोकथाम कर रहे हैं कि दवाओं का गलत इस्तेमाल न हो और उनका बाहर जाकर बिकना रुके। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि आज चरित्र का इतना अधिक पतन हो गया है कि जो दवायें बाजार में बिकती हैं उनमें अजीब बेईमानी होती है। सुई से दवा निकाल कर उसमें फिर पानी भर दिया जाता है और मरीज बेचारे पानी ही खरीद कर ले जाते हैं। अगर आप कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं तो मंत्री जी ने जैसी यह लाल टोपी अपने सिर पर लगा रखी है वह दवा की शीशी पर भी लाल टोपी लगवा दें ताकि शीशी में पानी न भरा जा सके। हिन्मत कर के राज्य सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि दवाओं के पूरे उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी सरकार पूरी अपने हाथ में ले ताकि दवाओं में मिलावट न की जा सके।

अभी कहा गया कि देहातों की अधिक सेवा करने की कोशिश की जायगी। देहातों में ऐसी बुरी अवस्था है कि वहां के आदमी आज बिना इलाज के मर जाते हैं, उनको ठीक इलाज नहीं मिलता। देहातों के अस्पतालों में एक आम धारणा है कि दवाओं में रंग और पानी मिला कर दे दिया जाता है, कोई उचित सलाह भी उन्हें नहीं मिलती। जिला हेडक्वार्टर्स पर जो अस्पताल है वहां भी निदान के उपकरण नहीं है और कहीं हैं भी तो वे ठीक हालत में नहीं है। मैं अपने जिले की बात जानता हूं कि किस तरह से गलत जांच होती है और मरीजों को धोखा

दिया जाता है, वहां अभी एक हादसा हुआ कि एक नौजवान लड़का जिसकी शादी को थोड़े ही दिन हुये थे फालिज से पीड़ित हुआ और रायबरेली के अस्पताल में आया, वहां वह ४-५ दिन पड़ा रहा और कोई डाक्टर समझ ही नहीं पाया कि क्या बात है। सिविल सर्जन से मैंने बात की और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि बिल्कुल ठीक है, ठीक हो रहा है और आशा है ठीक हो जायगा। तब मैंने एक दूसरे डाक्टर से पूछा तो उसने बताया कि इस मरीज को तुरन्त लखनऊ ले जाओ। कहने का मतलब यह है कि ये रोग का निदान भी नहीं कर सकें। तब मैं उस लड़के को लखनऊ लाया और मेडिकल कालेज में दिखाया। यहां पर भी दिन भर निदान होता रहा और शाम के समय वह लड़का मर गया। इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन वहां के सिविल सर्जन यही कहते रहे कि ठीक हो जायगा। हमारे जिले के मुख्यालयों में जो अस्पताल हैं, उनमें न किसी रोग के विशेषज्ञ हैं जैसे आंखों के विशेषज्ञ, दांतों के विशेषज्ञ और न अच्छे उपकरण हैं, जिनसे अच्छी प्रकार से जांच हो सकें और रोग का निदान हो सके। आज यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस ओर किसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा। आज हमारे देहात के लोगों को लखनऊ भागना पड़ता है। जिस दिक्कत और परेशानी को उन्हें उठाना पड़ता है, उसका अनुमान हमारे सदन के हर सदस्य को हो सकता है। आवश्यकता तो इस समय इसकी थी कि चिकित्सा सुलभ बनायी जाय और उसको सस्ता किया जाय जिससे मरीजों को अपना स्वास्थ्य सुधारने का मौका मिल सके परन्तु यह नहीं हो रहा है।

अब मैं अधिक समय सदन का न लेकर परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। वह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वहां पर विवरण रखें, उनसे मालूम पड़ा है कितने भयानक रूप से हमारे प्रदेश की आबादी बढ़ रही है लेकिन आज परिवार नियोजन का जो तमाशा हो रहा है, उसके जरिये इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया जा सकता है। आज ऐसे लोगों की नसबन्दी हो रही है, जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ तादाद बढ़ाने और १० रुपये के लालच से किया जाता है।

आज लूप की भी बड़ी चर्चा है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कितने लूप किन किन को लगे? सिर्फ आकड़े दिखा दिये जाते हैं। मान्यवर, इसके लिये एक गोली निकली है जिसके नित्य प्रति प्रयोग से परिवार नियोजन हो सकता है लेकिन वह इतनी मंहगी है कि गरीब आदमी उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि यह सरकार उस गोली को सस्ता करायें और जन सुलभ करें जिससे उनके माध्यम से परिवार नियोजन का प्रसार हो सके। मैं तो यह भी चाहूंगा कि इन गोलियों का उत्पादन भी सरकार की ओर से हो।

श्रीमन्, एक बात मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में इस सदन में पिछले दिनों काफी चर्चा हुयी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम को राज्य के अधीन लाना चाहते हैं ताकि उसमें ज्यादा सफाई और कार्य अच्छे ढंग से हो सके। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि जो मेडिकल कालेज नये खोले गये हैं वे सब सरकार के कार्य क्षेत्र में हैं, युनिवर्सिटी के नहीं। लखनऊ का मेडिकल कालेज एक बहुत पुरानी संस्था है। बहुत दिनों से उसका विकास हुआ है और स्वतंत्र रूप से हुआ है। तो जो एक पुरानी परम्परा बन गयी है, जो संस्था विकसित हो गयी है, उसको तोड़ कर सरकार के नियंत्रण में ले आना और वहां पर आई० ए० एस० अधिकारियों का आधिपत्य कर देना कौन सी अकलमन्दी का काम है। इससे तरह तरह की बाधा उत्पन्न हो जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें। जहां तक दवाइयों की चोरी आदि का मसला है वह अपनी पुलिस और इन्सपेक्टरों की मदद लेकर हल करें। लेकिन विस्तृत रूप से कोई ऐसी योजना बनायें जिससे दवाइयों में मिलावट बंद हो और ज्यादा से ज्यादा दवाइयां देहात के अस्पतालों में पहुंच सकें जिससे कि वास्तविक लाभ देहात की जनता उठा सके। केवल घोषणा से काम नहीं चल सकता, इसकी तरफ एक ठोस प्रयास की अपेक्षा आप से की जाती है। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

*श्री रमा वल्लभ मिश्र (जिला बरेली)—

मान्यवर, अभी स्वास्थ्य मंत्री ने इस पवित्र सदन से अनुदान मांगा है जिस पर विपक्ष के एक बन्धु ने कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह अधिक से अधिक अनुदान इस कार्य के लिये दें क्योंकि वही एक मात्र ऐसी चीज है जिसमें कवल देना ही देना है सरकार को लेना कुछ नहीं है और जिसके द्वारा हम मानव समाज की सेवा करते हैं, प्रदेश की सेवा करते हैं, अपनी सेवा करते और अपनी आने वाली सन्तानों के लिये स्वस्थ मार्ग खोल जाते हैं। परन्तु इसके साथ साथ में स्वास्थ्य मंत्री के सामने कुछ अपने प्रदेश के रहने वाले नागरिकों की करुण पुकार भी अवश्य रखूंगा। मान्यवर, आज हम कल्पना करें कि २० वर्ष हो गये हमारे देश को स्वतंत्र हुये, इस प्रदेश में एक दल की सरकार चलते हुए परन्तु आज भी हमारे देश में चेचक निकलती है। हजारों बालक प्रतिवर्ष चेचक के द्वारा काल के गाल में चले जाते हैं, हजारों लड़कियां कुरूप हो जाती हैं जिनके विवाह की समस्या उत्पन्न हो जाती है और अपने माता पिता की छाती पर एक बोझ बन कर रह जाती हैं। बहुत से ऐसे बालक हैं जो दुनिया को बिना देखे ही शुरू से अंधे हो जाते हैं। २० वर्ष में हम अभी चेचक को रोक नहीं सके हैं।

एक सदस्य—

कहां नहीं निकलती है।

श्री रमा वल्लभ मिश्र—

जो सज्जन पूछ रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि सबसे अधिक चेचक का प्रकोप जर्मनी में हुआ करता था। सम्भवत उन्हें याद होगा अंग्रेजी के शृंगारप्रिय कवि ने लिखा है कोई भी महिला का सौन्दर्य चेचक के नकाब के बिना छिपा हुआ नहीं था। परन्तु जर्मनी के लोगों ने, वहां की सरकार ने इस बात पर दृढ़ संकल्प किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि २० वर्ष हो गये जर्मनी में एक भी केस चेचक का नहीं हुआ और यह सारा काम ४ वर्ष में उन्होंने समाप्त कर लिया था। लेकिन हमारे यहां चेचक निकलती है, हर साल प्रश्न होते हैं कि कितनी मौतें हुईं और हम चेचक रोक नहीं पाये। हमारा जीवन इस प्रकार का संघर्ष मय जीवन है, रोज चोट लगती है, रिक्शा चालक अस्पताल में चिकित्सा के लिये जाता है लेकिन वहां समुचित चिकित्सा उसको नहीं होती। टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगता है और १५ दिन बाद जब स्वर्ग जाता है तो घर वाले समझते हैं किसी भूत प्रेत का प्रकोप हो गया होगा। आज हजारों, लाखों शिशु इस देश से उठ जाते हैं टिटनेस हो करके। माता पिता कहते हैं कि मसान चढ़ा है और मर गया बालक। क्यों ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या करते रहे हम २० वर्ष तक इसके लिये। आज जनता की सरकार है उसके कान में यह पुकार अवश्य डालना चाहता हूं।

स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सक नहीं है। अरे, अस्पताल में जहां चिकित्सक हैं वहां की स्थिति तो सुनिये। मुझे अनुभव अंग्रेज की जेल का भी है, कांग्रेस की जेल का भी है, हम जेल में पीटे गये हैं, वार्डरों ने पीटा है परन्तु हमको हिकारत की निगाह से नहीं देखा। आज अस्पताल में जो गरीब ग्रामीण जाता है, उसके सामने से नर्स इठलाती हुई चली जाती है, वार्ड ब्वाय कहता है कि बैठता क्यों नहीं। जो जेल में अपमान नहीं होता वह अस्पताल में होता है। २० वर्ष तक व्यवहार करना न आया। डाक्टर ठीक समय पर नहीं पहुंचता और अगर पहुंच गया तो बेगार टाल दी और कह दिया कि चार नम्बर का मिक्श्चर दे दो और अस्पताल की दवायें चोरबाजारी में बिक रही हैं। इसका समुचित प्रबन्ध हमको करना होगा।

श्री अध्यक्ष—

आपको समय का खयाल रखना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री रमा वल्लभ मिश्र--

मुझे कुछ अधिक समय आप देने की कृपा कीजियेगा क्योंकि मैं इसमें विशेषज्ञ हूं।

श्री अध्यक्ष--

कल श्री हरीश कुमार गंगवार ने बतलाया था कि यहां सभी सदस्य विशेषज्ञ हैं।

श्री रमावल्लभ मिश्र--

विशिष्ट चिकित्सा का हाल यह है कि जिला अस्पतालों में उसका प्रबन्ध नहीं है। लेकिन अगर कहीं है भी तो दांत का डाक्टर जो है उसका कम्पाउन्डर कहता है कि इंजेक्शन लगवा कर दांत उखड़वाओगे या ऐसे ही। मरीज पूछता है कि दर्द होगा? वह जवाब देता है कि इंजेक्शन लगवा लो तो नहीं होगा। इंजेक्शन लगवाना हो तो घर पर आना। अगर घर पर जाने के लिये उसके पास पैसा नहीं है तो जम्बूरे से पकड़कर उसका दांत उखाड़ा जाता है और इंजेक्शन उसके दांत में नहीं लगाया जाता है। किसी के फ्रेक्चर हो गया हो तो हाथ लटकाये घूमता रहे, डाक्टर उसे देखना भी गवारा नहीं करता। एम० एल० ए० साहब से चिटठी लिखाई जाय तो वह देखें। ८, ८ रोज तक रोगी दौड़ते फिरते हैं। मैं आपके सामने वस्तुस्थिति रख रहा हूं। अगर एक्सरे कराना है तो पहले तो रोगी से कहा जायगा कि एक्सरे मशीन खराब है, अगर खराब नहीं है तो कहा जायगा फिल्म नहीं है और फिल्म बाजार से खरीद लाओ। अगर १० का नोट दे दिया गया तो एक्सरे मशीन भी ठीक हो जाती है, फिल्म भी आ जाती है। जर्मनी में जूते की दूकानों पर एक्सरे मशीन लगी रहती है कहीं जूता दबा तो नहीं रहा है। वहां अस्पतालों में एक्सरे मशीनें नहीं हैं। इसी तरह से देश में टी० बी० की विभीषिका बढ़ती चली जा रही है लेकिन उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हमारा जिला बरेली है। वहां पर इमारत तो बढ़िया बन गयी है लेकिन चिकित्सा की विशेषता यह है कि हम वह भी नहीं कर सके हैं जो यूनिसेफ की ओर से व्यवस्था है। यूनिसेफ से केवल एक शर्त लगा रखी है कि बंगलौर का जो ट्रेंड डाक्टर होगा उसे अस्पताल को रखना होगा, वह उस क्लिनिक का इंचार्ज बनाया जायगा। सहायता जो दी जाती है यूनिसेफ की तरफ से वह यह है कि एक्सरे मशीन मिलेगी, फिल्म्स मिलेंगी, जीप मिलेगी, सारी दवाइयां मिलेंगी, जांच करने के उपकरण माइक्रासकोप्स वगैरह मिलेंगे। रक्त व थूक की जांच करने के भी उपकरण मिलेंगे। दूसरी सभी सामग्रियां मिलेंगी। हेल्थ विजिटर्स मिलेंगी। परन्तु शर्त क्या है कि उसमें ट्रेन्ड आदमी इंचार्ज होना चाहिये। हमारे यहां सारी टीम ट्रेन्ड है। टी० बी० क्लिनिक भी है और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की जांच कमेटी जांच भी कर गयी। इसके बावजूद भी इन्चार्ज बना दिया गया है एक अन ट्रेन्ड आदमी, जबकि ट्रेन्ड आदमी बरेली में ही मौजूद है उसके सबार्डिनेशन में। यदि एक कलम से उसे बदल दिया जाय तो दो वर्ष तक यूनिसेफ सारा खर्च देगा और एक साल तक सारा खर्चा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट देगी और तीन, चार साल बाद प्रान्तीय सरकार पर उसका खर्च पड़ेगा। हम इन चीजों को कलम की एक नोक से ठीक कर सकते हैं।

अभी हमारे सामने परिवार नियोजन का जिक्र आया। ठीक है। परन्तु एक लाक में आज से करीब ६ महीने पहले की घटना है, एक महिला लगभग ६० वर्ष की है, उनके बाल सफेद हैं, वह वहां व्यवस्था को देखती हैं। एक दिन बस में मेरा उनका टकराव हुआ। मैंने प्रणाम किया और कहा कि माताजी, आप बताइये कि कैसी व्यवस्था चल रही है। उन्होंने तीन, चार आदमियों का नाम लिया कि अमुक अमुक पद पर नियुक्त हैं और इतना खर्च हो रहा है। मैंने पूछा कि कितना परिवार नियोजन कर पाये हैं। तो उन्होंने कहा कि ७ आपरेशन साढ़े तीन वर्ष में हुये। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह परिवार नियोजन चलता रहेगा तो हमारा सारा पैसा व्यर्थ चला जायगा। इतने पैसे से तो हम कोई और लाभ उठा लेते।

एक सदस्य--

अस्पताल का नाम क्या है?

श्री अध्यक्ष—

पूछ रहे हैं कि अस्पताल का नाम क्या है ।

श्री रमावल्लभ मिश्र—

डायरेक्ट बोल रहे हैं या आपके माध्यम से ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने अपना माध्यम तो इस्तेमाल कर ही दिया ।

श्री रमावल्लभ मिश्र—

मैं यह कहूंगा कि फतेहगंज ब्लाक ।

इतने दिन हो गये हमारे यहां एम० एस० और एम० डी० के क्लासेज नहीं खुल पाये । इजराइल इतना बड़ा युद्ध कर जाता है इतने थोड़े दिनों में, लोग स्पुतनिक छोड़ रहे हैं और हमारे यहां एम० एस० और एम० डी० की व्यवस्था भी नहीं हो पाती और कहा जाता है कि डाक्टर्स की कमी है और डाक्टर्स इम्पोर्ट किये जा रहे हैं मानो वह भी कोई माइलो और गेहूं जैसी चीज है । अब मदरास का डाक्टर आयेगा तो हम कल्पना करें कि हमारी एक बुढ़िया आयेगी और कहेगी कि बेटवा देखो हमरे पेटवा में कुन्न मुन्न होत हैं और डाक्टर अपनी बोली बोलेगा । तो अगर मरीज डाक्टर को और डाक्टर मरीज को अपनी बात ही समझा न सका तो क्या होगा । मुझे मालूम है कि प्रथम महायुद्ध में और द्वितीय महायुद्ध में अंग्रेजों ने फाइनल क्लासेज के लड़के जिन्होंने अपनी सर्विसेज आफर किया था उनको पास करके फौरन सेवा में ले लिया था । जो लड़के छोटे मोटे मार्क्स से रह गये हों उन सब को जो रूरल डिस्पेन्सरीज में जाने के लिये तैयार हों, इमर्जेन्सी के तौर पर एम० बी० बी० एस० की डिग्री दें और उनको भर्ती कर लें । जो लड़के आयुर्वेदिक और एम० बी ० बी० एस० पास हों उनको लें बजाय इसके कि वह डिस्पेन्सरीज खाली रहें और चमगादड़ वहां बीट करते रहें । इसके बजाय अगर एक कम पढ़ा लिखा डाक्टर वहां पहुंच जायगा तो कोई न कोई दवा तो देगा ।

इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि यहां के मेडिकल कालेज ऐसी हमारी शिक्षा संस्था को लेने की कोशिश की जा रही है, मैं इसका विरोध करता हूं । इसलिये कि उस संस्था के अन्दर हमारी व्यवस्था करने का काफी बड़ा हक है । यूनिवर्सिटी में, उसके अस्पताल में और वहां की मैनेजमेंट कमेटी में ९ आदमी सरकार के हैं १६ में और ७ यूनिवर्सिटी के हैं । यह बात हो सकती है कि जो नामिनेट किये गये हैं उनको आपके विचार के अनुसार चलना चहिये और ५ जो सरकारी नौकर हैं उनको आपके आदेश के अनुसार चलना पड़ेगा । आप ४ के लिये और नामिनेशन की व्यवस्था कर सकते हैं । परन्तु यदि उसे सरकारी चंगुल में ले लिया गया तो राकफेलर से मिलने वाला अनुदान उसे नहीं मिल पायेगा । डाक्टर्स को रोज तबादले के लिये डर लगा रहेगा और वे आई० ए० एस० के सामने अपनी दुम हिलाते रहेंगे । वैसी सूरत में आइ० ए० एस० आफिसर की सूचना उनके यहां पहुंचेगी कि अपने कालेज में मेरे साहबजादे का ऐडमिशन दो वरना आपको देवरिया भेज दिया जायगा । उसके बाद ही उनका साहबजादा पास हो जायगा, मेरे पास ऐसा उदाहरण है । मैं जानता हूं ऐसे केस को । एक विद्यार्थी को मैं जानता हूं जिसने सब चीज में थर्ड डिवीजन पाया लेकिन फारेंसिक में उसे फर्स्ट क्लास मिला क्योंकि सचिवालय के एक बहुत बड़े अधिकारी के यहां से डोर खींची गयी जिसका कि वह पुत्र है । मैं पूछता हूं फारेंसिक में ही फर्स्ट क्लास क्यों मिला, मेडिकल और सर्जरी में क्यों नहीं मिला ? बात यह है कि वह विद्यार्थी हर सबजेक्ट में डफर था । इसलिये मेरा निवेदन है कि मेडिकल कालेज को न लिया जाय ।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में डेंटल कालेज और खोले जांय । मैं चाहता हूं कि पटुआडांगर में अधिक मात्रा में ए० टी० एस० का निर्माण करें जिससे किसी गरीब रिक्शे वाले को भी साढ़े ३ रुपये वाला इंजेक्शन न खरीदना पड़े । मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जिला अस्प-

बाहर में एक व्यक्ति इस बात के लिये निश्चित किया जाय जो रोगियों को चिट दिया करे कि किसका क्या नम्बर है और किस टाइम पर उसे चिट दिया गया ताकि किसी रोगी को नम्बर से दवा न मिलने पर डाक्टर को पकड़ा जा सके कि फलां रोगी जो सवा ८ बजे आया उसे तो दवा नहीं मिली लेकिन एक साहब जो अभी साढ़े १२ बजे आये वे अपनी दवा लेकर बिना नम्बर ही चले गये ।

हमारे यहां यौन रोग और कुष्ट रोग के इलाज के लिये भी विशेष व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि हमारे प्रदेश के गरीब वर्ग में यह विभीषिका बहुत अधिक है । इसके अतिरिक्त एक बात मैं और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । औषधियों में जो चोरी होती है उसके रोकने की एक ही विधि हो सकती है कि सरकार जितनी भी औषधि खरीदे, उन पर औषधि निर्माण करने वाले अपनी मुहर तो लगावें ही उस पर दूसरी तरफ यू० पी० जी० भी लिख दें। जैसे सल्फाडाइजिन में एक तरफ कम्पनी का नाम शिवा लिखा रहता है, उसी तरह से यू० पी० जी० भी लिख दें । इससे यह फायदा होगा कि औषधि खरीदने वाला खरीदते समय ही यह जान जायगा कि हम चोरी की औषधि खरीद रहे हैं और वह इत्तला दे सकेगा कि फलां के यहां चोरी का माल है । इस तरह से उसकी चोरी पकड़ी जा सकेगी ।

अन्त में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर मेरी आलोचना में उनको कुछ कटु अलोचना लगी हो तो वे उसे यह समझ कर स्वीकार करेंगे कि मैंने फोड़े में चीरा लगा दिया है । श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश को २० वर्ष के कोढ़ के बाद एक कुशल चिकित्सक मिला है और हमें आशा है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस प्रदेश को काफी लाभ पहुंचा सकेंगे, इसलिये इस अनुदान को स्वीकार किया जाय।

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)**--

श्रीमन्, यदि इस माननीय सदन के सदस्यों को स्मरण हो तो यह जो वर्तमान बजट है इसकी एक विशेष खामी है । माननीय त्रिपाठी जी ने उसका जिक्र अपने बजट भाषण में किया और मैं बहुत संक्षेप में केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस बजट में विशेष बल इसी पर दिया गया है कि अन प्रोडक्टिव सर्विसेज में पैसा खर्च न किया जाय । श्रीमन्, को स्मरण होगा कि बजट में सोशल वेलफेयर सरविस में केवल १२ प्रतिशत रुपया रखा गया है । मैं खयाल कर रहा था कि वही दुर्दशा मेडिकल सरविस में होने वाली है और इस मेडिकल अनुदान को, जिसको मेरे मित्र, स्वास्थ्य मंत्री जी ने उपस्थित किया है, यदि बारीकी से देखा जाय मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि वह दुर्दशा इसकी भी हुई है ।

श्रीमन्, एक अजीब किस्म का रोग व्याप्त होता जा रहा है । मैं इसका जिक्र किसी उपालम्भ के रूप में नहीं करना चाहता हूं । लेकिन अपने मित्रों से सोचने के लिये कहना चाहता हूं कि यह बार बार कांग्रेस के २० साल के ही शासन का ही जिक्र करते हैं । क्या कोई इसको अस्वीकार कर सकेगा कि जब अंग्रेज यहां से गये तो हमारे देश की औसत आयु २३ वर्ष छोड़कर गये थे । लेकिन आज ५० वर्ष की औसत आयु है । दूसरी पंचवर्षीय योजना म हमारी समाजीकरण और समाजवाद की ओर उपयोगी कदम बढ़ाने की चेष्टा हुई और यह हमारा प्रदेश किसी से पीछे नहीं रहा । आखिर समाजवाद है क्या ? हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि समाजवाद के अन्तर्गत हम इस प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सुविधा प्रदान करना चाहते हैं कि या तो वह रोगी न हो और यदि हो तो उसका निश्चित रूप से दवा दारू का प्रबंध कर सकें ।

श्रीमन्, हमने इस ओर अपना कदम बढ़ाया था । ओल्ड ऐज पेंशन हमने की और हमने यह तय किया कि धीरे धीरे हम ऐसी सुविधा कुछ लोगों को दे सकें जिससे उनके स्वास्थ्य का प्रबंध कर सकें। हमारी निश्चित योजना यह है, जैसे यू० के० में है, जिसको उन्होंने दूसरे महायुद्ध के समय प्रारम्भ किया था और तय किया था कि जो व्यक्ति रोगग्रस्त हो उसकी दवा

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

दारू का सरकारी तौर पर प्रबंध किया जा सके। हमारी यह निश्चित योजना है कि इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को दवा दारू का प्रबंध कर सकें। मेरे मित्र बतायें कि उन्होंन क्या किया? हमारी एक योजना का लक्ष्य यह था कि हमारे जितने श्रमिक हैं उनमें से प्रत्येक का हेल्थ इन्श्योरेंस कर सकें और उसके अन्तर्गत हम २७ लाख आदमी को लाना चाहते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बतायें कि उन्होंने इस संबंध में क्या किया? मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिये हमारी योजना थी कि हम किसी तरह से उनके लिये ऐसा प्रबंध कर सकें कि उनको भी निश्चित रूप से हम शनैः शनैः उस स्थान पर ले आयें जहां उनको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके। मेरे मित्र बतायें कि उन्होंने क्या किया? मेरा खयाल है कि हमारे साजवादी साथियों की वही दशा है तो तुलसीदल वाले सज्जन की थी। वह कहानी श्रीमन्, आपने सुनी होगी। एक प्रौढ़ सज्जन थे। धीरे धीरे उनको हाला का चस्का लग गया। उनके बच्चे और साथी उनको मना करते थे। एक दिन उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा कि इसको मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक काम जरूर करता हूं कि सुरापान करने से पहले सालिगराम के सामने तुलसी की पत्ती मुंह में रख लेता हूं। वही मेरे मित्रों को सुरापान करने और तुलसी की पत्ती का चस्का लग गया है। और उनमें प्रत्येक व्यक्ति को, जो बैठे हैं, हमारे पंडित जी ने अपनी ओर से एक छोटा सा आफर दिया, ऐसे मित्रों को जो अपने को समाजवादी कहते हैं, कि कहां उलझगये उस सड़ेगले कूड़े में, जो कूड़ा हमारे दल का है, जो हम को धोखा दे सकता है, वह तुम्हारे साथ कैसे रहेगा। उनसे हमने यह कहा कि अरे भाई चलो तुम सरकार बनाओ और तुम्हारी सरकार की हम सहायता करेंगे। लेकिन तुलसीदल मुंह में लिए बैठे हैं। नाम लेते हैं सिद्धांतों का, बड़ी बड़ी बातों का, लेकिन हर समय चेष्टा यह है कि किसी तरह से सरकार न गिरजाय।

मेरे मित्र शायद चले गये, वैद्य जी महाराज। उन्होंने जिक्र किया इस प्रदेश में अभी चेचक नहीं रुकी। इस प्रदेश में हम आज तक लगे हुए थे मलेरिया में। क्या कहा जा सकता है कि मलेरिया का कंट्रोल इस प्रदेश में नहीं हुआ? हम लोग कालरा को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। उसका कंट्रोल हुआ। हम लोग टी० बी० को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। टी० बी० बेड्स की उतनी वृद्धि हुई जितनी एक सदी में नहीं हुई थी। कहां है आज प्लेग? चेचक के निराकरण के संबंध में वह वहां बैठ कर बात कर रहे हैं जहां तुलसीदल और सुरापान साथ चल रहा है। लेकिन वह कार्य भी हमें सम्पन्न करना पड़ेगा और हम करेंगे।

एक चीज बड़े दुख की है। और यदि आवश्यकता पड़ी और उसके लिये कहीं और आगे जाना पड़े तो जायेंगे। हम नहीं चाहते कि मेडिकल कालेज की इस प्रकार दुर्दशा की जाय। जिस प्रकार हमारे मित्र करना चाहते हैं। उस कार्य को हमारे मित्र करना चाहते हैं जिसको अंग्रेज इस देश में नहीं कर सका। यदि मैं आप का ध्यान आकर्षित करूं तो मैं मेडिकल कालेज का छोटा सा इतिहास आपके सामने उपस्थित करूंगा। १९२२-२३ में यूनिवर्सिटी संगठित हुई और मेडिकल कालेज को उसमें लगाया गया। १९३५-३६ में गायनाकालोजी के प्रोफेसर का स्थान रिक्त हुआ। इस जमाने में आई० एम० एस० को जो आम तौर पर अंग्रेज हुआ करते थे, उनको नियुक्त किया जाता था। जी० एच० मर्चेन्ट करके एक योग्य चिकित्सक महिला थीं। उनको उस पद पर नियुक्त कर दिया गया। उस जमाने की ब्रिटिश हुकूमत ने एक कमेटी स्थापित की। उस कमेटी से कहा गया कि अगर इस तरह से आई० एम० एस० को नहीं रखा गया तो हमारी सर्विसेज निश्चित रूप से निराशा की ओर बढ़ेगी, हमारी सर्विसेज का मारल नीचे चला जायगा। लेकिन उस कमेटी ने, १९३९ में जो हेल्थ सर्वे ऐंड प्लानिंग कमेटी बनी थी, उसने अन्त में निर्णय लिया—

"King George's Medical College, Lucknow, is in every respect better suited in research. This college is under the direct control of the University and this may help to account for greater research activity than in most other medical colleges in India"

मेडिकल कालेज, लखनऊ प्रत्येक प्रकार से शोध करनेके लिये ज्यादा उपयोगी है। कालेज विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्य करता है। यह कारण हो सकता है कि जिससे व शोध कार्य करने में अधिक उपयोगी है। फिर मुदालियर कमेटी का १९५९-६० में निर्माण हुआ। मुदालियर कमेटी ने भी यह कहा था। उन्होंने यह कहा था चूंकि कि यह कालेज, डाइरेक्टली मेडिकल कालेज, यूनिवर्सिटी के अन्डर में काम करता है इसलिये इसकी कार्य-क्षमता, कार्य-पटुता और शोध छात्रों की क्षमता सभी कालेजों के छात्रों से अधिक है। तो यहां तक कहना चाहता हूं कि आज सारे संसार की मान्यताओं के विरोध में यह सरकार काम करने का दुस्साहस करना चाहती है। वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन जिसे डब्लू० एच० ओ० के नाम से जाना जाता है जो संसार का एक विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी संगठन है वह भी इन्हीं विचारों का है। मैं श्रीमन्, उसका भी निष्कर्ष आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि कदाचित बहुत ठीक होगा।

"The principle has met with world -wide acceptance. A World Health Organisation publication, the world Directory of Medical Schools shows that in almost every country Medical Education is now conducted under the aegis of Universtities."

यही नहीं, चुनौती के तौर पर मैं कहना चाहता हूं यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में कोई ऐसा कालेज नहीं है जो इस प्रकार का हो। यू० के० यानी इंगलैन्ड में भी इस प्रकार का जिक्र चला और वहां के भी विद्वान् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेडिकल कालेजेज को निश्चित रूप से विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत काम करना चाहिये। क्योंकि वहां पर शोध कार्य होता है। केवल इंजेक्शन लगा देना डाक्टर का काम नहीं होता है, केवल बुखार और मलेरिया का इंतजाम करना डाक्टर का काम नहीं होता है। डाक्टर का अन्तिम कार्य शोध कार्य है और वह कार्य यदि विश्वविद्यालययों के अन्डर में नहीं किया गया तो वह ठीक से नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में मुख्य मंत्री जी ने भी कहा। आप क्षमा करें, उन शब्दों का प्रयोग मुझे अच्छा नहीं लगा। त्रिपाठी जी ने कहा कि वह ऐसी दलील देते हैं कि जैसे तीसरे दर्जे के वकील दिया करते हैं--क्योंकि आपने आगरा को क्यों नहीं लिया तो इसको क्यों लेते हैं और प्रदेश में फलां हैं तो उसको क्यों न लें। इससे तथ्यों को मोड़ा नहीं जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि फलां फलां को यूनिवर्सिटी में नहीं लिया गया है तो यह ही उसके अन्डर में क्यों रहे। आप उसे अपने कब्जे में लेकर मनमानी करना चाहते हैं जिससे अपनी गवर्नमेन्ट के अन्तर्गत जिस किसी डाक्टर को फेंका जा सके और किसी को कहीं लिया जा सके। उनका यह कार्य निश्चित रूप से प्रतिक्रियावादी कार्य है और यह सदन कभी इस कार्य को बरदाश्त नहीं करेगा।

एक बात की ओर श्रीमन्, मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं और मेरा खयाल है कि उसके संबंध में सदन से एक चीज अर्ज कर दूं। हमारी कुछ योजनाएं थीं, किन्तु मैंने इस बजट के पन्ने पलट पलट कर देखे पर उनका कहीं हमने जिक्र नहीं पाया। केन्द्र ने हमारी सरकार से कहा था कि आपके प्रदेश के एक अंचल में वी० डी० (वेनरल डिजीजेज) जोरों से फैली हुई है इसके लिये आप एक पायलट स्कीम बना लीजिये, हम उसके लिये आपको आधा धन देंगे और शेष आधे का प्रबन्ध आप अपने पास से कर लीजिये और उसको हम शुरू भी करने वाले थे। किन्तु हम तो श्रीमन्, अब इधर आ बैठे, पता नहीं हमारे मंत्री अब उसके बारे में क्या करना चाहते हैं। (लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मैं केवल एक अन्तिम चीज ही कहना चाहता हूं कि इसको भी सरकार गम्भीरता से विचारे। १८९१ में ३१ करोड़ जनसंख्या हमारी थी और १९६६ में ५० करोड़ जनसंख्या माइनस पाकिस्तान है। श्रीमन्, जैसा कि कहा जाता है २ हजार ए० डी० में हमारी जनसंख्या होगी एक अरब। यह तो मैं नहीं कहना चाहता हूं कि चार बच्चों के बाद किसी को गद्दे जेल भेज दें, यह तो मंत्री ही कह सकते हैं। उनके बयान जितने होते हैं वह

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

२० साल को लेकर कहते हैं। २० साल यदि नहीं होते तो वह आज यहां नहीं होते, पता नहीं कहां होते। २० साल का झुनझुना हाथ में लेकर बजाना बन्द करें और तथ्यों को देखें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने फेमली प्लानिंग के लिये क्या कोई योजना बनाई ?

किन्तु कहीं ७, कहीं १०, कहीं १५, कहीं ५० लोगों के आपरेशंस होते हैं। मुझे माफ करें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर उसके विरोधी हैं। हम समझते थे कि समाजवादी बजट बनेगा तो उसके संबंध में चर्चा करेंगे लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी के पास तो एक शंख है २० साल उसी की ध्वनि वह किया करते हैं, कृपया उस शंख की ध्वनि बन्द कीजिये और इस प्रदेश में वह कार्य कीजिये जिसकी हम आपसे अपेक्षा करते हैं।

*श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो भाषण आदरणीय आचार्य जी का सुनने को मिला है उससे ऐसा लगता है कि मानों २० साल की बात कहने पर उन्हें चोट लगती है। तो चिढ़ क्यों है। जो जनता के सामने आपने कारनामे किये हैं वह किस्से तो खुलेंगे ही।

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें कुछ बातें तो स्वागत योग्य हैं। उदाहरण के लिये बहुत से डाक्टर्स जो जूनियर थे और किसी मिनिस्टर या नेता के रिश्तेदार थे वह तो सिविल सर्जन बन जाते थे और जिनके सोर्स नहीं होते थे वे बेचारे मुंह ताकते रह जाते थे। यह अच्छी परम्परा नहीं थी। लेकिन अब जो योजना बनी है सारा प्रांत उसका स्वागत कर रहा है। परिवार नियोजन की बात कही गयी है उस संबंध में मैं एक ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे समाज के ऊपर एक कलंक है वह भिखारी जिसके पैरों में कोढ़ है, वह भिखारी जिसका शरीर तो गल रहा है लेकिन आप रेलवे स्टेशनों के निकट जाकर देखिये उनके साथ कुछ औरतें भी रहती हैं और वे संतान उत्पन्न करते रहते हैं और अलग से एक वर्ग का निर्माण होता रहता है। उनका परिवार नियोजन नहीं किया जाता। इस कलंक को मिटाने के लिये इन भिखारियों के परिवार का नियोजन होना चाहिये। उनके छोटे-छोटे बच्चे रेलों में भीख मांगते हैं---बाबू एक पैसा दे दो और छोटी-छोटी बच्चियां जब बड़ी होती हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है उसके लिये क्या कहा जाय, इसलिये उनके परिवार नियोजन की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

आचार्य जी ने कहा २० साल में औसत आयु क्या हो गयी। मैं कहता हूं कि आप अपने आसपास के देशों को देखिये जो हमारे बाद आजाद हुये हैं।

आज मलेरिया उन्मूलन की बात कही गयी है। जब युद्ध हुआ था तो हमने सीमा रक्षा की बात कही तो ये उस समय कहा करते थे कि हम नियोजन में लगे हैं और जब आज भुखमरी की बात आयी तो कहने लगे कि हम, जब देश के ऊपर आक्रमण हुआ था उसमें लगे रहे। इसी तरह से जब चेचक रोग की बात आये तो ये हैजा रोकने में लगे रहे और जब हैजा रोकने की बात आयी तो मलेरिया रोकने में लगे रहे इस तरह से बहाने बाजी करने से बहुत दिनों काम नहीं चल पायेगा। इस मलेरिया पालन विभाग के लिये जिसको कहा जाता है मच्छर पालन विभाग खोला गया। इसमें यह कहा गया था कि सारे देश के अन्दर मच्छर मार दिये जायेंगे जब ये मच्छर मिनिस्टरों को काटने लगे तो मच्छर मारने वाले विभाग के लोगों ने दीवारों पर लिखा दिया कि मच्छड़ तो रहेंगे मलेरिया नहीं रहेगा। तो इस से यह चीज बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है।

एक मेरे साथी अभी आलोचना कर रहे थे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उनकी रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी रक्षा का जो सवाल है इसके लिये उनको पता नहीं है कि उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां पर तनख्वाह पूरी नहीं मिलती है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे भाई कांग्रेस के लोगों को उधर जाकर बहुत समझ आ गई। यह वह कुर्सी है जहां पर जाकर दिमाग के परदे खुल जाते हैं। वे २० साल तक इधर बैठते रहे लेकिन उनको कोई कमी नजर नहीं आई। आचार्य जी ने बड़ी लम्बी-चौड़ी बात कही लेकिन जब वह इधर सरकारी कुर्सियों पर बैठते थे तो उनको कोई कमी नजर नहीं आती थी। उनको हमारा धन्यवाद देना चाहिये कि उनको उधर बैठा दिया। अगर ऐसी बात न होती तो उनको उधर बैठने का अवसर नहीं होता। "आयें हमको वो कि हमने तुमको कातिल बना दिया।" जो लोग एक दूसरे से नफरत करते थे आज वह यहां पर साथ साथ बैठने लगे हैं। गुप्ता जी और त्रिपाठी जी इस राजनैतिक उथल-पुथल में अब एक जगह बैठने लगे हैं और एक जगह इकट्ठा हो गये हैं। तो यह खुशी की बात है कि हमने उनके सारे झगड़े दूर कर दिये।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि झगड़ा किस बात पर था। झगड़ा सारा सत्ता के लिये था जो सत्ता के छिनने के बाद खतम हो गया है। यह इसी तरह से हुआ कि जिस तरह से डकैत लूट का माल ले आये और उस पर झगड़ा हो जाय। अगर उस समय वहां पर पुलिस आ जाय तो सारा झगड़ा खत्म हो जाता है और वे सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग उस समय सत्ता के लिये लड़ाई आप में लड़ा करते थे। जब वह सत्ता इनके हाथ से छिन गई तो ये सारे एक जगह इकट्ठा होकर बैठ गये। यह खुशी की बात है। अब जब इनके हाथ से सत्ता चली गई तो रावण की तरह से बात करते हैं। जब रावण चला गया तो वह भी कहता था कि मैं यह करता, वह करता। इसी तरह से जब २० साल का पुराना शासन कांग्रेस के हाथ से निकल गया तो वह भी कहते हैं कि हम यह करते, वह करते, आचार्य जी ने भी उसी तरह से कहा कि हमारी योजना ऐसी थी और वैसी थी और हम यह करना चाहते थे और वह करना चाहते थे। अब तो वह सारा स्वप्न ही विलीन हो गया। आज उनको ये सारी बातें याद आई हैं कि हम कहां से कहां चले गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे हेल्थ मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है और अपनी मांग सदन में उपस्थित की है उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ कुछ सुझाव भी उनकी सेवा में रखना चाहता हूं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो दवाइयां अस्पतालों में भेजी जाती हैं जनता को बांटने के लिये उनमें बहुत गड़बड़ होती है। यह २० साल पुराना किस्सा है जिसको सुनकर आचार्य जी कहते हैं कि २० साल की हर तरफ से दुहाई दी जाती है। यह २० साल का ऐसा किस्सा है कि इस दौरान में लोगों की आदत पड़ गई है। डाक्टर से बात करते हैं तो वह कहता है कि क्या चाहते हो। जब रोगी अपनी बात कहता है तो डाक्टर कहता है कि तुम यहां के चक्कर में क्यों पड़े हो, यहां दवाई नहीं मिलेगी, यहां पानी मिलेगा। तुम मेरे घर पर आ जाना वहां तुमको मैं देख लूंगा। इस चीज को सरकार को दूर करना पड़ेगा। आप किसी भी अस्पताल में जा कर देख लीजिये कहीं पर भी दवाई नहीं मिलती है। उनको झांसा दिया जाता है। कह दिया जाता है कि क्या करें दवाई नहीं आती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जिस तरह से हमारे म्युनिसिपल बोर्ड में कम्पल पर निशान लगा दिया जाता है उसी तरह से सरकारी दवाइयों पर भी कोई लेबिल छाप देना चाहिये। जो दवाई दी जाय उस पर सरकारी लेबिल होना जरूरी है ताकि यदि वह दवाई कहीं बाजार में बिकती हुई पकड़ी जाय तो उसको सजा दी जा सके और पूरी तरह से दंड दिया जा सके।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि हमारे प्रांत के अन्दर डाक्टरी के लिये जो कालेज खुले हैं उनमें सैकड़ों डाक्टर शिक्षा लेकर निकलते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गरीबों की मदद की बात करते हैं तो उन कालेजों में गरीबों के लिये कोई इन्तजाम होना चाहिये जिससे उनके लड़के इसमें स्थान पा सकें। जो इम्तहान होता है उसमें जज का लड़का डाक्टर बन जाता है, डाक्टर का लड़का जज बन जाता है और मिनिस्टर का लड़का डाक्टर बनता है

[श्री महेश कुमार]

लेकिन मामूली किसान का लड़का किस प्रकार से डाक्टर बनेगा। उसको खराब शिक्षा प्राइमरी स्कूल से ही ऐसी मिली है। वह धूप में बैठकर पढ़ा है जहां पर छप्पर भी नहीं है। ऐसी ही वहां पर पढ़ाई होती है। वहां तो उस को वह मास्टर मिलते नहीं।

आप की योजनाओं का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने योजना रखी है पर्वतीय क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने की, ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने की, लेकिन इसके साथ ही यह भी पाबन्दी होनी चाहिये कि उस में गरीबों और किसानों के लड़के ही दाखिला पायेंगे और दूसरे उन में पढ़ने वाले प्रत्येक डाक्टर के लिये अनिवार्य होगा कि वह पढ़ाई के बाद ग्रामीण क्षेत्र में ही नियुक्त किया जायगा। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से डाक्टर उच्च शिक्षा आदि का बहाना लेकर विदेश चले जाते हैं। उन के लिये भी पाबन्दी होनी चाहिये कि कम से कम पांच साल वे यहां सेवा करके ही बाहर जाने पायेंगे। प्राइवेट डाक्टर्स यदि सेवा भाव से काम करना चाहते हैं तो हमें उन का स्वागत करना चाहिये और उन की सेवाओं का उपयोग करना चाहिये। मैं कहता हूं कि आप यहां के धुरंधर राजनीतिक नेताओं की चिन्ता मत कीजिये। जैसे आपने बांदा में जा कर दवाइयों को पकड़ा है, जैसे और जगह रेड्स किये हैं उसी प्रकार आप अपना काम जारी रखिये। माननीय अध्यक्ष जी, बीस साल से सम्बल में एक आक्सीजन सिलेंडर बेकार पड़ा हुआ है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। मैं इस संबंध में दाऊ दयाल खन्ना जी से मिला था। उस में के दो एक पुरजे खराब हैं लेकिन उस का उपयोग नहीं किया जा सकता और आज तक वह बेकार है। मुरादाबाद की एक्सरे मशीन भी कह दी जाती है कि खराब है, लेकिन जब पैसा मिल जाता है तो वह ठीक हो जाती है। इन शब्दों के साथ अन्त में मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे समय दिया। मैं इस कटौती के प्रस्ताव की ताईद करता हूं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो ग्रांट पेश की है वह तो समाजवाद से बिलकुल खाली है। उन का खयाल मजदूरों की तरफ नहीं गया है। अभी उन की उम्र थोड़ी है, वे नातजुरबेकार हैं और उन्होंने डाक्टरों को देखा नहीं है। अगर डाक्टर उन को एक इंजेक्शन भी लगा देंगे तो वे इस बीस साल वाली बात को भूल जायेंगे। यहां उन के हर सपोर्टर को बीस साल, बीस साल की ही डकारें आ रही हैं और इस कारण उन को बदहजमी हो गयी है। इस का मतलब यह है कि वे कमजोर हैं। बीस साल में कांग्रेस सरकार ने जो काम किये हैं उन के कारण आप अंधे से हो रहे हैं। किसी आई स्पेशलिस्ट से अपना इलाज कराइये तब आप को दिखायी देगा कि इस बीच कितनी तरक्की हुई है। मंत्री जी ने कहा कि बीस वर्ष तक बड़े लोगों का इलाज ही होता था। आप डाक्टरों के करेक्टर पर रेफलेक्शन क्यों डालते हैं। मैं यह पूछता हूं कि सन् ४८ से लेकर आज तक के आबादी शुमार हस्पतालों के ले लें तो हमारे अहद तक हजारहा लोग देहातों से आकर इलाज करवाते रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो लोग डरते थे। आज देहात का आदमी आकर अस्पताल में इलाज करवाना चाहता है। यह आपकी खूबी नहीं है, हमारी देन है और कांग्रेस की योजनाओं की देन है जिसकी तरफ से आप आंखों पर पट्टी बांधे हुये डकारें लेते हैं कि "हाय बीस साल ! हाय बीस साल !!"

दूसरी बात यह है कि मरकजी सरकार जो योजना में कट कर रही है, तो कौन सी योजना में आपने ऐसी तरक्की करवायी है जिससे मालूम हो कि आप कुछ करना चाहते हैं। पिछले साल की ग्रांट कितने करोड़ की थी और आज कितने की है ? आपने एडमिनिस्ट्रेशन इतना लूज कर दिया है कि मोर कमेटी की सिफारिश यह थी कि "देयर शुड बी ए कम्पलीट इंटीग्रेशन आफ मेडिकल ऐंड हेल्थ सर्विसेज ऐट एवरी स्टेज"। उन्होंने कहा कि एक ही

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डायरेक्टर होना चाहिये मेडिकल ऐंड हेल्थ में और आपने तीन हिस्सों में बटवारा कर दिया। इस्टैब्लिशमेंट एंड क्लार्क्स का एक डायरेक्टर, मेडिकल का एक डायरेक्टर और हेल्थ का एक डायरेक्टर। तीनों डायरेक्टरों में लड़ाई हुआ करेगी। नतीजा यह होगा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। मैं जानता हूं आप अच्छे हैं, नौ उम्र हैं, जोश हैं, सब कुछ करना चाहत हैं, लेकिन भाई साहब आप अभी नातजुर्बेकार हैं, आप कुछ नहीं जानते। आप डाक्टरों की दवाई के बारे में, इंजेक्शनों के बारे में रिसर्च के बारे में कुछ नहीं जानते। आपको इल्म नहीं है, यह चौधरी चरण सिंह की देन है कि उन्हें कुछ पोर्टफोलियो लोगों को देने थे, लिहाजा आपको भी मिल गया। लेकिन तजुर्बा आपको सिखायेगा कि कांग्रेस इन २० सालों में कितनी दुश्वारी से गुजरी है और किस तरह से गवर्नमेंट को निभाया है। ये जनसंघ वाले कहते हैं कि भूखों की फैमिली प्लानिंग करो, इनकी न करो। यह है इनका समाजवाद। फैमिली प्लानिंग हो तो सब का हो। कहा गया कि डाक्टरों की कमी है, वह तो हमेशा रही। हमने कोशिश की लेकिन रुपये पैसे की कमी से वेतन दे ही नहीं पाये। आप कहां से दे पायेंगे? जब ९२६ करोड़ की योजना है जिसमें ४२१ करोड़ आपको जमा करना था, वह आपने नजरअन्दाज कर दिया, लोगों के सामने रखा ही नहीं और अब कहते हैं कि समाजवाद कायम करने जा रहे हैं।

"साफ छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं—खूब परदा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं।" यह सोचिये कि जब योजनायें नहीं रखेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा, सोशल वेलफेयर कैसे होगा? यही आपकी कमी है। आप डाक्टर को बुलाकर कितना वेतन देंगे। अच्छा वेतन पाने वाले कैसे देहातों में आयेंगे। उनके लिए मकानात, अच्छे रहन सहन का इंतजाम कैसे होगा, रुपया कहां से आयेगा? यह तो आपको करना ही होगा। वरना आपकी यह स्कीम ही फेल हो जायेगी। माननीय मंत्री जी मजदूरों के बारे में बोले तक नहीं। न ही स्टेट इन्श्योरेंस की कोई बात उन्होंने कही। यह देश किसान और मजदूरों का देश है। कांग्रेस सरकार ने मजदूरों के लिये स्टेट इन्श्योरेंस की व्यवस्था की। मजदूरों का मुफ्त इलाज होता है। कानपुर में उस अस्पताल को आप जाकर देख सकते हैं। यह कांग्रेस सरकार ने किया है, आप ने नहीं।

टी० बी० क्लीनिक्स की एक्सरे की प्लेटें बाजार में बेंची जाती हैं, और लोगों को वह नहीं मिल पातीं। दवा जब हमको दी जाती है तब मोहर लगायी जाती है, मगर जब दवा अस्पताल में आती है उसी वक्त मोहर नहीं लगायी जाती ताकि वह बाजारों में जाकर बिक सके। जिस दिन डाक्टर ने आपको ऐसा इन्जेक्शन लगा दिया आप सब भूल जायेंगे।

नर्सेज के बारे में सिम्पेथेटिक एटीट्यूड होना चाहिये। यह मरीज की सेवा करती हैं, लेकिन उनका न तो वेतन सही है और नहीं उनको दूसरी सहूलियतें मिली हुई हैं। सुप्रिन्टेंडेंट आफ नर्सेज से अगर कुछ कहो तो वह कहती हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर मत करो। आपका जी० ओ० है कि जिसका शौहर जहां हो उसकी ड्यूटी वहीं लगायी जाय। मगर आज हस्बैंड कहीं हैं, बच्चे कहीं हैं, बीबी कहीं हैं। तो वह कैसे सच्ची सेवा मरीजों की कर सकती है। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिये।

मैं पूछता हूं कि मिर्जापुर में आपने कितने डाक्टर इस समय भेजे हैं? मिशन हास्पिटल के जो डाक्टर्स हैं वे ही वहां सेवा कर रहे हैं। जितना वहां उन्होंने काम किया है आपके डाक्टरों से नहीं किया है। फिर भी आप उनको कम एड दे रहे हैं।

सिविल सर्जन देहात का दौरा करेंगे, आपने कहा वह तो देहात में जायेंगे, उनको भत्ता मिलेगा। पहले भी जाते थे। इसमें आपने कौन-सा नया परिवर्तन कर दिया। आपने कौन सा ऐसा नया तरीका अपनाया जिससे कि हम समझते कि तरक्की होती। इस तरह से तो तरक्की के बजाय कहीं तनुज्जली ही न हो जाय। मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से निवेदन

[श्री ए० जी० बख्त]

करूंगा कि वे ३-३ डायरेक्टर्स के स्थान पर एक डायरेक्टर रखें, इस से प्रदेश को ज्यादा लाभ होगा ।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो स्वास्थ्य का अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है इस सिलसिले में जो चर्चा अभी तक की गई उसके बारे में हमें बहुत थोड़ा सा निवेदन करना है । निवेदन यह करना है कि उधर से हमारे ज्यादातर माननीय कांग्रेस के सदस्यों को इस बात की चिढ़ हो रही है कि उनके बीस वर्षों के कारनामों का बराबर जिक्र क्यों किया जा रहा है । असल में जब कोई सरकार किसी काम को अपने हाथ में लेती है तो यह आवश्यक होता है कि वस्तुस्थिति क्या है और उसकी पूरी जानकारी रक्खे और अगर सरकार को उसकी जानकारी नहीं तो वह कुछ ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है । हम तो पिछले बीस साल का जिक्र करते हैं तो माननीय सदस्यों को इतनी खीझ होती है लेकिन हमें सुनकर आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस पार्टी के एक माननीय वरिष्ठ सदस्य को जिन्हें मैं समझता हूं उनके कहने का मतलब और कुछ नहीं हो सकता है, या तो उन्हें बुद्धि का अपच है या और कोई बात है, जब यह मुकाबिला किया जाता है तब यह समझ में नहीं आता है कि ये हिम्मत कैसे करते हैं ।

माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने कहा कि अंग्रेज जब हिन्दुस्तान छोड़ कर गये तो यहां औसत आयु पच्चीस वर्ष की थी जो अब ५० वर्ष की हो गई है । मुझे दुख है इस बात को सुनकर कि हमारे देश के रहने वाले जो कल तक माननीय मंत्री थे इस राष्ट्र की सरकार के किसी काम का मुकाबिला एक परदेशी सरकार से कर रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बीस साल के कुकर्मों से देश और प्रदेश की जनता पीड़ित जरूर है लेकिन आचार्य जी को हम किसी अंग्रेज से अच्छा समझते हैं, समझते थे और समझते रहेंगे । अगर उनको बताना था तो यह बताना चाहिये था कि आज भी अंग्रेज के देश में औसत आयु क्या है और उत्तर प्रदेश में क्या है । अगर वे इसका मुकाबिला करते तो ठीक करते लेकिन परदेशी शासन जो शोषण करने के लिये था उसके मुकाबिले में कुछ ज्यादा योग्यता दिखाई है जिसके लिये उनकी तारीफ नहीं की जा सकती । यह तो कोई न कोई तरीका ढूंढकर अपनी कमजोरियों को छिपाना मात्र है । जो सरकार के सामने सवाल हैं उन सवालों की ओर अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि अभी तक आखिर स्वास्थ्य की स्थिति क्या रही है । मैं तो यह समझता हूं कि किसी भी सभ्य-देश को स्वास्थ्य शिक्षा आदि मामले में उदार होना चाहिये । उसे समान दृष्टि रखनी चाहिये और इसमें किसी भी प्रकार की किसी पर कोई कीमत न रक्खें । किसी से बिना कीमत लिये बिना मुआविजा लिये बिना किसी लाभ के हर नागरिक को स्वास्थ्य शिक्षा और न्याय की सहूलियत देनी चाहिये और यही किसी राष्ट्र की सफलता की निशानी होती है । सरकार को स्वयं उधर आगे बढ़ना चाहिये । हमें दुख हुआ कि पिछले कुछ दिनों से देहातों में, अस्पतालों में जहां पैसे नहीं थे वहां दस पैसे लेने की प्रथा जारी की गई है । मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि बहुत से गरीब लोग दवा न लेकर वापिस चले जाते हैं केवल दस पैसे न होने की वजह से । दवा के मामले में शुल्क नहीं लेना चाहिये चाहे वह किसी अच्छे काम में ही क्यों न लगाया जाय । तो मैं यह चाहता हूं कि यह हटाया जाना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि यद्यपि यह ठीक है कि अभी तक बहुत से अस्पतालों का निर्माण हुआ है लेकिन बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कहीं तो डाक्टर नहीं है और कहीं पर दूसरा स्टाफ नहीं है । इसके अलावा जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि अस्पतालों का वितरण ठीक नहीं है । मेरे ही गांव के एक फर्लांग पर इधर और एक फर्लांग पर उधर, दो-दो अस्पताल हैं लेकिन मेरे ही जिले गोरखपुर में ऐसे भी स्थान हैं जहां २०-२० मील तक कोई अस्पताल नहीं है, न कोई सड़क है । अगर वहां कोई आदमी बीमार हो जाय तो

सिवाय मरने के और कोई चारा ही नहीं है। इसलिये अस्पतालों के खोलने में किसी निश्चित योजना के अनुसार मंत्री जी को चलना चाहिये।

इसके अलावा इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और यह पिछले २० सालों के कांग्रेसी राज्य की देन है। जो सरकार अपने को देहात के किसानों की हितैषी कहती हो उसके जमाने में केवल लाल पीला पानी ही उनको दिया जाता है। डाक्टर लोग इंजेक्शन की ही सलाह देते हैं और कभी-कभी तो उनमें भी केवल डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। इसलिये इस स्वास्थ्य के मामले में भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय होना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि बहुत से स्थानों पर छिपी हुई दवाओं को निकाला। कहीं से दवा निकाल लेना अथवा किसी अधिकारी को सजा दे देना इसका स्थायी हल नहीं है। यह बड़े अफसोस की बात है कि एक ओर दवाओं में मिलावट होती है और दूसरी तरफ बिना पैसे के दवा मिलती नहीं है। डाक्टर लोग बाजार से दवाओं को मंगाते हैं और जब मरीज बाजार से लाता है तो उसमें से भी कुछ रख कर उसको दवा दी जाती है। अगर सरकार ने इस भ्रष्टाचार को न मिटाया तो आप कितना ही खर्चा क्यों न करें, उससे कोई नतीजा नहीं हो सकता।

मेडिकल सर्टिफिकेट वाली बात भी बड़ी भयानक है। यह कानूनी भ्रष्टाचार है। जिस भी सरकारी मुलाजिम को छुट्टी लेनी होती है वही मेडिकल सर्टिफिकेट लगा देता ऐसे पवित्र पेशे के लिये ऐसी बात होना और २ रुपया लेकर सर्टिफिकेट दे देना यह बड़े कलंक की बात है। इसके लिये भी उचित कार्यवाही होनी चाहिये।

इसके अलावा किसी की दवा में फर्क नहीं होना चाहिये। स्वास्थ्य के मामले में सभी नागरिक बराबर हैं। यह बड़े दुख की बात है कि सरकार एम० एल० ए० के लिये अलग दवाओं का कोटा रखती है, सरकारी कर्मचारियों के लिये अलग रखती है और मिनिस्टरों के लिये अलग रहती है और फिर बाजार में बिकने के बाद जो बच जाता है वह साधारण नागरिक को मिलता है। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। यह दूसरे तरीके हो सकते हैं जिनसे सरकारी मुलाजिमों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, दिया जा सकता है लेकिन इस प्रकार से जनता के पैसे से विभिन्न प्रकार के कोटे रखना गलत बात है। एम० एल० एज० के लिये कोटा सुरक्षित करना बड़े शर्म की बात है कि वह जनता के प्रतिनिधि होकर पहले अपने लिए दवा का इन्तजाम, रहने का इन्तजाम और सब इन्तजाम अपने लिये करने के बाद जनता का इन्तजाम करते हैं। इसको खत्म होना चाहिये। मैं समझता हूं ऐसा करने से जनता को अधिक विश्वास होगा। इन शब्दों के साथ में मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जहां २०-२० मील तक अस्पताल नहीं हैं, वहां अस्पताल खोले जायं।

**श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)--**

अध्यक्ष महोदय, यहां अस्पतालों और मेडिकल हेल्थ के बारे में जो इस सदन में चर्चा चल रही है उस को मैं ध्यान से सुन रहा था। मुझे बहुत अधिक तो नहीं कहना है केवल दो-तीन ही बातें आप के सम्मुख रखना है पहली चीज तो यह है कि अभी तक कोई भी व्यक्ति सरकार की तरफ से ऐसा नहीं बोला कि जिसने २० साल के कांग्रेसी कुशासन की रट न लगाई हो। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की आयु अभी ३५ वर्ष की ही है और २० साल पहले वह केवल १५ साल के रहे होंगे। जब वह १५ साल के थे तो उन को इन २० साल के कांग्रेसी कुशासन करने वालों ने ही जिन्दगी का यह रास्ता दिखाया होगा, वह कोई खुदा के यहां से तो देखकर आये न होंगे। हर बात को छिपाने और पर्दा डालने के लिये २० साल की बात कही जाती है, यह अपना २० साल का तकिया कलाम बन्द कीजिये।

[श्री मदन मोहन मिश्र]

दूसरे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इनटेम्परेट भी हो जाते हैं बात करते करते बजाय आप के उन्होंने माननीय कृष्णानन्द जी को ही हुक्म दे डाला कि वह बैठें। कम से कम एक मंत्री के लिये यह एक बहुत ही अशोभनीय बात है। आज अस्पतालों की हालत यह है कि अगर कोई मरीज आता है तो पहले तो उस से सौदा किया जाता है और अगर उसकी जेब में या पास में रकम है तो डाक्टर की पूजा होती है और उसका इलाज अच्छे ढंग से होता है लेकिन अगर कोई मरीज गरीब है जिस को कि वह धूलिधूसरित कहते हैं और जिस को कि वह बात बहुत करते हैं उन की कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जो कायदे कानून वह बदल रहे हैं उस के संबंध में मैं ज्यादा मिसाल न देकर एक कानपुर की ही मिसाल दूंगा कि वहां पर एक जिला परिवार नियोजन अधिकारी हैं जो ८ साल से लूटपाट मचाये हैं लेकिन उस की तरफ उन की नजर नहीं गई, वह दूसरे लोगों की तरफ ही गई। रायबरेली में कसूर करने वाले यानी चोरी करने वाले या चोरी के आदी जो डाक्टर हैं और वह डाक्टर जो चोरी को खत्म करना चाहते हैं उन दोनों को मंत्री जी ने एक ही पैमाने से नापा है। दोनों से कहा गया कि अपनी शिकायतें लिख कर दें पर उस को शायद पढ़ा भी नहीं उन्होंने ९ मास के आये हुये डाक्टर का तबादला करना ज्यादा जरूरी समझा क्योंकि उसने ३–४ साल से रहते हुये वहां के डाक्टरों की चोरियों को पकड़ा था और वह योग्य था तथा ईमानदार था। लेकिन अफसोस है कि उसी का तबादला किया गया। इस संबंध में मैं अर्ज करूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इतनी जिद्द हो गई कि उनके जो उपमंत्री ने सारे तथ्यों को समझने की कोशिश की लेकिन उन की बात भी नहीं मानी गई। उपमंत्री जी ने लिखा कि ऐसे योग्य सिविल सर्जन को रोका जाय क्योंकि अभी और बहुत कम दिन उन को आये हुये हैं लेकिन मंत्री जी ने उसको नहीं माना पता नहीं किस जिद्द के कारण? कुछ ऐसे लोग हैं जो उन पर हावी हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं और उनका नाम भी जरूरत होगी तो मैं दे लूंगा। उनके कहने पर एक योग्य डाक्टर को हटाया गया और उस की सेवाओं से रायबरेली जैसे पिछड़े और गरीब जिले के मरीजों को महरूम रखा गया और उसकी योग्यता से लाभ नहीं उठाने दिया गया। श्रीमन्, आपके द्वारा दो तीन चीजों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि कानपुर के जिला परिवार नियोजन अधिकारी के विरुद्ध माननीय मंत्री को प्रार्थना–पत्र दिए, रिप्रेजेन्टेशन के बाद रिप्रेजेन्टेशन किये गये, और यह बताया गया कि वहां पर धन का घोटाला भी हुआ लेकिन इस जन प्रिय सरकार ने जो इतनी डींगें हांकती है, आज तक कुछ नहीं किया। जिला कानपुर के सरसौल विकास क्षेत्र में दिनांक २७, २८ और २९ दिसम्बर, १९६६ को एक परिवार नियोजन प्रशिक्षण शिविर चला था। उसमें रुपये पैसे की कुछ गड़बड़ हुयी लेकिन न तो कोई इन्क्वायरी ही बैठायी गयी और न कोई अधिकारी ही सस्पेन्ड हुआ।

वहां पर ८०० रुपये की नॉन रेकरिंग और १६०० रुपये की रेकरिंग खर्चे के लिये धनराशि स्वीकृति हुयी लेकिन इस प्रकार से २४०० रुपये का जो अनुदान विकास क्षेत्र सरसौल के लिये दिया गया था उसमें उल्टा ही हुआ। ८०० रुपये रेकरिंग पर और १६०० रुपये नॉन रेकरिंग पर खर्च हुआ। इसकी भी कोई जांच आज तक नहीं की गयी।

रायबरेली जिले के जगतपुर ब्लाक में प्राथमिक चिकित्सा के लिये एक अस्पताल बनाया गया लेकिन कई वर्ष हो गये आज तक वहां पर कोई डाक्टर नहीं है। न वहां पर दवाइयों का ही कोई प्रबन्ध है। एक कम्पाउन्डर वहां पर है जो न तो ठीक ढंग से निदान ही कर सकता है और जब निदान नहीं कर सकता है तो दवाई देने की बात तो उठती ही नहीं। वहां पर केवल एक बिल्डिंग है, एक ढांचा बना हुआ है और बस–बस मील से जो लोग वहां पर इलाज के लिये आते हैं निराश होकर लौट जाते हैं।

मलेरिया उन्मूलन की बहुत चर्चा की गयी लेकिन में कहूंगा कि मलेरिया अब भी मौजूद है। अगर आप सही तौर से जानना चाहें तो डाक्टरों से रिपोर्ट मंगालें। यह कम अवश्य हुआ है लेकिन बहुत कम रहा है। शायद १ प्रतिशत या हजार में एक भाग अभी शेष है।

जहां तक चेचक के रोग का प्रश्न है माननीय मंत्री जी ने कहा कि चेचक से कोई मौत नहीं हुयी है। मैं तो यही कहूंगा कि इसके बारे में जिलों से झूंठी रिपोर्ट भेजी जाती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार के जिला स्तर पर अन्दरूनी और इन्स्ट्रक्शन्स रहते हैं और दिखावे के कुछ और होते हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो गलत सूचनायें यहां पर भेजी जाती हैं, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता है तो यह मर्ज बढ़ता ही चला जायगा।

जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि १० वर्ष बाद आपकी आबादी चाहे १ अरब हो जाय लेकिन जब इस देश का विभाजन माइनॉरिटी और मैजोरिटी के आधार पर हुआ तो आप इस परिवार नियोजन को केवल एक तबके के लोगों के ऊपर ही क्यों लागू करते हैं। मैं समझता हूं कि जितने लोग यहां पर रहने वाले हैं, सब कम्युनिटीज पर इसको लागू करना चाहिये। यदि यह केवल एक वर्ग के लोगों पर ही लागू होगा तो बड़ा दुःख होगा क्योंकि शायद वे फिर इस मुल्क के टुकड़े करायेंगे। इस-लिये मैं आपसे और सरकार के अन्दर विचारकों से कहना चाहता हूं कि यद्यपि यह केन्द्रीय सरकार का विषय है आप उनको रिप्रेजेन्ट कीजिए कि किसी भी बहाने से किसी भी नियम से यह किसी पर लागू न हो और अगर हो तो सब कम्युनिटीज पर बराबर लागू हो।

यह जो कहा जाता है कि १० बजे पहले अस्पताल खुलते थे और अब साढ़े ७ बजे खुलने लगे हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह चीज गलत है। न पहले १० बजे अस्पताल खुलते थे। ८ बजे डाक्टर आ जाते थे। कोई स्वेच्छाचारिता से १२ बजे आ सकता है। यह भी मंत्री महोदय ने कहा था कि १० पैसे के टिकट वाली प्रथा को खत्म कर दिया है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है और यह स्टेटमेंन्ट उनका सही नहीं है।

इसके अलावा जो मेडिकल सेटअप है वह ठीक नहीं है। कुछ अस्पताल डी० एम० ओ० एच० तथा कुछ सिविल सर्जन के मातहत हैं। इसका एकीकरण किया जाय क्योंकि इसमें परेशानी होती है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो डायरेक्टर, मेडिकल हेल्थ हैं उनका नाम भी ट्रान्सफर वाली लिस्ट में है अथवा नहीं ? कानपुर में एक डाक्टर हैं परिवार नियोजन के अन्तर्गत जो कि ८ साल से वहां पर हैं उनको भी ट्रान्सफर किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नरवदेश्वर (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने १५ करोड़ कई लाख रुपये की मांग पेश की है। इससे यह अन्दाजा लगता है कि जनसंख्या को देखते हुए वह बहुत नाकाफी है और इतने अनुदान से जहां तक प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य तथा दवाइयों का सवाल है उसकी पूरी व्यवस्था नहीं की जा सकती। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाय तो दो रुपये या पौने दो रुपये यह अनुदान पड़ेगा जो बिलकुल नाकाफी है।

जहां तक हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य का सवाल है हमारे विरोधी दल के साथियों को काफी एतराज हुआ है सरकारी पक्ष के साथियों को बोलने पर। अपने विरोधी पक्ष के साथियों का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे देहात में एक कहावत है : "काने को काना न

[श्री नरवदेश्वर]

कहना चाहिये।" अगर काने को काना कहा जाय तो बहुत चिढ़ता है। तो इसी प्रकार मैं अपने साथियों से अपील करूंगा कि कांग्रेस के २० सालों के कारनामों को प्रस्तुत करने से अगर कांग्रेस के सदस्यों क: झुंझलाहट है तो थोड़ा कम प्रस्तुत किया जाय क्योंकि उनको तो अपने कारनामों की जानकारी है और सारा प्रदेश जानता है। हमारे देहात में जो अस्पताल हैं उनकी दशा बहुत ही शोचनीय है, शहरों की तरफ का ध्यान पिछली सरकार का विशेष रूप से रहा। मंत्री जी ने कहा कि ५०० से ऊपर अस्पताल ऐसे हैं जहां डाक्टर की व्यवस्था नहीं है, ये अधिकतर अस्पताल देहातों के होंगे। मेरे क्षेत्र का जहां तक संबंध है, उससे स्पष्ट है कि देहातों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं रहा है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि देहातों की तरफ ध्यान जायगा। लेकिन हमारे आजमगढ़ जिले में जो अस्पतालों की दशा है वह बहुत ही शोचनीय है। जिला परिषद् की एक डिस्पेंसरी है सगड़ी क्षेत्र में जिस में १५ रु० की दवायें वितरित करने के लिये डाक्टर को मिलती हैं। जब कि २५० रु० डाक्टर को तनख्वाह मिलती है, १२५ रु० कम्पाउन्डर को तनख्वाह मिलती है, ८० रु० चपरासी को और २५, ३० रुपये का किराये का मकान लिया जाता है। यह प्रमाण इसलिये दिया गया है कि देहात के अन्दर अस्पताल खोलने से ही समस्या हल नहीं होगी बल्कि दवाओं की मात्रा बढ़ानी होगी, कम से कम इतने की दवायें तो दी ही जायें जितना सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च करती है।

शहरों का क्या हाल है? हमारे एक मित्र ने लोक महत्व के प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आश्वासनों के बाद भी जब सदन में मामला प्रस्तुत हो गया, साधारण आदमी का नहीं, बल्कि एक एम० पी० का श्री जयबहादुर सिंह का, इलाहाबाद मेडिकल कालेज के अन्दर रात के समय किसी अस्पताल में फोन करने पर भी कोई फोन रिसीव करने वाला नहीं था। उन को किसी प्रकार रेलवे अस्पताल में जगह मिली और अगले दिन वह मेडिकल कालेज में गये। ४ तारीख से आज तक मेडिकल कालेज के अन्दर ठीक से व्यवस्था न हो सकी। इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि प्रदेश के अन्दर साधारण आदमी अगर अस्पताल के अन्दर जायगा तो उसको कौन सी दुर्दशाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। एक सदस्य ने कहा कि अस्पताल के अन्दर इंजेक्शन्स लिखे जाते हैं कि बाहर से खरीद लाओ। मैं कहता हूं कि बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां मरीज के पेट पर छुरा रख कर उसकी जिन्दगी से खेल किया जाता है, मोल भाव किया जाता है। ऐसा क्यों है? इसलिये कि कांग्रेस सरकार ने डाक्टरों को यही रास्ता दिखाया है और वही रास्ता वह आज भी चल रहे हैं।

लखनऊ में जो आयुर्वेदिक कालेज है उसकी ऐतिहासिक हड़ताल को अभी बहुत दिन नहीं हुये। इसी लखनऊ में पिछले १२ महीने तक उस कालेज के छात्रों ने हड़ताल की थी। उनकी यह मांग थी कि उनको दूसरे डाक्टरों के बराबर माना जाय, वही वेतनक्रम दिया जाय। उस कालेज के जो प्रिन्सिपल महोदय हैं उनके कारनामे ऐसे हैं जो छात्रों को पढ़ाई में मदद देने वाले नहीं हैं। उनका आरोप था उस कालेज पर यह कि वहां पर गबन है और बहुत बड़े पैमाने पर गबन है। उनकी मांग थी कि सरकार इसकी इन्क्वायरी कराये लेकिन नहीं करायी गयी और आज भी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान खींचना चाहूंगा कि पी० ए० सी० की बटालियन उस कालेज में तैनात है पता नहीं किस लिये जबकि न हां कोई आन्दोलन है न और कुछ। वह पुरानी सरकार कांग्रेस की सरकार थी जिसके काले कारनामे छिपे नहीं हैं और सारे प्रदेश की जनता जानती है। उसने उस आन्दोलदन का दमन किया और डाक्टर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन पर लाठी चार्ज किया और उन्हें जेल भेजा। लेकिन इस नयी सरकार को गम्भीरता से उनकी मांगों पर विचार करना चाहिये और उन छात्रों को, जबकि आप कहते हैं कि हमारे यहां डाक्टरों की कमी है, और डाक्टरों के बराबर तनख्वाह वगैरह देनी चाहिये।

मैं आपके सामने एक और सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। होमियोपैथिक और यूनानी और आयुर्वेदिक शिक्षाओं को सुलभ किया जाना चाहिये बड़े पैमाने पर, और उनके डाक्टरों को एलोपैथिक डाक्टरों के समकक्ष वेतन क्रम तथा और दूसरी सुविधायें दी जानी चाहिये। देहाती

क्षेत्रों में जाने के लिये डाक्टरों को प्रोत्साहन देना चाहिये और एक समय निर्धारण करना चाहिये जैसा कि मंत्री महोदय ने इशारा किया कि तीन वर्ष करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको पांच वर्ष करना चाहिये। दूसरे, नर्सों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। उनका प्रमोशन बिल्कुल नहीं किया जाता। उनके प्रमोशन के नियम ऐसे हैं कि जिनसे वे प्रोमोट नहीं हो पाती हैं और मेल कम्पाउन्डर्सको उनके कम्पीटीशन में रखा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। इसके अलावा टी० बी० क्लिनिक्स जहां पर सदर हास्पिटल्ससे अटैच्ड हैं वहां दोनों का बजट एक सा होता है। वह अलग-अलग होना चाहिये ताकि टी० बी० के मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसके साथ ही साथ आयुर्वेदिक अस्पताल की बिल्डिंग के बारे में बजट में कोई जिक्र नहीं है। यूनानी और आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज को बनवाने की तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के दोनों ओर से माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना लेकिन मुझे खेद है कि जिस साइन्टिफिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत विषय पर विचार होना चाहिये था उसको नजरअन्दाज किया गया जानकारी से या बेजानकारी से। सराहना उस सरकार की कर सकते हैं जिसके राज्य में इन्सान बीमार हो ही नहीं। "प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर"। रोकथाम होनी चाहिये बीमारियों की। जिस सरकार के राज्य में हर जगह अस्पताल हो, वह इस बात का सबूत है कि वह सरकार नहीं जानती है कि "प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर"। अगर बीमारियों की रोकथाम की जाय, अगर हेल्थ क्लीनिक हर सेंटर में खोले जायं, लोगों के स्वास्थ्य की चेकिंग हर महीने हो तो लोग बीमार क्यों हों?

दूसरी बात यह कि हमारे यू० पी० के अन्दर जो मच्छरों की तरह अस्पतालों में लोग भिनभिनाते रहते हैं और दवाइयां नही मिलतीं, इसका कारण क्या है। हमें देखना चाहिये कि किस कारण से यह अव्यवस्था है। इसकी सबसे बड़ी वजह आर्थिक खामी है, रुपये की कमी है, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के अन्दर विटामिन की कमी है, लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वे बीमारी को रोक सकें। आप हजारों अस्पताल खोलें लेकिन बीमारी को आप कम नहीं कर सकते। बीमार होने के बाद आप इलाज की बात कहते हैं। यह बहुत ही छोटी बुद्धि की बात है। बड़ी बुद्धि की बात यह है कि इंसान बीमार पड़ने ही न पावे। आप उनके लिये खाने की व्यवस्था कीजिये। दूध आप तब पिलाते हैं, जब कि वे अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। अगर वही दूध आप पहले पिलाते तो अस्पताल में जाना ही नहीं पड़ता और खाना कपड़ा ठीक से मिलता, और मकान की व्यवस्था होती तो इतने बीमार पड़ते ही नहीं। इसलिये आज जो आर्थिक अव्यवस्था से हमारा समाज पीड़ित है, उस आर्थिक अव्यवस्था का इलाज होना चाहिये। उनकी बीमारी तो कुछ और है लेकिन उसका इलाज आप अस्पतालों में खोजते हैं, यह कौन सी बुद्धिमत्ता की बात है? इस सदन के अन्दर पढ़े लिखे लोग हैं, इस देश के अन्दर यूनिवर्सिटीज और कालेजों से डिग्री लिये हुए बड़े-बड़े आफिसर हैं लेकिन फिर भी सही दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखते। इससे मुझे बहुत बड़ा खेद है।

दूसरी बात यह कि यह बिलकुल सत्य है कि हमारे देश और प्रदेश में दवाइयां अस्पतालों से बहुत बिकती हैं। मैंने कई बार इस संबंध में हेल्थ मिनिस्टर से रिपोर्ट की और अगर माननीय प्रताप सिंह जी ने इस प्रकार की चोरियों को बन्द कर दिया है तो वे बधाई के पात्र हैं और आगे भी बन्द कर देंगे तो मैं उनको ऐडवांस में बधाई देता हूं। वरना उनका भी वही हश्र होगा जो आज तक हुआ और उससे बड़ा दुःख और अफसोस होगा।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

एक माननीय सदस्य ने नर्सेज के संबंध में कुछ कहा। आखिर हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा मेडिकल डिपार्टमेन्ट है, उनको देखना चाहिये कि हर एक के साथ इंसानियत का बर्ताव होना चाहिये। लेकिन आज जो उनकी इन्चार्ज हैं उनका ट्रीटमेंट नर्सेज के साथ अच्छा नहीं है। वे उनके साथ इंसानियत का बर्ताव नहीं करतीं, उनको डांटती फटकारती हैं। इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया कि नर्सेज के मकान पर पत्थर तक फेंके गये। मैं कहता हूं कि इस प्रकार का आफिसर ऐडमिनिस्ट्रेशन में रखने के काबिल नहीं है जो अपने सबॉर्डिनेट को प्रोटेक्शन न दे सकता हो। उसे नौकरी में रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य इसे डिफेंड नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार की लापरवाही और इस प्रकार के कारनामे इस प्रदेश के अन्दर होते हैं तो लानत है जो इस प्रकार के व्यवहार को टालरेट किया जाय। जिस देश में पढ़े लिखे लोग हों, उस देश के लोग इंसानियत से गिरी हुई बात करें, इंसानियत से गिरा हुआ बर्त्ताव करें तो यह ठीक नहीं है। चाहे वह हिन्दुस्तान की डिग्री प्राप्त किये हों या बाहर के किसी देश की डिग्री प्राप्त किये हों, सब बेकार है। और दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि आपकी जो दवायें अस्पतालों को जाती हैं वे महीनों तक आपके सेंट्रल स्टोर्स जो जिलों में हैं उनमें पड़ी रहती हैं और उधर गरीबों को दवा समय पर नहीं मिल पाती हैं। इसको देखने की जरूरत है। पैसा खर्च किया गया, दवायें जिले में भेजी गईं और वे यदि जरूरत पर न पहुंचे तो फिर उनके भेजने का क्या फायदा है? इस पर ध्यान देना चाहिये।

मेरी फल कालेज की बात बहुत ही बुद्धिमत्ता से देखने की है कि हमारे मुल्क का विकास किस सीढ़ी पर है। इस सदन में पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि हमने भाषण दे दिया तो हमने मुल्क का बड़ा भारी काम कर दिया। वास्तविकता से बहुत दूर काल्पनिक बात रखना कोई सराहना की बात नहीं है। यह तो मुल्क का समय जाया करना है, नष्ट करना है और मैं समझता हूं कि वस्तुस्थिति को देखते हुये काम करना चाहिये। आज हमारे विभागों की हालत यह है कि सब बेलगाम चल रहे हैं उनके रोकथाम करने की जरूरत है क्योंकि हमें बताया गया और हमने देखा भी कि जब इक्विपमेंट और फर्नीचर साल डेढ़ साल पुराना हो गया तो फौरन उसको रिप्लेस कर दिया गया। इस प्रकार का खर्चा इस गरीब मुल्क में इस पैमाने पर हो तो मैं समझता हूं कि यह हम लोगों को शोभा नहीं देता है। पढ़े लिखे लोग चाहे मिनिस्टर साहब हों, डाक्टर साहब हों, चाहे बड़े से बड़े अधिकारी हों। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूं, मैं कोई पार्टी पोलिटिक्स की बात नहीं करता, यह तो स्वास्थ्य की बात है। क्या इसकी जरूरत कम्यूनिस्ट को न हो है, कांग्रेस को नहीं है और कौन ऐसा राजनैतिक दल है जिसको स्वास्थ्य की जरूरत न हो? यह स्वास्थ्य का बजट है इसमें पार्टी फ्रिक्शन की बात नहीं होनी चाहिये। जहां तक इंतजाम करने की बात है, जहां तक करप्शन की बात है और जहां तक एफीशिऐंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इसमें कोई दो रायें और दो मत नहीं हो सकते है और जो दो राय रखता है, मैं कह सकता हूं कि वह इंसान नहीं है। वह अपने को धोखा देता है, मुल्क को धोखा देता है और अपने प्रति और मुल्क के प्रति अन्याय करता है।

इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने कई डाक्टरों को देखा है कि वे बड़े एसेंट्रिक होते हैं। उनसे कोई बात करो तो १०/१५ मिनट तक समझते ही नहीं हैं। न जाने उनका दिमाग कहां चला जाता है। इस तरह के लोगों को जिले के चार्ज में रखना नादानी है और बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। भले ही आप उनको बड़ी-बड़ी तनख्वाह दीजिये। लेकिन जिले के चार्ज में मत रखिये। जिले के चार्ज में रखने के माने मुल्क के साथ धोखा है। इसलिये ऐसे लोगों को न रखा जाय। नर्सेज की तरफ ध्यान दीजिये। उनको ५/१० साल से टी० ए० नहीं दिया गया। एक-एक नर्स को एक-एक महीने में ४ दफा ८० मील की दूरी पर तबादला किया गया। उसके सात बच्चे और वह कहां-कहां मारी-मारी फिरे। उसको एडवांस टी० ए०

को नहीं दिया गया और उसको परेशान किया गया। एक नहीं बिल्क सारी नर्सेज रोती हैं, गाली देती हैं और परेशान हैं। इसलिये जो इंचार्ज हैं उनको करेक्ट करना चाहिये। हम देखेंगे कि कौन सी सरकार है जो इस व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती। हम इनएफेक्टिव नहीं हैं। हम किसी के रुपये पैसे से नहीं आये। जनता का विश्वास लेकर इस सदन में मुल्क के साथ न्याय करने बैठे हैं। इसलिये बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूं कि मुल्क के साथ ज्यादती होने से रोकना चाहिये।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं इस सम्बन्ध में अपने विपक्ष के साथियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने रखा है वह बिलकुल निरर्थक और निराधार है। यह एक ऐसी समस्या है, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा, कि अच्छा राज्य तो वही है जिसमें कोई बीमार ही न पड़े। कभी स्वास्थ्य खराब ही न हो। लेकिन यदि पिछली सरकार का ध्यान न गया हो और देश में जनता बीमारी और भूख से पीड़ित हो, तो उसके लिए जो धनराशि माननीय मंत्री जी ने मांगी है वह कम ही है। वह ज्यादा होनी चाहिये थी। इस लिये मैं इस बजट का समर्थन करूंगा। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान उन अस्पतालों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनका थोड़ा बहुत जाल हमारे प्रदेश में बिछा हुआ है वैसे उनकी संख्या बहुत कम है।

(इस समय १ बज कर ५७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुए।)

मैं देहात का रहने वाला हूं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक घंटे में चार सौ बच्चे पैदा होते हैं। शहरों में एक एक फर्लांग पर दस डाक्टरों की दूकानें होती है। देहात में एक पंचायत क्षेत्र में ७--८ हजार की आबादी होती है। वहां ८ हजार आदमियों के लिये एक भी अस्पताल नहीं। वहां पर हर पंचायत क्षेत्र में एक अस्पताल खुलना चाहिये। अगर कहीं-कहीं अस्पताल खुल भी गया है तो उनमें बड़ी दुर्व्यवस्था है। मैं नवाबगंज क्षेत्र से आया हूं एक रोज रात को मैं अस्पताल में पहुंचा। मैंने देखा जहां मरीज रहते हैं कोई बल्ब नहीं जल रहा था। रात के साढे नौ बजे का वक्त था। वहां पर चारपाइयों की कमी थी। दो चार मरीज जमीन पर लेटे हुये थे। मैंने डाक्टर से पूछा। उन्होंने कहा कि बल्ब बहुत दिनों से नहीं है। मैंने कहा आप अपने मकान से लगा दीजिये। वहां पर बल्ब लेकर लगाया। अच्छा खासा आदमी अंधेरे में सोना अच्छा नहीं समझता। बीमार आदमी के लिये तो और जरूरी है। दवाइयों का स्टाक नहीं। लोगों से कह दिया जाता है कि बाजार से ले आओ। डाक्टर की बात तो बहुत बड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डाक्टरों की व्यवस्था नहीं हो पायी है ऐसी अनेकों डिस्पेंसरीज हैं। बीसों वर्ष से अस्पतालों में दुर्व्यवस्था है। न दवाइयों का, न डाक्टरों का इंतजाम है, न रोशनी और पानी की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से अब यह शासन नहीं चलना चाहिये और यदि वैसे ही चलता रहा तो यह भी शासन देश पर कलंक होगा जैसा कलंक अब तक देश पर छाया रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक आध बात और बतलाऊंगा—जहां तक फेमिली प्लानिंग की बात है, इस क्षेत्र में, फेमली प्लानिंग में हमारी सरकार ने रुपया पानी की तरह व्यय किया है। लेकिन हम फेमली प्लानिंग में मैंने देखा है कि जिन लोगों का वास्तव में आपरेशन होना चाहिये, जिन लोगों की वास्तव में नसबन्दी होनी चाहिये, जिन स्त्रियों के असलियत में लूप लगने चाहिये थे उनके नहीं लगे हैं। बल्कि किसी तरीके से खाना पुरी कर दी गयी है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों की नसबन्दी हुई है जिनके घर में स्त्री ही नहीं है अथवा ५०--६० साल की आयु वाले व्यक्तियों की नसबन्दी हुई है। यही नहीं बुरी तरह से अस्वस्थ,

[श्री चेतराम पचपेड़ा]

पागल और उन्मादी व्यक्तियों की नसबन्दी की गयी है और इस तरह से जनता को धोखा दिया गया है और जनता की मेहनत के पैसे का अपव्यय किया गया है। पैसे का इसमें बुरी तरह से दुरुपयोग किया गया है। मैंने जब फेमिली प्लानिंग के बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि नसबन्दी आदि इस लिये हो रही है कि खाद्य समस्या खराब हो गयी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि नसबन्दी, चकबन्दी और तुकबन्दी से खाद्य समस्या कैसे हल हो जायगी। यदि ऐसा कोई कानून बना दिया जाये जिससे बड़ी उम्र में लड़के लड़कियों के विवाह हों तो ज्यादा अच्छा होगा और इससे कुछ इसका हल मिल सकता है।

यह जो स्वास्थ्य रिपोर्ट सम्बन्धी पुस्तिका हम लोगों को मिली है उसके पेज १२ पर अंकित हैं, जितने भी डाक्टर हैं और नीचे के कर्मचारी हैं वह सब के सब पेड होंगे, उनको सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती ही होगी। तो मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिनको आपरेशन करने के लिये या नसबन्दी करने के लिये अस्पताल में लाया जाता है उनसे डाक्टर बताता है कि तुमको इस कार्य के लिये १० रुपये मिलेंगे। इससे उक्त व्यक्ति चौंक जाता है और वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसमें कुछ धोखा है, कुछ चार सौ बीस है, क्योंकि यदि यह कार्य हमारे फायदे में है तो हमें १० रुपये का लालच क्यों दिया जा रहा है। जिसको १० वर्षों में कांग्रेस सरकार ने हर तरह से जर्जर कर दिया है उसको आप १० रुपये का लालच देकर नपुंसक बनाना चाहते हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि डाक्टरों के लिये जो ५ रुपया हर आपरेशन पर प्रबन्ध किया गया है, इससे वह तो राजा हो जायगा क्योंकि ४–५ आपरेशन वह नित्य कर देता है यह इनाम इन डाक्टरों को क्यों दिया जाता है? क्या उसको सरकार से तनख्वाह नहीं मिलती है? इसी तरह से २ रुपया आने जाने का देते हैं, १ १/२ रुपया सहायक को देते है और इसी तरह का कुछ पैसा प्रेरक को जो ग्राम सेवक आदि होता है उसको दिया जाता है, यह सब ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सरकार से तनख्वाह मिलती है। तो इस कार्य के लिये उनको अलग से तरह तरह की राशि क्यों दी जाती है? इस तरह से जो २९–३० रुपये का इस कार्य पर खर्च दिखाया जाता है वह बेकार नहीं है तो क्या है?

(लाल बत्ती होने पर)

अभी तो मैंने बोलना शुरु किया और आपने श्रीमन्, लाल बत्ती कर दी। अभी मुझे बहुत बोलना है। मुझे कई बातें कहनी हैं इस सम्बन्ध में। एक बात और अर्ज कर दूंगा कि इन कर्मचारियों को अलग से कोई राशि न दी जाये जिससे जनता के पैसे का अपव्यय न हो।

अभी अभी हमारे आचार्य लक्ष्मीरमण जी बोल रहे थे। उन्होंने यह माना कि मलेरिया उन्मूलन में लगे होने के कारण हम चेचक का उन्मूलन नहीं कर सके। हम टी० बी० पर कन्सेन्ट्रेट कर रहे थे इसलिये टाइफायड की ओर नहीं देख सके। इसका स्पष्ट कारण यह था कि आप धनाढ्य गुप्ता वर्ग के लोगों में मिनिस्ट्री का बटवारा करने में लगे हैं और ११ में से ७ अपने आदमी बना लिये और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज या ऐसे लोगों की ओर आपका ध्यान नहीं गया जिनकी ओर देखने वाला कोई नहीं है और इसी कारण आपको सरकार छोड़नी पड़ी और उस पक्ष में बैठना पड़ा। मैं जानता हूं कि आपने मलेरिया उन्मूलन किया चाहे आपके साफ किये मच्छड़ भी साफ न हुये हों।

मुझे अब चिकित्सा शिक्षण के बारे में कहना है। अभी मंत्री जी ने बताया है कि यह सरकार ऐसी प्रशिक्षण संस्थायें खोल रही है डाक्टरों के लिये, मिडवाइव्ज और नर्सेज के लिये। देहातों में ही प्रशिक्षण संस्थायें खुलनी चाहिये। अगर यह नहीं होगा तो डाक्टर लोग देहात में जाना पसन्द नहीं करेंगे और फिर यह प्रशिक्षण केन्द्र ज्यादा जनहित में नहीं होंगे। देहात की जनता उससे लाभान्वित नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार एक सुझाव और दूंगा कि क्योंकि डाक्टरों की काफी कमी है इसलिये बी० एम० बी० एस०, एम० बी० बी० एस, बी० आई० एम० एस० आदि में ५ साल की ट्रेनिंग देकर तब आप ऐप्वाइन्ट करते हैं। तो मैं सुझाव दूंगा कि जब तब डाक्टरों

की कमी पूरी न हो पाये भले ही थोड़ी देर के लिये हो यह शिक्षण केवल ३ साल के लिये या कुछ कम समय के लिये कर दिया जाय जिससे कि हम कम समय में ज्यादा डाक्टर्स निकाल सकें।

बैसे तो मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं लेकिन समय नहीं है इसलिये मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। इस बजट में १५ करोड़ रुपया है। चाहे इससे दूना रुपया लगा दिया जाय लेकिन सब व्यर्थ हो जाता है जब तक कि उन क्षेत्रों में जहां अछूत लोग रहते हैं, जहां मुसलमान लोग बहुत रहते हैं और जहां गन्दगी बहुत रहती है वहां पर अगर सफाई का प्रबन्ध नहीं होता। जब तक सफाई की ओर ध्यान नहीं जाता और जब तक चीजों में जो मिलावटें होती हैं, चाहे घी हो, तेल हो, कोई चीज मारकेट में लीजिये शुद्ध नहीं मिलेगी तब तक आपका सारा रुपया व्यर्थ है। इस शासन की ओर से इन चीजों के रोकने के लिये कड़े कदम उठाये जाने चाहिये। जिसके लिये २० वर्षों का कांग्रेस शासन कुछ नहीं कर सका उस ओर कदम अवश्य सख्ती से उठाये जाने चाहिये। अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मंगला प्रसाद तिवारी (जिला इलाहाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ की आबादी के लिये यह जो बजट पेश किया गया है उसमें जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जिन मित्रों ने बजट बनाया है उनके गले के नीचे वह नहीं उतरा क्योंकि जनसंघ के मित्रों का विश्वास नसबन्दी में नहीं है। वह बाहर प्रचार करते हैं कि इस बार गाय की पूंछ के बाद नसबन्दी का आन्दोलन ले कर चलेंगे, ऐसा वह बाहर कहते हैं। तो इस सरकार की जो सबसे बड़ी इकाई है उसका जब विश्वास किसी चीज पर न हो और वह बजट पेश हो और उस पर श्रद्धा प्रकट की जाय तो यह मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर आप इस प्रान्त के रहने वालों का कैसे भला कर सकते हैं ?

आपके सामने मैं अपनी बात कहूं कि जिला परिषद के जितने अस्पताल हैं उनके लिये हमने बार बार लिखा कि ए० एम० एस० या बनारस के आयुर्वेद की योग्यता प्राप्त लोग हैं उनको रखने की इजाजत दी जाय क्योंकि वहां पर छोट-छोटे डिस्पेंसरी खोलकर काम करना चाहते हैं लेकिन दुख की बात है कि सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सरकार का ध्यान उस ओर गया नहीं। होता यह है कि ८।। करोड़ की आबादी में प्रायः दो करोड़ की आबादी पर सारा पैसा खर्च होता है। ६ करोड़ आदमी तो अपनी आबहवा की वजह से और मेहनत की वजह से स्वस्थ रहता है। हमारे माननीय सदस्य ने बारबार यहां पर कहा कि २० साल की इन्तजाम में खराबी की वजह से यह नहीं हो पाया। मैं कहता हूं कि आप अपने चेहरे को देखिये, अपने दिमाग को देखिये और अपने परिवार को देखिये। आप एक छोटे परिवार के थे जो बड़े परिवार में आये हैं। आपने जो यह तरक्की की है यह कांग्रेस के २० साल के शासन में ही कमाई की है। जो ये बड़े अस्पताल खुले हैं, बड़ी संख्या में लोग जर्मनी गये हैं और विदेशों में गये हैं जिन्होंने आकर देश का भला किया है यह सब कांग्रेस सरकार का ही जमाना था। आप बड़े परिवार में होकर एक गैर जिम्मेदार बच्चे की तरह से बात कहते हैं यह बात करने और काम करने का ढंग नहीं है। इससे उत्तर प्रदेश का अधिक भला नहीं होगा।

एक बात स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहूं कि पहाड़ों पर भी बीमारी होती है जब कि वहां पर आबादी घनी नहीं होती है। यहां पर मैदान में घनी आबादी है। जो आवश्यकता की चीजें हैं उनकी भी कमी है। खाने की भी कमी है। तब भी इस बजट के अन्दर उन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। आप किसी भी अस्पताल में जाइये वहां पर रोगी को क्या खाना मिलता है और किस तरह का पानी मिलता है और कैसी व्यवस्था है यह सब आपको मालूम हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मंगल प्रसाद तिवारी]

जायगा। मैंने देखा है कि एक अस्पताल में एक हैजे का रोगी नीचे रखा हुआ पानी पी गया और उस तरफ तवज्जह नहीं दी गई। आप कहते हैं कि अपस्ताल में जाकर देखिये कि कितना सुधार हो गया है। डाक्टर साहब बड़ी सावधानी से आने लगे है। यह सब थोथी बातें हैं। एक हजार रुपया पाने वाला डाक्टर भी उस तरह से अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है जिस तरह से उसको करना चाहिये। क्या वजह है कि लखनऊ में डाक्टर बाहर प्रैक्टिस करता है और सरकारी नौकरी में आना पसन्द नहीं करता। पढ़े लिखे लोगों के ढंग में परिवर्तन होना चाहिये। यह सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की व्यवस्था की बात है।

मैं अपने जिले की बात करता हूं। मेरी तहसील में जिला परिषद् का एक अस्पताल है। हमने इस बात की कोशिश की कि कोई डाक्टर वहां पर चला जाय। न तो सरकार ने इस बात को मन्जूर किया कि कोई डाक्टर वहां भेजें और न किसी डाक्टर ने देहात में जाना पसन्द किया। जो वहां पर लगा वह भी छोड़ कर चला गया। अपना इस्तीफा उसने दे दिया। इसलिये सरकार देहातों के लिये कुछ सुविधा अवश्य दे जिनकी आवश्यकता देहात के जीवन के लिये जरूरी है। जो वहां का इस समय ढंग है उसको बदलिये तभी वहां का जीवन चल सकता है।

मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि आपने जो मर्दुमशुमारी में गणना लिखी है वह गलत है। इसका ठीक ठीक हिसाब नहीं लगाया गया कि चेचक से देश में कितने बच्चे मरे हैं और टीका लगाने के लिये कितने आदमी नियुक्त किये गये हैं। आज भी उनके आंकड़े गलत हैं। २॥ महीने की सरकार ने भी यह देख कर इसको ठीक करने का प्रयास नहीं किया। हालत यह है सैनीटरी इन्सपेक्टर ३ रुपये लेकर लाइसेंस देता है। जिस उत्तर प्रदेश के रहने वालों को ठीक करने की बात है यहां का आदमी तो मिट्टी खाकर जी लेता है। सरकार क्या उनकी मदद कर सकती है। उधर से बड़े घमंड के साथ कहा जाता है कि बड़ा सुन्दर बजट है। क्या इस बजट से उत्तर प्रदेश के रहने वालों का पेट भर जायगा? चाहे आप गढ़वाल के रहने वाले हों, चाहे बस्ती के रहने वालों हों और चाहे मध्य के रहने वाले हों आपको सोचना पड़ेगा कि आप इन्सान की जिन्दगी को अच्छी बनाने के लिये अस्पताल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं और उसमें अधिक पैसा लगा रहे हैं जिससे यहां के आदमी उन्नति कर सकें और ब्रह्मचर्य धारण करके अपना जीवन बढ़ा सकें। जिससे आदमियों के जीवन में कुछ फर्क आ सके। मैं देखता हूं कि आज लोगों का जीवन विलासपूर्ण बनता जा रहा है। ऐसा जमाना नहीं रहा कि आदमी मर्ज से पीड़ित न हो।

आज मंत्री जी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा दौरा करते हैं और चाहते हैं कि विरोधी भी उनकी तारीफ करें। हम उन की तारीफ इसलिये नहीं करते कि अभी हमने आप की चाल नहीं देखी है, अभी आप का ढंग हमने नहीं देखा है। जब आप की चाल, आपका ढंग, आप का काम हमारे सामने आ जायगा तब हम आप की तारीफ करेंगे। अढ़ाई महीने के बच्चे की तारीफ करने की कोई गुंजायश नहीं है इसलिये कि कहीं ऐसा न हो कि आप कल ही चले जायं। उत्तर प्रदेश के आदमियों की लाशें रोज आप को सड़क पर पड़ी दिखायी देंगी। नदियों में लोग लाशें बहा देते हैं। तो इन छोटी-छोटी बातों को आप को देखना होगा। उसे सुधारने की व्यवस्था करने से ही इस प्रदेश का भला होगा। अगर लखनऊ में मेडिकल कालेज की इमारतों में आपने दो इमारतें और बढ़ा दीं तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमारे प्रदेश में मुर्दे बहाने की प्रथा है, चेचक से मरे व्यक्ति को न लिखने की आदत है। इसे आप को रोकना चाहिये। आपको ज्यादा से ज्यादा दवाइयां देहात में भेजने की व्यवस्था करनी चाहिये। डाक्टर लोग अच्छी दवाइयां तथा चीजें मिनिस्टर साहब तथा बड़े लोगों को ही देते हैं। यह दवाइयें गरीबों के पास भी पहुंचनी चाहिये। संसार के बाजार में मेडिकल एसोसियेशन में आप की जगह कहां है इसे आप देखिये। आप यह दावा नहीं कर सकते कि आप प्रदेश के किसी एक क्षेत्र को पूरे का पूरा दवाइयों से सेचुरेट कर देंगे। मुझे पता लगा है कि चेचक से मरे व्यक्ति की लिखा

कड़ी नहीं होती। जो किसान दस घंटे काम करता है, उसे आप कितनी दवाई देते हैं। मजदूर को आप कितनी दवाई देते हैं। वे लोग भी आपको टैक्स देते हैं। आप का यह बटवारा बिलकुल गलत है। मैं बजट की स्कीमों में नहीं जाता, लेकिन आप तो बड़े समाजवादी हैं। कहते थे कि अगर हम राजा हो जायंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन इधर से उधर होते ही इतना फर्क पड़ गया जो आदमी जिन्दगी में दस रुपये की भी दवा न पाये वह भी इस उत्तर प्रदेश में रहता है और उसका नेता सेक्रेटेरियेट के बगल में स्पीच झाड़ देता है और उसको अच्छी से अच्छी दवाइयां उपलब्ध हो जाती हैं। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें। जो यहां का रिक्शा चलाने वाला है उसके लिये दवा की कोई व्यवस्था नहीं है। आज मिडिल क्लास का आदमी ही सारी की सारी दवा खा जाता है और दुहाई देता है कि वही प्रदेश को आगे ले जाने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मोटर छोड़े, घोड़े पर, पैदल घूमें, पहाड़ और गांव को देखें और फिर देखें कि यहां का आदमी खाने बिना मरता है अथवा दवाई बिना। अगर आप यह करेंगे तो भले ही हमने बीस साल में बड़ा पाप किया है, लेकिन ढाई महीने में आप एक भी पुण्य न कर सकें यह कोई शोभा की बात नहीं है। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि सोचिये, ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात करने से अधिक लाभ नहीं होगा। आज व्यूरोक्रेसी के जमाने में हर आदमी सोचता है कि ४ पैसे के बजाय ३ पैसे में मेरा कोई काम कर दे चाहे दूसरा मर जाय। तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि बुड्ढा आदमी रिक्शा नहीं चलायेगा, बच्चा ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़े। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की उस अपील का उत्तर देने जा रहा हूं जो उन्होंने सदन में की कि कोई सदस्य उनके स्वास्थ्य सुधार आन्दोलन में जो भी चन्दा देना चाहे वह दे दें। मेरा सीतापुर जिला है और लहरपुर कांस्टीटुयेंसी है। मैं बतलाना चाहता हूं कि मेरे यहां ३० मील तक महिला अस्पताल नहीं है। अगर वहां आप महिला अस्पताल खुलवा सकें तो १० हजार रुपया और बिल्डिंग का आवश्यक प्रबन्ध वहां करवा देंगे।

मैं समझता हूं कि मंत्री जी के सामने उत्तर प्रदेश के अन्दर स्वास्थ्य सुधार की कल्पना इतनी व्यापक है और उनमें उत्साह है कि १५ करोड़ क्या और भी अधिक अगर होता तो बहुत जल्दी उनके हाथ मजबूत होते और वह अपनी कल्पना पूरी कर सकते। लेकिन मैं उनको बधाई देता हूं कि सीमित साधनों में भी उन्होंने इस सदन में जो घोषणाएं की हैं वह कांग्रेसी बादशाहत में कभी नहीं हुई—बजट उठा कर देख लीजिये। वास्तव में शासन नहीं था बादशाहत ही थी। मंत्री जी ने इस प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दृष्टिकोण बदल दिया और डाक्टरों का दृष्टिकोण बदलने का प्रयास किया। जो डाक्टर शहरों में जाना चाहते थे, अब इन्होंने प्रेरणा कर दी कि ३ साल तक देहातों में रह कर वहां क सेवा करो और उस नजरिये को उन्होंने बदलना शुरू किया। मैं स्वास्थ्य विभाग के आदमियों को भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि प्रदेश के स्वास्थ्य जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, एक एक भ्रष्ट कर्मचारी को सजा देंगे और ईमानदार लोग जो सेवा करने के लिये तैयार होंगे उनके अन्दर एक नया उत्साह पैदा होगा कि हम जनता की सेवा करने के लिये आये हैं, नौकरी करने और मौज उड़ाने के लिये नहीं आये। तो ये घोषणाएं जो उन्होंने की हैं वह सम्मिलित सरकार की अनमोल देन हैं। उन्होंने पर्वतीय और पर्वी जिलों में एक एक स्कूल खोलने की व्यवस्था की है ताकि डाक्टरों की कमी पूरी की जा सके। अभी तक कांग्रेस की बादशाहत में यह कभी दिमाग में नहीं आता था कि कहीं झोपड़ियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बिपिन बिहारी तिवारी]
में भी अस्पताल खोले जा सकते हैं, प्रदेश को, देहात को जनता को दवाई दी जा सकती है, लेकिन उनके दिमाग में आयी। उन्होंने मोबाइल ट्रेवलिंग अस्पताल की योजना बनायी जिससे देहात के लोगों को बड़ा फायदा होगा।

(व्यवधान)

इस बौखलाहट से आपका और पतन हो जायेगा।

एक सदस्य--

पतन तो आपका होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया आपस में बातें न करें।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी--

उपाध्यक्ष महोदय, इनको इन गांधी जी की तस्वीर को देख लेना चाहिये और उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर आज बड़ा उत्साह है। सरकारी कर्मचारियों के अन्दर भी आज बड़ा उत्साह है और बहुत जल्दी ही प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य सुधरेगा और आर्थिक स्थिति भी संभलेगी। (व्यवधान) मुझे खुशी है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन जन उत्साह पैदा करने वाली योजनाओं को सदन के समक्ष रखा है, किन्तु मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है। हमारे प्रदेश में कुष्ठ रोग बहुत बढ़ रहा है। लखनऊ में चारबाग स्टेशन की तरफ चले जाइये, तमाम व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, भीख मांगते दिखाई देंगे। यह ऐसा रोग है जो बड़ी तेजी से फैलता है। ऐसे रोग के लोगों के लिये अलग गृह निर्माण होना चाहिये और वे शहरों से दूर होने चाहिये। यह ऐसा संक्रामक रोग है जो बड़ी तेजी से फैलता है। सरकार ने इनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। अगर यह व्यवस्था आप नहीं कर पाये तो जनता का उत्साह कम हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों के लिये समुचित व्यवस्था की जाय।

गांवों में भेड़िये बहुत से बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। कभी जख्मी करके छोड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों के इलाज के लिये दवाई का अस्पतालों में मुफ्त प्रबन्ध होना चाहिये क्योंकि इसके इलाज की दवायें बड़ी कीमती होती हैं, ८०-८० रुपये की कीमत की होती हैं, गरीब उन दवाओं को खरीद नहीं पाता है और नतीजा यह होता है कि उनके बच्चे भों, भों करके मर जाते हैं। इसलिये इसके इन्जेक्शन्स का प्रचुर मात्रा में प्रबन्ध होना चाहिये।

सन् १९३८ में जब मैं पढ़ा करता था तो उस समय हमारा स्कूलों में वेट लिया जाता था। स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख की जाती थी। जब से कांग्रेस की बादशाहत हुई तब से वे चीजें खत्म हो गईं और उस शासन में बच्चों के स्वास्थ्य को नहीं देखा गया। अब इस सरकार द्वारा जिलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे स्कूलों में जाकर बच्चों को देखें। आपको पता होगा कि दांतों की बीमारी देश में बहुत फैली हुई है और उस ओर ध्यान जाना आवश्यक है। जहां पर महिला चिकित्सालयों की आवश्यकता है वहां महिला डाक्टरों की भी आवश्यकता है। आप अगर इस आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए लड़ाई के मोर्चे की तरह भर्ती करना शुरू कर दीजिए ताकि महिला डाक्टरों की कमी पूरी की जा सके। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में जो सिविल सर्जन होते हैं उनकी फीस १६ रुपये होती है। अगर किसी साधारण व्यक्ति को सिविल सर्जन की आवश्यकता होती है तो वे उनकी सहायता से वंचित रह जाते हैं। ऐसे डाक्टरों के संबंध में भी कोई नियंत्रण रक्खें ताकि उनकी पहुंच गरीब आदमी तक भी हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

श्री विपिन बिहारी तिवारी—

कृपया एक-दो मिनट बोल लेने दीजिए । जिलों में जो डाक्टर्स होते हैं उनको तीन घण्टे चिकित्सा का और ६ घण्टे क्लैरिकल काम करना पड़ता है । मैं कहता हूं कि उनसे क्लैरिकल वर्क ले लीजिए ताकि वे चिकित्सा का कार्य कर सकें । इन शब्दों के बाद मैं चाहता हूं कि कांग्रेसी भाई संविद सरकार को मजबूत करें और मजबूत करके इस प्रदेश में अपनी आंखों से सम्पन्नता को देखें । कांग्रेस सरकार जो काम बीस साल में नहीं कर पाई वह संविद सरकार अढ़ाई महीने में करके दिखा रही है । जो वातावरण इस सरकार में मेहनत और ईमानदारी का तैयार हुआ है उसके आधार पर हम इस प्रदेश से दुख और दैन्य दूर कर सकेंगे और सम्पन्नता को ला सकेंगे यह हमें ईश्वर का आशीर्वाद है और आपके सहयोग से कर सकेंगे ।

*श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । जिस समय मेरे मित्र प्रतापसिंह जी, जो इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं, अपना भाषण दे रहे थे उनको पहले शिकायत थी कि उनके कामों की और उनकी कलाबाजियों की कोई तारीफ हमारी तरफ से नहीं की गई । मान्यवर, वे मुझसे छोटे हैं । मैं उनसे मुहब्बत भी करता हूं और उनकी हर अदा को देखता जाता हूं । मैंने बहुत चाहा, कि मैं अपने भाई को, अपने मित्र को मुबारकवाद दूं, परन्तु मान्यवर, उनके हर काम में मुझे बचकानापन महसूस हुआ । मैं कहता हूं कि उनके मिनिस्टर होने के बाद भी बचकानापन महसूस हुआ तो बधाई किस बात की । मुझे उनसे बड़ी आशा थी । वे बांदा तशरीफ ले गये जहां कोई दवाओं का स्टाक बरामद हुआ और जिनके लिए कहा जाता है कि वे डैड मेडिसिन्स हैं । पर एक बात है कि प्रेस पब्लिसिटी के बारे में जितने भाई प्रतापसिंह जी होशियार साबित हुए उतना और कोई मिनिस्टर नहीं हुआ, आपने कौन सी तब्दीली की ? मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में जो कदम आप उठायेंगे उसमें हमारी ओर से हमारी पार्टी की ओर से आपको पूरा समर्थन पहुंचेगा । यह बचकानेपन की बात कि कहीं २ शीशी पकड़ ली, कहीं कहीं ३ शीशी पकड़ ली, या १५ पैसे पकड़ लिए, यह कोई बहुत ज्यादा तारीफ की बात नहीं है । अगर वह संजीदगी से काम करें तो मुझे बधाई देने का मौका मिलेगा ।

मान्यवर, यह किताब मैंने तो छपवाकर बंटवाई नहीं है । यह प्रतापसिंह जी ने ही बांटी है । इसमें जो प्रगति लिखी है वह कांग्रेस सरकार के जमाने में हुई है, कम हुई या ज्यादा हुई । मान्यवर, मैं क्या बताऊं, एक नया शौक पैदा हो गया । अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना । मुझे बेहद तकलीफ हुई जब माननीय चौधरी चरणसिंह जी ने कहा कि २० साल में कांग्रेस के जमाने में जो कुछ हुआ वह उन्हीं की वजह से हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार की जितनी नीतियां हानिकारक संपादित हुई वे सब उन्हीं की वजह से हुईं । आपने कहा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में बताया जायगा । आप यह कहेंगे कि मैं कांग्रेस में था, इनइफेक्टिव था, मेरी चलती नहीं थी, इम्पोटेंट था, कोई मेरी सुनता नहीं था । यदि ऐसा था तो उनका स्वाभिमान कहां गया था ? अगर उनकी नीति नहीं चल पाती थी तो स्वाभिमान का तकाजा था वह उसी समय कांग्रेस छोड़ देते । अब २० साल कांग्रेस से फायदा उठाकर उसे अब छोड़ने पर मुझे बड़ा ताज्जुब है ।

एक भाई ने कहा कि इनफैक्शस बीमारों को, जैसे कोढ़ी वगैरह हैं, उनको सन्तान उत्पत्ति रोकी जाय । मैं भी चाहता हूं कि ऐसे मरीजों के सन्तान नहीं होनी चाहिए । एक भाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्शोधन नहीं किया ।

[श्री मथुराकिशोर]

ने कहा कि मिनिस्टर के लड़के डाक्टर हो जाते हैं, प्रतापसिंह जी के भाई डाक्टर हो जाते हैं लेकिन किसी किसान का बेटा कैसे डाक्टर होगा। मुझे पता नहीं है कि प्रतापसिंह जी ने इस संबंध में क्याकिया है। इतना मुझे मालूम है कि ५ सीटें कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण भाइयों के लिए रिजर्व की थीं।

मलेरिया, हैजे वगैरह की बात प्रतापसिंह जी ने कही। एक भाई ने कहा कि पहले जिंदगी का औसत २३ साल था और अब ५० होगया है। उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं लगती है कि आपने अंग्रेजों के जमाने की बात कह दी। कहा कि जेल गये थे हालांकि जेल का दरवाजा तक उन्होंने नहीं देखा।

प्रतापसिंह जी एक होनहार व्यक्ति हैं। वह मिनिस्टर हैं। एक किस्सा है कि देहात से एक आदमी लखनऊ पहले पहल आया। उसने यहां पार्क देखे, यनिवर्सिटी देखी, असेंम्बली देखी और एक गन्दा नाला भी देखा। जब वापस पहुंचा तो कहा कि वहां तो गन्दा नाला ही है और कुछ नहीं है। ऐसी ही बात प्रतापसिंह जी ने कही। मैं चाहता था कि वह सारी बात कहते।

उन्होंने तबर्रा पढ़ा मेडिकल कालिज का कि वहां फेवरिटिज्म, नेपाटिज्म और सारी खराब बातें हैं। टीचर्स का जिक्र किया लेकिन एक भी प्रोफेसर का नाम नहीं बताया कि कौन इन्टरनेशनल फेम का है जो पोलिटिक्स में आ गया है। जब पिछली दफा प्रतापसिंह जी असेंबली के मेम्बर थे तो यूनिवर्सिटी आटोनामी की बड़ी दुहाई दिया करते थे। कहां गये आपके वे उसूल अब? सवाल यह है कि यह मेडिकल कालेज सिर्फ अस्पताल ही नहीं है। वह एक टीचिंग इन्टीट्यूशन है जहां मेडिकल स्टुडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। सवाल यह है कि यह संस्था जो ४०, ४५ साल की हो चुकी है और जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का इंटीग्रल पार्ट है उसे यूनिवर्सिटी से हटाया जाय या नहीं। मेरे भाई ने कहा कि हैलेट और हेग के जमाने में भी यह बात उठी थी। मैं मान सकता हूं कि चौधरी चरणसिंह जी को या प्रतापसिंह जी को किसी, १, २ डाक्टर से नाराजगी हो सकती है। मगर उसके कारण तमाम कालेज को हटा लिया जाय, कोई अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, मैं कुछ थोड़े से दूसरों के विचार पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो इसमें माहिर हैं। १९४४ में मिनिस्ट्री आफ हैल्थ, यूनाइटेड किंडम की एप्वाइन्ट की हुई एक गुडएनफ कमेटी ने लिखा है :—

The training of medical students on modern lines can be properly conducted only under the aegis of a university and in institutions that conform to university standards in respect of staffing, accommodation, equipment and other arrangements.

मेडिकल स्टुडेंट्स की ट्रेनिंग ऐसी संस्था में हो जो यूनिवर्सिटी का अंग हो तथा ऐसे इंस्टीट्यूशन्स में जहां स्टाफ वगैरह यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड का हो।

Every medical school should be a university medical school in the sense that it is an integral part of a university.

हरेक मेडिकल कालेज को यूनिवर्सिटी का अंग होना चाहिए।

To agree to the training of medical students in institutions which are not parts of universities is to support the belief that doctors can be produced in intellectual circumstances that are not the best that the community provides.

यह मानना कि मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग ऐसी संस्था में भी हो सकती है जो यूनिवर्सिटी के अंग नहीं हैं ऐसे ही होगा कि डाक्टर ऐसी दशा में भी बन सकते हैं जो कि सबसे अच्छी नहीं है जो कि

कम्युनिटी प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद और भी कई हैं जिनका मतलब यह है कि इंगलैंड और अमेरिका में जो मेडिकल टीचिंग इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनमें कोई ऐसा नहीं है जो यूनिवर्सिटी का हिस्सा न हो।

This principle has met with world-wide acceptance. A World Health Organisation publication, 'The World Directory of Medical Schools' (1957), shows that in almost every country medical education is now conducted under the aegis of universities. The presence of a medical school within a university benefits both the school itself and the other faculties.

In U.S.A. the position from the very start has been that the medical schools and colleges have been university institutions, and the question of reviewing the mode of their control has never arisen.

हर जगह मेडिकल स्कूल्स यूनिवर्सिटी के हिस्से हैं। इसी मेडिकल कालेज के बारे में जिसके अन्दर प्रतापसिंह जी ने इतनी बुराइयां बताई हैं, १९४३ में एक मोर कमेटी बैठी थी और उसने यह कहा कि हिन्दुस्तान के बैस्ट इन्टीट्यूशन्स में यह एक है और उसकी एक वजह यह भी है कि इसके ऊपर कंट्रोल यूनिवर्सिटी का है। मान्यवर, १९५३-५४ में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने देश के कुछ मेडिकल कालेजेज को अपग्रेड करने का तय किया कुछ विषयों में और देश के १८ कालेजों में से इस कालेज के पैथोलाजी व फारमैकालाजी डिपार्टमेंट्स को अपग्रेड करने का तय किया क्योंकि स्टाफ की क्वालीफीकेशन्स और रिसर्च वर्क तथा भविष्य के हिसाब से उन्होंने यह उचित समझा। यही नहीं, १९५९-६० में भी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो मुदालियर कमेटी बैठायी थी उसने भी यह सिफारिश की कि इन कालेजेज में रिसर्च पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर्स स्थापित किए जायं। इसके अलावा १९६५ में जो सर्वे यूनिट आफ इन्डस्ट्रियल रिसर्च कायम हुई उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है--

The research activity at the K.G. Medical College was one of the highest in the country and this was one of the colleges which had published the largest number of papers during the last ten years.

इस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा पेपर्स पिछले दस सालों में प्रकाशित किए हैं। उन्होंने यह भी कहा है --

In the matter of education and research it has been one of the best in the country.

देश में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बाद यह सबसे पुराना मेडिकल कालेज है।

एप्वाइन्टमेंट के बारे में शिकायत की गयी। लेकिन एप्वाइन्टमेंट के बारे में स्टेट्यूट्स बने हुए हैं और सेलेक्ट कमेटी बनी हुई है। जहां तक डेफीसिट की बात है उसके बारे में भी मेरा कहना यह है कि बोर्ड आफ मेनेजमेंट के अन्दर गवर्नमेंट के ८ नामिनी हैं। इसके अलावा दफा ७ यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अनुसार गवर्नमेंट को बहुत सी पावर्स हैं, उनके अनुसार वे जो चाहें कर सकते हैं। माननीय चरणसिंह जी ने एक दलील यह दी कि आगरा और इलाहाबाद के मेडिकल कालेजों को यूनिवर्सिटीज से क्यों अटेच नहीं किया गया। अगर वह यह कहते कि उनमें यह कमी है तब तो मैं उनकी इस बात को मान लेता और उनकी इस बात का समर्थन करता कि उनको भी विश्वविद्यालयों से अटैच कर दिया जाय और उनका वह कदम एक डेमोक्रेटिक कदम होता। लेकिन उनकी यह बात समझ में नहीं आयी कि उनका बहाना लेकर इसको भी यनिवर्सिटी से निकाल लिया। अगर माननीय प्रतापसिंह जी अपनी तारीफ ही चाहते हैं तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वह भी कर सकता हूं लेकिन वह वाकई कोई तारीफ का काम करके दिखायें जिससे दिल से मैं उनकी तारीफ कर सकूं।

एक भाई ने यह भी कहा कि बजाय कटौती के हमको तो धनराशि ज्यादा करने के लिए प्रस्ताव रखना चाहिए था। मेडिकल की मद में जितना भी खर्चा किया जाता है हम चाहते

[श्री बचलकिशोर]

हूँ कि वह ज्यादा हो। हम चाहते हैं कि मेडिकल की हर योजना के अन्दर खर्च बढ़ाया जाय लेकिन यह जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है वह इसलिए किया है कि आप जो धांधलेबाजी कर रहे हैं, फासिस्ट तरीकों से जो आप जनतंत्र को पददलित करना चाहते हैं, उसका विरोध हो जाय। अगर आप हमें यह विश्वास दिला दें कि अब भी आप मे पुरानी भावनायें बाकी हैं, आपकी आत्मा का हनन नहीं हुआ है, तो फिर से इसके ऊपर सोचा जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ग्रांट सदन के सामने प्रस्तुत है वह ऐसी ग्रांट है जिसमें सरकार को कुछ मिलने वाला नहीं है। यह मैं मानता हूं कि पिछले कांग्रेस शासन में ये सब योजनायें बनीं और यह भी मानता हूं कि प्रदेश के हित के लिए मेडिकल कालेज की स्थापना हुई लेकिन उसके साथ ही साथ मैं यह भी मानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो उसकी दुर्व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं वे ठीक हैं और इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि इतने समय में हम लोगों ने क्या किया है। जो कुछ किया है वह बहुत काफी है लेकिन क्या आपको इस ढाई महीने के बच्चे पर अभी कोई दया नहीं आ रही है और २० साल तक जो आपने कारनामे किए हैं इस जगह पर बैठकर उनको ठीक करने की आप इतनी जल्दी उनसे कैसे आशा कर सकते हैं? जो कुशासन की बीमारी थी उसका तो इलाज कर के हमने आप को उधर बिठा दिया है, लेकिन सारे रोगों का तो इलाज हो गया है पर गद्दी छिनने की तड़पन की जो बीमारी है उसका इलाज करने में शायद मंत्री जी सफल न होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जनता को इस सरकार से पूरी आशा है कि २० साल के जटिल रोग को वह जल्दी से जल्दी दूर करेगी। आज अस्पतालों में जो बुर्दशा है वह पिछले समय से चली आ रही है और मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि वह इस मामले में स्वयं ही बहुत सचेत रहते हैं और बहुत दिलचस्पी से काम कर रहे हैं और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं, कानपुर में जो उर्सला अस्पताल है और जो मजदूरों का बीमा अस्पताल है उसमें जो डाक्टरों की आदतें पड़ी हुई हैं उनको सुधारने के लिए आप को कोशिश करना होगी। जो तबादलों की योजना मंत्री जी ने बनाई है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन उनकी जो यह बिगड़ी हुई आदतें हैं उनको सुधारने की आपकी जिम्मेदारी है। एक मजदूर को छुट्टी के लिए दो-दो, चार-चार रुपया रिश्वत देना पड़ता है और आज भी यह चीज जारी है।

अनेक सदस्य--

आज ऐसा क्यों हो रहा है?

श्री बाबू बदरे--

आज भी ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनकी आदतें २० साल से बिगड़ती चली आ रही हैं और वहां के डाक्टर समझते थे कि हमारे कोई न कोई परिवार के लोग मंत्री हैं ही और वह हमें बचा लेंगे लेकिन अब ऐसे लोगों और डाक्टरों के खिलाफ आशा है कि सरकार कार्यवाही करेगी और यह उनकी कोई मदद नहीं करने वाले हैं, अब उनकी जबरदस्ती आदत छुड़ाई जायगी। अस्पतालों में गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन अब जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा अपने भाषण में उससे आशा है कि गरीबों के लिए अब प्रबन्ध किए जायेंगे और प्रदेश का लाभ होगा। लेकिन उस सरकार ने जो योजना अस्पतालों की बनाई थी उसमें उन्होंने केवल बड़े बड़े लोगों का ही प्रबन्ध किया था और जितना रुपया वह खर्च करते थे उसका लाभ गरीबों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजाय पूंजीपतियों और बड़े लोगों को ही पहुंचता था। जब यह सरकार कुछ करना चाहती है गरीबों के लिए तो आप इनको हटाने की फिक्र में हैं। इस सरकार को हटाने के पक्ष में २ तरह के ही लोग हैं। एक तो वे लोग हैं कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के इल्जामात हैं और जो सोचते हैं कि अगर यह सरकार रह गई तो हमारे खिलाफ इन्क्वायरी और सख्त कार्यवाही होगी और जेल जाना पड़ेगा और दूसरे वह भ्रष्ट अफसर हैं जो गलत काम कर रहे थे उनको भी खतरा है और डर है कि हम सरकार की कार्यवाही से रगड़े जायेंगे। जो अस्पतालों की बिगड़ी हालत चली आती है उसको यह सरकार सुधारेगी और अब डाक्टरों को उस का डर भी पैदा हुआ है जो पहले जनता की बात को सुनते और मानते ही नहीं थे।

अभी एक माननीय सदस्य ने मंत्री जी की तरफ इशारा करके कहा कि वह लाल टोपी लगाकर बहुत दूर तक दौरा करते हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर उनको मंत्री जी की लाल टोपी पसन्द है तो वह भी खुद इस लाल टोपी को लगाकर बैठें उसमें मंत्री जी को कोई आपत्ति न होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सवाल इस बात का है कि २० साल के अन्दर जो अस्पताल के अन्दर दुर्व्यवस्था हुयी है, उसको सुधारने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने जो सुधार किए हैं, वास्तव में वे बधाई के पात्र हैं। उधर से कटौती का प्रस्ताव आया, आना ही चाहिए था लेकिन यह बात निर्विवाद है कि जिन-जिन चीजों को आप करना चाहते थे, उन-उनको करने में आप असफल रहे। यह विषय कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर आप पोलिटिकल स्पीच करें। जनता में प्रसन्नता है कि जो बातें कुर्सियों पर बैठकर आपकी समझ में नहीं आती थीं, वे उधर बैठने से आने लगी हैं। आपको चाहिए कि आप ठोस सुझाव दें और यदि वे जनहित में होंगे तो अवश्य माने जायेंगे और यदि केवल आपको आलोचना ही करनी है तो यह तो आप जब तक उधर बैठे रहेंगे, करते ही रहेंगे।

कानपुर में एक टी० बी० अस्पताल है। वहां के डाक्टर के रवैये से वहां के मजदूर बड़े परेशान हैं। वहां पर यदि बड़े आदमी की सिफारिश हो जाती है तो उस आदमी को भरती कर लिया जाता है। मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं होती। अतः माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस तरफ तवज्जह दें।

डाक्टरों के संबंध में कहा गया है कि उनकी कमी है लेकिन उसका कारण केवल यह है कि पिछली सरकार ने ज्यादातर जोर एलोपैथिक इलाज की ओर दिया है। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अब माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि जो लोग इनमें काम करेंगे, उनकी तरक्की होगी और ये इलाज भी प्रदेश में बढ़ाये जायेंगे, मुझे आशा है अब अवश्य ही डाक्टरों की कमी दूर होगी।

कानपुर के मेडिकल कालेज में जो प्रिंसिपल हैं, उनका इतना शासन है कि जितनी संख्या में वहां पर विद्यार्थी पास होकर निकलने चाहिए, उतने नहीं निकल पाते हैं। इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। इस सरकार को यह भी देखना चाहिए कि पिछली सरकार ने क्या-क्या किया है और इन्हें क्या करना चाहिए। यह बात सही है कि आप २० साल तक इस शासन में जमे रहे और २० साल के बाद आप हमें कहते हैं कि ये लोग ७-७ पार्टी के लोग एक कुनबा बनाये हुए हैं। यह बात सही है कि हम लोगों के दिमाग नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते लेकिन इस प्रदेश की जनता ने मांग की थी कि इस राज्य को अवश्य हटाना चाहिए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भले ही हमारे विचार न मिलते हों लेकिन दिल हमारे मिल रहे हैं और दिल मिला कर हम काम कर रहे हैं। आपको इसकी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए।

[श्री बाबू बदरे]

जहां तक नसबन्दी वाली योजना का संबंध है, उसके बारे में मैं निवेदन करूं कि हमारे जिले में कविता में इसे इस प्रकार कहते हैं :

"जमीन गयी चकबन्दी में,
मेहराऊ गयी नसबन्दी में
और देश गया गुटबन्दी में ।"

जिन लोगों को आवश्यता नहीं है उन लोगों की नसबन्दी की जा रही है । बहुत सी ऐसी योजनायें इस प्रदेश में चलायी गयी थीं क्योंकि इन्हें अपने परिवारों को पालना था । मजबूरी है अगर हम खर्च को कम करते हैं तो प्रदेश में बेकारी बढ़ेगी । इसलिए उन्हें निभाने की कोशिश कर रहे हैं । कानपुर में परिवार नियोजन के प्रचार के लिए जो रुपया खर्च होना चाहिए था वह वहां के जिलाधीश ने गलत तरीके से खर्च किया । इन योजनाओं में जो हमारा रुपया खर्च होता है, उसे माननीय मंत्री जी को देखना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त जो भी अधिकारी हैं उनमें अगर योग्यता है, बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर अच्छे अधिकारी हैं, तो बहुत सी समस्यायें वह खुद ही हल कर लेते हैं, लेकिन जो तानाशाह अफसर हैं वे राज्य का कितना बड़ा नुकसान करते हैं, जनता कितनी उन से पीड़ित हो जाती है उसी से ऐजीटेशन की भावना वहां पर बनती है । इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगर पिछले कुशासन के समय के भ्रष्ट अधिकारी हों और उनका आतंक हो तो उनको अपने विभाग से हटाइये अगर आप चाहते हैं कि आप का विभाग अच्छी तरह से चले । मुझ को मालूम है कि विभाग में डायरेक्टर साहब ७ साल से डटे हुये हैं, मैं समझता हूं कि उनको भी हटाने की कोशिश कीजिये । इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री राजाराम (जिला देवरिया)—

माननीय, बहुत देर से दोनों तरफ की बात सुनता रहा । सरकारी पक्ष से इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि इस वर्ष चेचक से मृत्यु हुई और उस का कारण बताया गया कि उस के पीछे जो लोग जिम्मेदार थे उन्हीं के ऊपर यह जिम्मेवारी आती है । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह जो अप्रैल का महीना है, जब गरमी शुरू होती है तो चेचक शुरू होती है, उसके बाद हैजा शुरू होता है बरसात में, और जाड़े में प्लेग होता है । मैं अगर कहूं कि पहली अप्रैल से जब से कांग्रेस सरकार गयी और आप का राज्य आया तभी से उसी के साथ चेचक भी शुरू हुई, तो गलत बात न होगी । आपने इस पर ध्यान नहीं किया क्योंकि एक तरफ तो आप के सामने जशन था, जनता के स्वास्थ्य की तरफ आप ने ध्यान नहीं दिया । जब से यह सरकार बनी तब से आंकड़े मिला लीजिये पिछले वर्ष के, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले वर्ष अप्रैल से जून के महीने में जितने लोगों की मृत्यु हुई या जितने प्रभावित चेचक से रहे हैं या जितने गांव में आग लगी है या जो ओले पड़े हैं, जो बरबादियां हुई हैं, आप देखेंगे कि उस के मुकाबले में इस अप्रैल से जून तक काफी मृत्युयें हुई अधिक लोग प्रभावित हुए हैं जब से आप ने भार सम्हाला है ।

एक भाई ने कहा कि हम १० हजार रु० की इमारत देते हैं । आप को मालूम हो कि देवरिया जिले में छितौनी के मजदूरों ने और सेठ योजक की तरफ से मिल कर १ लाख रु० का अस्पताल बना कर आप को दिया गया । लेकिन आप वहां पर डाक्टर नहीं दे सके । केवल ताली बजाने से काम नहीं चलता । माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि स्वास्थ्य का मसला है इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । अगर इस को लाइटली लिया जायगा तो काम नहीं चलने वाला है । फैमिली प्लानिंग की बात हुई, बड़ा जोर है आप की तरफ से । हम तो कहते हैं कि माननीय झारखंडेराय की खाद्य नीति ने ऐसे ही प्रदेश के सामने

एक समस्या पैदा कर दी है, जिस से लोगों का स्वास्थ्य गिर जायगा और वे बच्चा पैदा करने लायक ही नहीं रह जांयगे। मैं तो कहूंगा कि फैमिली प्लानिंग का पैसा कुछ उन गोलियों के बनाने में खर्च कीजिये, अगर खाना न मिले तो वे गोलियां दे दी जायं ताकि वह कुछ दिन जिन्दा रह सके।

आप कहते हैं कि इस विभाग में अब भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन हेल्थ ऐसिस्टेंट्स कैसे रखे जाते हैं। एम्पलायमेंट एक्सचेंज से रखे जाते हैं अथवा किसी नियम के अन्तर्गत रखे जाते हैं ? जिसको आप ओबलाइज करना चाहते हैं उनको आप डायरेक्ट भरती करा सकते हैं, इसीलिये शायद इसे रखा गया है। जितनी अनियमितायें इसमें है उतनी कहीं और नहीं है।

आपने कहा कि २/३ पहले इमारतों पर खर्च होता था और एक तिहाई दवाईयों पर लेकिन अब दो तिहाई दवाईयों पर खर्च होगा। लेकिन वे दवाइयां कहां खर्च होंगी। देहात में खर्च होंगी या शहर में खर्च होंगी ? आपने शहरी लोगों के लिये भूमि भवन कर माफ किया और ये जो दो तिहाई दवाईयां खर्च हो रही है वे किन अस्पतालों में खर्च हो रही हैं, १ से ५० मील तक देहात में कोई अस्पताल नहीं है। ब्लाक में प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम हैं लेकिन वहां कोई डाक्टर अथवा नर्स नहीं है। आप यह करते कि दो तिहाई जो दवाईयों पर आप रुपया खर्च करेंगे उन दवाईयों का दो तिहाई हिस्सा देहातों के अस्पतालों में खर्च होगा।

डाक्टरों की कमी की बात कही गयीं। मैं कहता हूं कि अपने प्रदेश में डाक्टरों की कमी नहीं है। अगर आप उनके ग्रेड अच्छे करके कुछ सुविधायें उनको दें तो आपको प्रदेश में ही अच्छे डाक्टर मिल जायेंगे। आप प्रदेश में ५०० डाक्टरों की कमी की बात कहते हैं, मद्रास से डाक्टर लाने की बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि प्रदेश में काशी विश्व-विद्यालय से जो ए०एम०एस० अथवा ए०वी०एम० एस० डिग्री होल्डर्स निकलते हैं वे एम० बी० बी० एस० के बराबर ही क्वालिफाइड हैं और मदरास सरकार ने उनको ईक्वली रिकगनाइज भी कर रखा है तो यहां भी वैसा ही क्यों नहीं किया जा सकता। अगर ए० एम० एस० और ए० बी० एम० एस० अथवा बी० एम० बी० एस० को एम० बी० बी० एस० के बराबर मानने को तैयार नहीं हैं तो आप रिफरेशर कोर्स दे सकते हैं और उनको बराबरी के स्तर पर ला सकते हैं।

नर्सेज की कमी की बात कही गयी। आप को चाहिये कि आप ९वीं अथवा १० वीं कक्षा में नर्सिंग की ट्रेनिंग देवें या जिसको रुचि हो उसे आप फिर रिफरेशर कोर्स दे दें और उसके बाद वह नर्सिंग में ले ली जाय तो इस तरह से नरसेज की कमी दूर हो सकेगी।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं क्योंकि अगर मैं नहीं कहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह स्वास्थ्य का मामला है प्रदेश के और जिस बात को मैं सोचता और देखता हूं अगर सदन के सामने वह न रखुं तो मुझे लगता है कि उससे प्रदेश को एक बड़ा भारी खतरा पैदा हो सकता है। पता नहीं मंत्री जी जानते हैं या नहीं। हम जानते हैं कि आप उत्साही व्यक्ति हैं, आपके अन्दर उत्साह है और जन कल्याण की भावना है, लेकिन आप कैसे सारी योजनाओं को पूरा करेंगे। आपको इसके लिये मशीनरी चाहिये। आपकी मशीनरी क्या है ? डायरेक्टोरेट और सचिवालय। आप कहते हैं कि अस्पताल साढ़े ७ बजे खुलते हैं। मैं कहता हूं कि अस्पतालों के अन्दर लिखा हुआ है कि अस्पताल ८ बजे खुलेंगे। आप लखनऊ में बैठकर किस मशीनरी के दावे पर कह सकते हैं कि अस्पताल साढ़े ७ बजे खुलते हैं ? आपकी वही पुरानी मशीनरी है। अगर आपके अन्दर हिम्मत है तो आप उस डायरेक्टोरेट को रिआर्गेनाइज करिये। आप जानते हैं कि आपके यहां कितने पटु डायरेक्टर हैं। आपकी उम्र तो अभी थोड़ी है। बड़ी बड़ी उम्र वाले जब मंत्री लोग आते हैं उनको भी वे प्रसन्न

[श्री राजाराम---]

कर लेते हैं । आप कहते हैं कि सभी डाक्टरों का हमने तबादला कर दिया । क्या आप समझते हैं कि इससे प्रदेश का स्वास्थ्य बढ़ जायगा ? डाक्टरों से आपको पूछना चाहिये और इनडायरेक्टली भी आपको जानना चाहिये था कि कौन सी जगह किस को सूट करेगी । डाक्टर संतुष्ट रहेगा तभी वह अच्छी तरह से काम कर सकता है । लेकिन मैं इस बात को कह दूं, मंत्री जी कि आपके यहां डाक्टर्स के तबादले में स्टेशन्स बिके हैं । आपको क्या पता है । आपके यहां डायरेक्टोरेट से प्रोपोजल्स आते हैं । वह प्रपोजल्स कौन भेजता है । मैं इस बात की ओर केवल संकेत करना चाहता हूं । आपकी भावनायें स्वच्छ हैं । आप प्रदेश के जन कल्याण को ध्यान में रखते हुये एक प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं । मशीनरी आपकी स्वच्छ होनी चाहिये । हमारे स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य उप मंत्री तकड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे सचिव और डायरेक्टर भी तगड़े हैं । अगर रस्साकशी हो तो मैं यह कह सकता हूं कि मंत्री महोदय अपनी मशीनरी के सामने थक जायेंगे । इसलिये अगर आप अपने प्रोग्राम को पूरा करना चाहते हैं तो मशीनरी के ऊपर आपका कब्जा होना चाहिये ।

आपने कहा कि हम रूरल एरिया में मेडिकल कालेज खोलना चाहते हैं । बड़ी उत्तम भावना है । गांव के लोग उसमें आयेंगे । लेकिन बजट व्याख्यान में आपने केवल पूर्वी जिले का नाम लिया । मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि देवरिया जिले में इंटरनेशनल फेम का सेंटर कुशीनगर है । वहां चार लाख की लागत से एक बिल्डिंग भी बनी हुई है जिसका थोड़ा सा पोर्शन डिग्री कालेज के होस्टल के लिये यूटिलाइज होता है । वहां पर जापान और दूसरी जगहों के बुद्ध धर्म मानने वाले लोग रहते हैं । आपको साधन वहां पर मिल सकते हैं और हम लोगों से जो सहयोग आप चाहेंगे वह हम देंगे । मेडिकज कालेज अगर आप रूरल एरिया में बनाना चाहते हैं तो कुशीनगर उसके लिये बहुत सुन्दर और उपयुक्त स्थान होगा ।

इन शब्दों के साथ में जो यह कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राज बहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा रखे गये अनुदान के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से संविद की सरकार बनी है और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सम्भाला है, उन्होंने अपने बजट भाषण में जो इस सदन को बतलाया था कि अब दिशा बदली है, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि निस्संदेह इस प्रदेश में अस्पतालों के वातावरण में बहुत सुधार तो नहीं हुआ है लेकिन बदल जरूर गया है । यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, कुछ अस्पतालों को देखने के बाद । यह बात बहुत सही है और पहले भी कही जा चुकी है कि अस्पताल पहले टाइम से नहीं खुलते थे, डाक्टर लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे रहते थे और इस वजह से अस्पताल देर से पहुंचते थे । लेकिन जब से यह सरकार बनी है चारों तरफ इसका भूत लोगों के ऊपर छाया हुआ है और लोगों ने जिम्मेदारी से काम करना शुरू कर दिया है । मैं इस बात को मानता हूं कि अभी तक बहुत सुधार नहीं हुआ है लेकिन दिशा बदली है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की यह बात बहुत उत्साहवर्द्धक है कि उनका ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ विशेष गया है । इसके लिये मैं उनको सदन की तरफ से मुबारकबाद देता हूं । निस्संदेह आज ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिये समुचित व्यवस्था नहीं है । भोजन, कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य नागरिक जीवन के आवश्यक अंग है । आज स्वास्थ्य के लिये जितनी परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में है, अगर उसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाय तो मैं कहता हूं कि काफी समय उसकी तरफ लगाना पड़ेगा । केवल थोड़े समय में उस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा । आज जो गांवों में थोड़े से अस्पताल हैं भी उनमें डाक्टर भी नहीं रहते । मेरे यहां के गोसाईगंज अस्पताल में

काफी दिनों से कोई डाक्टर था ही नहीं । इस संबंध में मैंने कई बार सरकार का ध्यान दिलाया और अभी कुछ दिन पहले ही वहां डाक्टर पहुंचे हैं। ऐसे जो थोड़े बहुत अस्पताल गांवों में हैं भी, उनमें डाक्टर भी नहीं हैं और दवाओं का तो कुछ कहना ही नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्य न देना चाहिये और इसके लिये मैं सुझाव देता हूं कि शहर के अस्पतालों में काफी डाक्टर रहते हैं, अपग्रेडेड होते हैं, कुछ विशेषज्ञ भी होते हैं, इसलिये जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी है, तब तक शहर के अस्पतालों में डाक्टर भले ही कम रहें लेकिन उनको देहातों में भेज दिया जाय क्योंकि ग्रामीण जनता को दवाओं की सुविधा हर हालत में मिलनी चाहिये।

यह जो पुस्तिका बटी है उसको पढ़ने की जरूरत है। उसमें दिखलाया गया है कि पिछले बीस वर्षों तक रहने वाली सरकार ने क्या-क्या काम किया है और ढाई तीन महीने की इस नयी सरकार ने स्वास्थ्य की दिशा में क्या-क्या काम किये हैं।

श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस २० वर्ष और ढाई महीने की संख्या पर आप प्रतिबन्ध लगादें क्योंकि ऐसा हो जाने पर इधर के लोगों को बोलने के लिये कोई बात नहीं रह जायगी, उनके पास कोई मसाला नहीं रह जायगा । इसलिये आप उन पर जरूर प्रतिबन्ध लगा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें, यदि मैं ऐसी व्यवस्था दे दूंगा तो अव्यवस्था हो जायगी । इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री राज बहादुर द्विवेदी—

मैं कह रहा था कि इस पुस्तिका के पेज ११ को देखें जिसमें नसबन्दी की काफी चर्चा की गयी है। उसमें दिया गया है कि ७९,३१५ स्त्री, पुरुषों की नसबन्दी की गयी । नसबन्दी की योजना अच्छी है लेकिन मैं इस बात की तरफ जरूर इशारा करना चाहता हूं कि इस योजना को सफल ढंग से नहीं चलाया गया । नसबन्दी उन लोगों की की गयी जिन्होंने या तो स्वयं रुपये के लालच में नसबन्दी करायी या जो उस स्तर पर पहुंच गये थे, और जो स्वेच्छा से तैयार नहीं थे । आपने नसबन्दी की योजना चलायी है तो आपको चाहिये था कि नसबन्दी के रूप में चलाते और उसके लिये सही वातावरण बनाते, तो भविष्य में नसबन्दी योजना को काफी सफलता मिलती । अगले बजट में १.७५ लाख आपरेशन की व्यवस्था की गयी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि पिछले वर्षों में जिस तरह से आपने नसबन्दी की योजना चलायी है अगर अगले वर्ष भी आपने उसी तरह का कार्यक्रम चलाया तो नसबन्दी के लिये दरअसल या तो कोई तैयार नहीं होगा या लोगों के लिये उपयोगी नहीं होगी। और जब उपयोगी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि यदि नसबन्दी योजना या परिवार नियोजन को चलाया जाय तो उसमें सुधार किये जायं और अच्छे ढंग से अमल में लाये जायं।

मंत्री जी ने २-३ बातें बड़ी उत्साहवर्द्धक कहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों के अभाव को पूरा करने के लिये दो मेडीकल कालेज स्थापित किये जायेंगे। एक पर्वतीय क्षेत्र में और एक ग्रामीण क्षेत्र में । एक सुझाव मुझ से पहले वक्ता ने कुशीनगर का दिया है, वह ठीक है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फैजाबाद एक ऐसा स्थान है जहां न कोई विश्वविद्यालय है और न मेडिकल कालेज है। वहां आचार्य नरेंद्रदेव का स्मारक हैं। उस स्थान पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय क्योंकि वहां एक भवन के मिलने की भी बात है। मंत्री जी और सुझावों को देखते हुये इसको भी अपनी दृष्टि में रखें। माननीय नरेंद्रदेव

[श्री राज बहादुर द्विवेदी---]

जी की यादगार में मेडीकल कालेज खोला जायेगा तो प्रदेश का बड़ा हित होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाक्टरों का अभाव है उसकी पूर्ति में भी काफी मदद मिलेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले मलेरिया योजना चालू की गई । वह काफी हद तक सफल रही और मलेरिया का उन्मूलन हो गया । इसके बाद चेचक उन्मूलन योजना चलाई गई। लकिन यह सफल नहीं हो पाई। इस पर ध्यान देना होगा । इस बीमारी से काफी मौतें होती हैं । लेकिन अधिकारी सही सही रिपोर्ट नहीं देते हैं । मेरे जिले में इससे काफी मौतें होती हैं लेकिन अधिकारी बहुत कम बताते हैं । इसलिये उनको आदेश दिये जायं कि वे सही रिपोर्ट दिया करें जिससे सरकार सही प्रोग्राम बना सके क्योंकि जब तक सही नक्शा सामने नहीं आयेगा तब तक सही कदम कैसे उठाया जा सकेगा ?

मैंने मंत्री जी के बजट भाषण को सुना और मेरी व्यक्तिगत राय है कि पिछले साल से जो सरकार ने पेइंग बैड्स की स्कीम चलाई है वह केवल सम्पन्न लोगों के लिये ही सुविधाजनक हुई है । इसमें गरीब आदमी पैसा न होने के कारण भरती नहीं हो पाते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस बात की घोषणा करें कि अस्पतालों में जो पेइंग बैड्स की स्कीम चलाई गई है वह समाप्त की जाये जिससे गरीबों को सुविधा मिल सके ।

हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि एलोपेथी के साथ साथ अन्य पद्धतियों की तरफ भी ध्यान दिया जायगा । मैं उनसे सहमत हूं और चाहता हूं जितनी पद्धतियां हैं सभी पर विशेष ध्यान देना चाहिये । मैं समझता हूं कि सरजरी में एलोपैथी सब से उत्तम है लेकिन जहां तक दवा का सवाल है उसमें होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयां ज्यादा लाभदायक हो सकती हैं । मैं मांग करूंगा कि इनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय और देहातों में आयुर्वेदिक दवाखाने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाये तो ज्यादा सुविधा होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात कही है। उत्तर प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता देहातों में रहती है । यह नारा तभी सार्थक होगा जब उनके हितों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । मैं मानता हूं कि यह काम बड़ा पेचीदा है लेकिन उस तरफ चलिये तो । तभी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा सार्थक हो सकता है । माननीय मंत्री युवक हैं, उनकी भावनायें अच्छी हैं । इन शब्दों के साथ मैं उनक अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपकी दृष्टि तीन घंटे की लगातार उठक-बैठक के बाद मेरे ऊपर पड़ी । मान्यवर, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी के भाषण को अभी सुना । उन्होंने जो डिमांड आज पेश किया है उन्होंने उसका उद्देश्य मानव मात्र की सेवा बताया है । स्वास्थ्य मंत्री स्वयं भी स्वस्थ्य हैं । उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की परम्पराओं को सधारने के लिये दौड़ धूप मचाई । अभी सदन में सुना कि बांदा अस्पताल में छापा मारा । बहुत सी दवायें निकालीं । वह रात दिन प्रयत्नशील हैं । वह जन कल्याणकारी इस विभाग को बनाना चाहते हैं । लेकिन आज जहां कांग्रेस के बीस साल के प्रशासन की दुहाई दी जाती है, कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इन तीन महीनों में जितनी दौड़ धूप उन्होंने मचाई, उसका नतीजा यह हुआ कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया । मैं पहाड़ी क्षेत्र से आया हूं । माननीय स्वास्थ्य मत्री का और मेरा क्षेत्र मिले हुये हैं । उस क्षेत्र के निवासियों को जो परेशानियां हैं उनसे स्वास्थ्य मंत्री महोदय भली प्रकार परिचित हैं । मैं हल्द्वानी क्षत्र का निवासी हूं । हमारे यहां जिस शहरी क्षेत्र में अस्पताल बना हुआ है उसका निधॉरण १९१४–१५ की जन संख्या के आधार पर हुआ था । तब से आज तक दवाओं का बजट और रखरखाव का बजट वही चला आता है जब कि केवल शहरी क्षेत्र की आबादी ५०–६० हजार हो गयी है । वहां पर पांच कम्पाउन्डरों की जरूरत है जब कि

केवल दो तीन ही हैं। इस नये बजट में उस पर विशेष ध्यान देना चाहिये था। लेकिन उसके रखरखाव के लिये कोई विशेष प्राविधान नहीं किया गया है। जब १९५१-५२ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्डर में था, वहां पर कम से कम पंखे तो चलते थे। जब प्राँतीयकरण हुआ तो बिजली पहुंच गयी है लेकिन पंखे उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा मरीज जाते हैं, तो देखते हैं, कि बड़ी बड़ी दवाइयां तो एक तरफ रहीं, मरहम पट्टी तक भी गरीबों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। मंत्री जी ने कहा कि अब विशेष सुविधाओं के लिये दवाओं का विशेष कोटा रखने की प्रथा समाप्त कर दी गयी है, मैं भी नहीं चाहता हूं कि दवाओं का कोई विशेष रिजर्वेशन किया जाए। लेकिन इससे होगा क्या ? जो कोटा खत्म किया जाएगा उससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। एक्सरे मशीन बार-बार वहां की जनता और कार्यकर्ताओं के चिल्लाने पर लगी है, किन्तु वह अब भी ठीक से काम नहीं करती है। यदि वह ठीक भी कभी हो जाती है तो उसकी प्लेटें नहीं मिलती हैं जिसके कारण कभी भी उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। अभी जब स्वास्थ्य मंत्री जी वहां गये थे और उन्होंने वहां की जनता के सहयोग की याचना की थी। किन्तु मुझे खेद है कि स्वास्थ्य मंत्री जी जब अपने निर्वाचन क्षेत्र में पधारे तो बिल्कुल अपने क्षेत्रसे मिले हुये क्षेत्र के प्रतिनिधि से यह भी नहीं कहा कि आप इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और आपका सहयोग हमें चाहिये। तो मैं कैसे मान लूं कि मंत्री जी को जनता के सहयोग की आवश्यकता है और वह उसके सहयोग का सदुपयोग करेंगे ?

इन दिनों रुद्रपुर में कालोनाइजेशन हो रहा है, वहां पर तमाम किस्म के विकास कार्य हो रहे हैं, किन्तु उसके साथ ही साथ क्राइम्स वगैरह का भी विकास हो रहा है। एक अस्पताल वहां पर है, लेकिन वहां के लोगों को वहां से २० मील की दूरी पर हलद्वानी में पोस्टमार्टम के लिये ले जाया जाता है। मैं पहाड़ी क्षेत्र की बातें आपको बताऊं, जहां पर २०,२१ लाख की जनता है, अल्मोड़ा और नैनीताल की बराबरी को छोड़कर वहां पर कहीं पर भी कोई महिला चिकित्सालय नहीं बनाया गया है और न इस बजट में ही उसका कोई प्राविधान किया गया है। जो वहां पर रूरल डिस्पेन्सरीज हैं उनमें भी दवाओं का कोई स्टाक नहीं है, न डाक्टर ही उपलब्ध हैं।

अभी परसों प्रश्नों के समय मंत्री जी ने बताया था; जब उनसे यह पूछा गया था कि वहां पर चेचक से कितनी मौतें हुई हैं, तो सूचना दी कि वहां पर चेचक से केवल चार मौतें हुई हैं। किन्तु जब उनसे पूछा गया और जोर देकर कि क्या यही वास्तविक स्थिति है तो उन्होंने सूचना मंगाने की बात कही है। उस क्षेत्र के जो डी० एम० ओ० एच० महोदय हैं, उनका काम और व्यवस्था और व्यवहार जनता के साथ ठीक नहीं है वहां की जनता ने उनके ट्राँसफर की भी मांग कर रखी है, मुझे पता नहीं कि अभी उनका ट्राँसफर हुआ है या नहीं, लेकिन समस्यायें जो हैं जनता की, बीमारियाँ जो जनता की हैं, उनका समय पर ठीक से इलाज न हो सकने के कारण वह विकराल रूप धारण कर लेती हैं और इससे संक्रामक बीमारियां फैली हैं। अगर वह इस मामले में फिर गहराई से देखें तो सौ से ऊपर वहां पर मौतें हुई हैं और सरकार को बिल्कुल गलत रिपोर्ट जिला अधिकारियों ने दी हैं। पहाड़ों पर अनेकों अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं और कहीं पर दवायें नहीं मिलती हैं। मंत्री जी ने यह तो कहा कि वह झोपड़ियों में भी अस्पताल खोल सकते हैं, लेकिन पहले आप पक्की इमारतों में जहां अस्पताल खुले हैं डाक्टर उपलब्ध कराइये। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जिस निर्वाचन क्षेत्र से पधारे हैं, भले ही वहां की जनता को वह कुछ आश्वासन दे आए हों, लेकिन उनको ठीक से पता नहीं है कि वहां की वास्तविक कंडीशन क्या है, और वहां के अस्पतालों की क्या स्थिति है, वक्त पर वहां कभी जनता को दवाएं नहीं मिल पाती हैं। आप किसी भी समय जिस तरीके से बांदा की तरफ आपने कदम उठाया है किसी वक्त किसी अवसर पर जरा वहां भी पहुंचे और जन साधारण में खड़े हो कर देखे कि वहां टिंचर आयोडीन भी नहीं है, स्प्रिट चाहें तो स्प्रिट नहीं मिल सकती।

[श्री इन्द्रलाल--]

आप जहां बड़ी-बड़ी योजनायें बनाते है; मेडिकल कालेजों को लेना चाहते है वहां जरा जनता के मेडिकल कालेज में जाइये और जो आपने आश्वासन दिया है कि हम लखनऊ जाकर जनहित का कार्य करेंगे तो आप जब तक उनकी ओर नहीं देखेंगे तब तक जनता की वास्तविक सेवा हो नहीं सकती। आये दिन इधर उधर से आरोप प्रत्यारोप तो बहुत होते हैं लेकिन क्या आपनें कभी यहां दारुलशफा में ही देखा है कि वहां दवायें उपलब्ध नहीं होती हैं, विधायक लोग जाते हैं उनको समय पर दवायें उपलब्ध नहीं हो पाती है और बात-बात में उनको टाल दिया जाता है।

मलेरिया उन्मूलन के सम्बन्ध में बातें कही गयी हैं कि सरकार उसको रोक रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

समय बहुत कम रह गया है।

श्री इन्द्रलाल--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे ज्यादा समय मिलना चाहिये। लेकिन, खैर, मुझे यों तो बहुत सी बातें कहनी थीं लेकिन समय कम होने से केवल एक बात कहता हूं कि आप केवल सेवाओं के नाम पर कोरे कागजों के पन्ने रंग डालने का लक्ष्य बना रहे है अगर वास्तविकता को देखा जाय तो अभी तक आपने कुछ किया नहीं है। वास्तविक सेवा की ओर बढ़े तभी मानवमात्र की सेवा हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं, जो कटमोशन पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री कृष्ण बहादुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश हो रहा है मैं बड़े ध्यान से प्रारम्भ से ही इस सम्बन्ध में दिये गये भाषणों को सुन रहा हूं। मैं यह विचार करके चला था कि आज मुझे कुछ शिक्षा मिलेगी क्योंकि उधर जो मेरे माननीय मित्र बैठ हुये है उन्होंने दीर्घ-काल तक इस विभाग के द्वारा और अन्य विभागों के द्वारा ज्ञान अर्जित किया है और उनके अनुभवों से हम लाभ उठा सकेंगे परन्तु बालू से तेल निकालना तो आसान मालूम होता है परन्तु इन सब आलोचनाओं से कोई सार निकालना सम्भव प्रतीत नहीं होता। जिन्होंने इस विवाद को प्रारम्भ किया है वे बहुत सी बातें कहते रहे और कहते-कहते यह कह गये कि जो मद्रास से डाक्टर्स आयेंगे वे यहां लोगों की न बोली समझेंगे न भाषा फिर दवा कैसे करेंगें लेकिन यह साधारण सी बात है कि जिन लोगों ने यह योजना बनाई है उन लोगों ने इस बात का बिचार कर लिया होगा कि जो इस प्रदेश की बोली समझते है केवल उन्हीं को बुलायें, न कि जो तामिल, तेलुग् और मलयालम समझते हों, उनके बुलाने का कोई विचार नहीं है। आलोचना केवल आलोचना के लिये हो, वह बात समझ में नहीं आती। मैं जब चुनाव लड़ने के लिये सोच रहा था यह सोचा था कि इस माध्यम से साढ़े ८ करोड़ जनता की सेवा करने का सुअवसर मिलेगा, यहां बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जननायक है जिनके सान्निध्य में रह कर जनसेवा की भावना में वृद्धि होगी तथा उस ओर जिनको मैं समझता था कि यह अनुभवी हैं, उन्होंने मेरी भावना पर कुठाराघात किया और कुछ भी ऐसी बात नहीं कही जिससे मुझे प्रेरणा मिलती। दवाई की चोरी की बात उन्होंने कही कि जैसे स्वास्थ्य मन्त्री सिर पर लाल टोपी लगाये हुये है उसी तरह से दवाई की शीशी पर लाल टोपी लगा दी जाय तो दवाइयों की चोरी रुक जायगी। मैं उनको बताऊं कि हर इंजेक्शन की दवाई के ऊपर सफेद टोपी लगी हुई है। लेकिन उस सफेद टोपी के बावजूद भी दवाइयों की चोरी चल रही है। कई मित्रों ने इस बात का जिक्र किया कि उनके ऊपर यू० पी० सी० लगा देना चाहिये। यह गोली के ऊपर लिखा तो सम्भव है लेकिन इंजेक्शन की शीशी के ऊपर या सब दवाइयों पर या पाऊडर के ऊपर किस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार से उनकी चोरी को रोका जा सकता है इसके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार हो रहा है ताकि दवाइयों की चोरी में रोकथाम की जा सके। इतनी बात सदन के समक्ष अवश्य रखना चाहता हूं कि जिस भारी पैमाने पर

आज से पहले जो सरकार थी उसके जमाने में चोरी हुआ करती थी उस बड़े पैमाने पर कम से कम नहीं रह गई है। यह हमारा दावा नहीं है कि दवाई अब चोरी नहीं होती है या बिलकुल रुक गई है।

जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, इसके लिये हमारे विभाग की ओर से हमारे अधिकारियों की ओर से यह दावा नहीं किया गया है कि हमने भ्रष्टाचार रोक दिया है परन्तु यह दावा अवश्य है कि भ्रष्टाचार का निवारण करने के लिये हमने कदम बढ़ाया है और वह हमारा कदम सही दिशा में है। इसलिये हम यह दावा करते है कि हमको अवसर मिलने पर हम इस भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकेंगे। हमारे एक भाई ने यह कहा कि यहां पर डाक्टरों को आकर्षक ग्रेड मिलना चाहिये जिसकी वजह से डाक्टर दूसरे प्रदेशों से हमारे यहां आ सके। ग्रेड कम होने के कारण दूसरे प्रदेश में यहां से डाक्टर चले जाते हैं और जो डाक्टरों की कमी है वह कमी न हो इस वजह से उनको अधिक वेतन देने की बात उन्होंने कही। मैं अपने मित्र की सूचना के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों में जो वेतन के क्रम हैं उनको मैं यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं जिससे यह गलतफहमी दूर हो जाय कि हमारे प्रदेश में वेतन क्रम बहुत कम है और इतने अनाकर्षक है जिसके कारण डाक्टर यहां नहीं ठहरते है। बिहार में एम० बी० बी० एस० पास डाक्टरों को २१० से ४५०। गुजरात में २२० से ६५०। उड़ीसा में २५० से ५४०। अपने प्रदेश में ३०० से ९०० तथा सेलेक्शन ग्रेड ६०० से १,२५० तक है। इस प्रकार से मैं अपने मित्र तथा अपने दूसरे माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि जो आलोचना यहां पर की गई कि यहां के ग्रेड आकर्षक हैं इनको आकर्षक बनाये जायं तो डाक्टर रुक सकते हैं, यह सही नहीं है।

तीसरी बात जो हमारे मित्र ने कही कि मेडिकल कालेज को जो राज्य सरकार के अन्तर्गत लेने का प्रस्ताव है वह बिलकुल गलत है और इस पर उन्होंने आलोचना की। इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज बजट भाषण के समय मन्त्री जी ने अपने विचार प्रकट नहीं किये लेकिन मैं अपने मित्र को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उनका जो सुझाव है और जो उनकी स्वस्थ आलोचना है उनके ऊपर विचार किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर विचार किया जायगा। हमारे मित्र ने जो आलोचना की है और जो व्यावहारिक बातें कही हैं उन सभी के ऊपर हमारा विभाग गम्भीरता से विचार करेगा परन्तु मैं उनसे यह आशा करता था कि कुछ स्वस्थ आलोचना होती तो अच्छा था।

हमारा ही विभाग एक ऐसा विभाग है कि जो हमेशा देता ही देता है, लेता नहीं। हमारे मित्र ने नये दस पैसे की बात कही। उस पर अवश्य विचार किया जायगा कि वह लेने चाहिये अथवा नहीं, किन्तु दस पैसे रोगी को केवल एक बार ही देने पड़ते हैं और यह रकम इतनी कम है कि गरीब से गरीब आदमी भी इसे दे सकता है। किन्तु जिस के पास पैसा नहीं है उसके लिये आवश्यक भी नहीं है कि वह इस रकम को दे ही। उसे बिना यह पैसे दिये हुये ही परचा बना दिया जाता है और इसे आप सब लोग जानते है। मैं पिछले बीस वर्ष की बात नहीं कहता क्योंकि मेरे मित्र ने कहा था कि इस पर पाबन्दी लगा दी जानी चाहिये। वह बात इसलिये भी यहां नहीं लाना चाहता क्योंकि कोर छूने से ही दुख होता है। मैं वह दुख उत्पन्न करना नहीं चाहता। तो इस प्रकार इस नयी सरकार ने एक योजना सामने रखी कि कुछ अस्पतालों में पेड शैय्यायें होती हैं और उन के लिये विशेष रियायतों की सुविधा रहती हैं। इस नवीन सरकार ने इस पर विचार करने का निश्चय किया है कि इस प्रकार की व्यवस्था को क्यों न समाप्त कर दिया जाय ताकि गरीब जनता को कुछ और अधिक सुविधा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष––

समय की बहुत कमी है इसलिये जहां तक संभव हो आप भाषण संक्षेप में ही समाप्त करें। यदि आप ५ मिनट में समाप्त कर सकें तो अच्छा हो।

[श्री कृष्ण बहादुर---]

बहुत अच्छा, मैं पेइंग बेड्स की बात कह रहा था। इस संबंध में निकट भविष्य में ही बताया जा सकता है। कुछ खास खास बातें जो स्थान विशेष के संबंध में मेरे मित्रों ने कहीं है, उनके संबंध में निश्चित रूप से जांच होगी और उनके सुझावों पर यथासंभव अमल किया जायगा।

(इस समय ३ बज कर ४८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुये।)

जहां तक आयुर्वेद का प्रश्न है, उस विषय में इतना ही कहूंगा कि पिछली सरकार के दो वरिष्ठ नेताओं की कशमकश में स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की जो दुर्दशा पिछले सालों में हुई है और वहां जो अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था रही है उससे सभी अच्छी तरह से परिचित हैं इससे आयुर्वेद की कमर ही टट गयी। अब उस कमर को सीधी करने के लिये हमने इस विभाग द्वारा निकट भविष्य में आयुर्वेद के विद्वानों और ज्ञाता लोगों की एक विस्तृत सभा करने का आयोजन किया है जिस के माध्यम से कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सके जिससे आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित किया जाय। इस संबंध में हमारा प्रयत्न जारी है। हमारे कई मित्र पिछली सरकारों में मंत्रिपद सुशोभित कर चुके हैं। मैं उनसे अपेक्षा करता था कि वे ऐसी कुछ बातें कहेंगे जिस पर गौर किया जा सके लेकिन उनकी बात सुन कर मुझे कुछ निराशा ही हुई है। आचार्य जी ने स्वास्थ्य विभाग के बजट पर कोई बात नहीं कही। वह विभाग के बजट पर कोई बात नहीं कही। यह तो पुरानी बात को ही लेकर दोहराने लगे कि इस विभाग को अमृत को छोड़ कर हलाहल का ही पान करना चाहिये। ऐसा लगता है कि उनमें एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसी निराशा उत्पन्न हो गयी है कि जिसके कारण वे रचनात्मक सुझाव नहीं दे पा रहे है। हमारी जो बुद्धि है, जो हम लोगों का हिसाब है उसी से चल कर हम जनता जनार्दन के कष्टों को दूर करने की योजना बना रहे हैं। आज रिक्शा चलाने वाले से लेकर ऊपर की श्रेणी वाले लोगों तक को यह मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे निवास स्थान पर लोग पहुंच जाते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। आज एक सज्जन उस पक्ष के मेरे पास आये और उन्होंने कई बातें शासन के विषय में कहीं, परन्तु उनमें इतना भी साहस नहीं है कि उन सही बातों को पुष्टि के लिये कहा जाता। माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि बधाई देना चाहता हूं, यह भी नहीं हो सका कि मुक्त कंठ से शाबाशी देते कि हमारे छोटी उम्र के मंत्री ने इस विभाग के अन्दर कैसी क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। मेरा दावा है कि पिछले शासन में जो डाक्टर कभी समय पर उपस्थित भी नहीं होते थे वह आज समय से उपस्थित हो रहे हैं। जो दवायें लोगों को उपलब्ध नहीं होती थीं वह हो रही हैं। जो दवाई "वी० आई पी० कोटा" के नाम पर वरिष्ठ लोग ले जाते थे और उनके सगे संबंधी ले जाते थे आज शासकीय आदेश के द्वारा सब कोटे में कटौती कर दी गयी है और कोई ऐसी सुविधा इस समय उपलब्ध नहीं है। फिर भी चर्चा कि गयी कि वी० आई० पी० कोटा और एम० एल० ए० कोटा बन्द होना चाहिये। आपको सूचना के तौर पर बता देना चाहता हूं कि वह समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार का कोई कोटा अब नहीं है, सब अस्पताल में पहुंच गया है और यदि कोई लेने जायेंगे तो उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। (एक आवाज--- मिनिस्टर का कोटा ?) वह भी वी० आई० पी० में ही आते हैं।

फैमिली प्लानिंग की चर्चा की गयी कि बुड्ढों और असमर्थ लोगों की नसबन्दी कर दी गयी। मेरे माननीय मित्रों के पास अगर कोई ऐसी सूचनायें हों तो कृपया इस विभाग को दें ताकि जिनके विरुद्ध ऐसी शिकायतें हो उनके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इस भ्रम में न रहें कि पिछले वर्षों में जिस तरह से लोग सूचनाओं पर सूचनायें दिया करते थे और कोई सुनवाई नहीं होती थी। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, हमको १० मिनट का समय मिला है।

श्री अधिष्ठाता---

इस ग्राँट को साढ़े चार बजे तक पास करा देना है। कटौती के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य बोलेंगे, मंत्री जी भी बोलेंगे। यह आप देख लें।

श्री कृष्ण बहादुर ---

मैं कह रहा था कि इस प्रकार से अगर स्पेसिफिक चार्जेज हों अधिकारी के विरुद्ध तो देने चाहिये। आप लोगों को आश्वासन होना चाहिये कि पिछली सरकार में जिस प्रकार से मंत्रियों के पास लोगों को पहुंचने में कठिनाई होती थी और शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, वह चीज अब होने वाली नहीं है और दोषी अधिकारी कोई पाया जायगा तो उचित मात्रा में विधि अनुसार उसे दंड मिलेगा और सूचना पर तुरन्त कार्यवाही की जायगी।

हमारे एक मित्र ने बोलते-बोलते कह दिया कि अभी तक १/३ खर्च इस विभाग का दवाओं पर होता था और २/३ कंस्ट्रक्शन पर होता था। अब उलट गया है। हमारे नौजवान मंत्री ने तय किया है कि १/३ कंस्ट्रक्शन पर होगा और २/३ दवाओं पर होगा। इस पर भी उनको आपत्ति है। इस आपत्ति को पेश करते हुये कहा कि २/३ का २/३ देहात में ही खर्च मंत्री जी करते तो शायद उनको बड़ा संतोष होता। लेकिन वह भूल गये कि प्रारम्भ में ही इस अनुदान को स्वीकार करने के लिये जो प्रस्ताव मंत्री जी नें रखा उसमें स्पष्ट संकेत किया कि अब हम शहरों से देहात की ओर जा रहे हैं देहात की समस्याओं और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझने के लिये और २/३ क्या, हम तो समस्त देहात में ही लगाना चाहते है, क्योंकि ९० प्रतिशत लोग देहात में रहते है और हम तो ९० प्रतिशत के अनुसार ही जहां तक होगा वहां तक वहीं खर्च करेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। डायरेक्टोरेट को ठीक करने की बात कही गयी, डायरेक्टोरेट में बड़े बड़े ऐसे अधिकारी रहते थे जो बड़े बड़े नेताओं के कृपा पात्र थे, उनका इधर से उधर तबादला किया गया। जनता जनार्दन का आज पूरा सहयोग मिल रहा है और चारों तरफ प्रशंसा ही सुनाई पड़ रही है। मिश्रा जी ने कहा कि बांदा कांड क्या हो गया, बड़ा भारी तीर मार लिया। मैं पूछता हूं कि पिछले तमाम वर्षों में एक भी बांदा कांड किसी माननीय मंत्री ने किया हो तो वे बतायें।

कहा गया कि जल्दी जल्दी तबादले करके कोई अच्छा काम नहीं किया, बड़ी गड़बड़ी हो गयी। मैं पूछता हुं कि जो डाक्टर देहातों में जाना नहीं चाहते थे, वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुये थे और जो यह समझे हुये थे कि अब तो वे दूसरी जगह नहीं जायेंगे, अगर उनको दूसरी जगह भेज दिया, उनकी योग्य सेवाओं का फायदा दूसरी जगह वालों ने भी उठा लिया तो इसमें कौन सी गलती हमने की ? यह आलोचना की जाती है कि उनसे पूछ कर, जहां उनकी गोटें बैठती, वहां उनको भेजा जाता, ऐसा कहना उचित नहीं लगता। एक ही सांस में वे कुछ कहते है और दूसरी ही सांस में वे कुछ कहने लगते हैं। पिछली तमाम वर्षों की खराबियों को एक महीने में नहीं सुधारा जा सकता, इसमें काफी समय लगेगा। इसके लिये तो संस्कृति को बदलने की आवश्यकता होगी। उसके लिये समय चाहिये, आपका सहयोग चाहिये। उन कटुताओं को भुलाकर इस विभाग के साथ आपको सहयोग करना चाहिये। जो भी लाभान्वित सुझाव हों, उनको देना चाहिये। आपके द्वारा पिछले २० वर्षों में प्रदेश की जनता की सेवा नहीं हो पायी है, यह सरकार सेवा करने का प्रयास कर रही है। बाकी बातें मैं फिर कभी कहूंगा।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपने स्वास्थ्य विभाग के उप मंत्री जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना। जिस क्रान्ति का उन्होंने जिक्र किया, मुझें खेद है कि उसमें चमत्कार मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने शुरू में ही कहा था कि एक महीने में जो क्रान्तिकारी कदम स्वास्थ्य मंत्री जी ने उठाया है, मैं उसे क्रान्तकारी कदम नहीं मानता। उसमें आशा की कोई बात नहीं है। इस विभाग की कार्यप्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जो बहस आज हुई उसमें यही कहा गया कि पिछले २० वर्षों में क्या हुआ। बीस वर्ष की बात बहुत ज्यादा कही गई। मुझ को अफसोस है कि यह जो स्वास्थ्य समीक्षा की किताब सदस्यों के हाथ में है जिसमें अधिकांश जो बीस वर्षों में हुआ है उसको वह बताती है और हमारे साथी और वरिष्ठ सदस्य आचार्य

[श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह]

जी ने एक और भी अच्छी मिसाल दी। उन्होंने बताया कि इससे तो कम से कम परखा जा सकता है कि इन बीस वर्षों में क्या हुआ। जिस वक्त इस देश को आजादी मिली उस वक्त से अब तक जो औसत आय है वह बढ़ गई है। मुझको अफसोस है कि मेरे एक साथी ने उसको गलत समझा कि इस प्रदेश में ऐसा कार्य किया गया जिससे हमारी औसत आयु बढ़ गई। मैं उप मंत्री जी को एक बात के लिये धन्यवाद जरूर दूंगा कि उन्होंने संकेत किया कि मेडिकल कालेज को पुरानी स्थिति पर रहने दें। मैं और मेरे साथी बहुत से लोगों ने इस बात पर अपने विचार प्रकट किये और सबकी यह मान्यता है कि उन संस्थाओं को अपने पुराने रूप में रहना चाहिये जिससे कि वहां का जो मुख्य रिसर्च का कार्य है उसको अच्छे ढंग से चलाया जा सके। मैं यह बात कहने के लिये तैयार हूं कि जो भी खराबियां है उनको आप दूर करें तो उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। हम भी नहीं चाहते है कि डाक्टरों को बहुत ज्यादा प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत मिले। उस पर आप प्रतिबन्ध लगावें। लेकिन उनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये, उनको ऐसी चीजें मिलनी चाहिये जिससे वे लालच में न पड़ें और अपने कर्त्तव्य का अच्छे ढंग से पालन कर सकें।

अधिष्ठाता महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं जिस पर हमारे मित्रों ने इशारा किया कि इस चिकित्सा और स्वास्थ्य के विभाग में समन्वय होना चाहिये। जिले के स्तर पर जो दिक्कत आती है, सिविल सर्जन और डी० एम०ओ०एच० के झगड़े अक्सर हो जाते हैं, अस्पताल बटे हुये है अलग अलग जिनमें कि व्यवस्था करने में दिक्कत होती है और साथ ही साथ जिलों में तो जिला परिषद् भी कुछ अस्पताल चलाती है और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय है। तो इस तरह से जो अलग अलग चले हुये अस्पताल है इनकी एक व्यवस्था होनी चाहिये जिससे सचारु रूप से सभी अस्पतालों में उचित मात्रा में औषधियों का प्रबन्ध हो सके और उचित ढंग से डाक्टर रह सकें और ज्यादा से ज्यादा सेवा वे देहातों की कर सकें। कहा गया है कि बड़े देहातों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इसके लिये उनको बधाई देता हूं और चाहता हूं कि देहाती उन अस्पतालों में जहां कि दवा के नाम पर कुछ खाली शीशियां देखने को मिलती है और जहां डाक्टर उन गरीबों को यही राय दिया करते है कि बाजार से दवा खरीदें जिनको खरीदने में वे असमर्थ है वहां की हालत सुधरे, वहां अधिक से अधिक दवाईयां पहुंचे जिससे सही माने में ग्रामीण जनता को लाभ हो सके। साथ-साथ मैं एक बात अपने प्रारम्भिक भाषण में नहीं कह सका था कि आज भी देहात के लोगों को आयुर्वेद की प्रणाली पर ज्यादा विश्वास है और उनकी मान्यता है कि हमारी पुरानी जो पद्धति है उससे ज्यादा प्रभावशाली ढंग से रोगों को खत्म किया जा सकता है। ऐसी मान्यतायें उन लोगों की हैं कि एलोपैथी प्रणाली ऊपरी इलाज करती है। रोगों की जड़ पर मूल प्रहार आयुर्वेद द्वारा होता है। इस तरफ देहाती क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है और आयुर्वेद के प्रचार से उन डाक्टरों को रख कर अच्छे ढंग से काम किया जा सकता है।

(इस समय ४ बज कर ७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं एक बात और खास तौर पर कहना चाहता हूं। यहां पर अभी मंत्री जी ने कहा कि कुछ नेताओं के चहेतों को डाइरेक्टरेट से अथवा किन्हीं स्थानों से हटा दिया गया है इसलिये यह बात कही जा रही है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इधर के लोगों के चहेतों को हटा कर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने चहेतों को रखा है। तबादलों में कितना टी०ए० का पैसा दिया गया है, इसका कोई खयाल नहीं किया गया। वह पैसा अगर दूसरी जगह पर खर्च किया जाता तो बहुत सा अच्छा काम हो सकता था। दूसरे मुल्कों में इस तरह से डाक्टरों के जल्दी-जल्दी तबादले होते हुये नहीं पाये जाते। जहां पर कोई डाक्टर काम करता है वहां पर उसकी कुछ ख्याति हो जाती है और लोगों में उसके प्रति कुछ विश्वास पैदा हो जाता है और वह जनता की ज्यादा सेवा कर सकता है। इस तरह की बातों को किसी प्रकार भी क्रान्ति नहीं कहा जा सकता। किसी अस्पताल में डेड स्टाक का पकड़ लेना और किन्हीं डाक्टरों के तबादले

कर देना कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं कहे जा सकते। इस प्रदेश की जनता को सस्ती चिकित्सा सुलभ हो, देहात में डाक्टर उपलब्ध हों जिससे शहरों की ओर ही उनको न दौड़ना पड़े, यह होगा तभी जनता समझेगी कि कुछ क्रान्तिकारी कदम उठाया गया। और तभी यह समझा जा सकता है कि यह विभाग सच्चे माने में मानवता की सेवा करने के लिये कृतसंकल्प है। इस विभाग का सचमुच ऐसे लोगों से संबंध है जो वास्तस्तव में पीड़ित है, जो रोगों के कारण आक्रान्त है। लेकिन मुझे अफसोस होता है जब यह काम नहीं हो पाता और इसकी भी प्रवंचना की जाती है। मुझे आशा है मंत्री जी लोगों में ऐसा विश्वास पैदा करेंगे कि देहात के लोगों को भी चिकित्सा उपलब्ध हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रताप सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी साथियों और सम्मानित मित्रों का आभारी हूं जिन्होंने इस अनुदान पर बोलते हुए अपने अमूल्य सुझाव प्रस्तुत किये। मैं उनको और खास कर माननीय नवल किशोर जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसको प्यार ही समझता हूं और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उनको सही प्रकार से कार्यरूप में परिण त किया जायगा। और जैसा उनके जमाने में हुआ करता था कि उनकी ओर के बैठने वाले जो सुझाव देते थे, उसको नम्बर एक दिया जाता था और दूसरी ओर जो लोग बैठते थे उनके सुझावों को नम्बर दो दिया जाता था, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी ओर से जो सुझाव दिये जायेंगे उनको नम्बर एक दिया जायगा और इधर के लोगों के सुझावों को नम्बर दो दिया जायगा।

हमारे माननीय मित्र ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें ५ बातें कही गयी हैं। पहली बात है—चिकित्सा प्रणाली को जनसाधारण को सुलभ करना। यही हम कर रहे हैं। होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं को सुलभ करने के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हम किस प्रकार से पिछली सरकार से आगे हैं। मुझे एक चीज का बहुत दुख हुआ। जब अंग्रेजी राज्य को समाप्त करके यह कांग्रेस आफिस में आयी तो अंग्रेजी राज्य से मुकाबला किया जाता है कि उसके मुकाबले में क्या अच्छाई की जा रही है। अब जब उसके स्थान पर हम आये हैं तो यह नेचुरल है कि हम पिछली सरकार से मुकाबला करें कि उससे अच्छा हम क्या कर रहे हैं। लेकिन श्री लक्ष्मीरमण जी ने कहा कि बार-बार यह २० साल, २० साल क्यों कहा जाता है। इससे तो उनको खुशी होनी चाहिए थी। आपको अंग्रेजों के राज्य को बदलने का श्रेय था तब तो आप को चाहिए था कि उनसे सत्ता लेने के बाद आप उसके जनता के अनुकूल बनाते लेकिन आप ऐसा न कर सके और आपको यहां से हटना पड़ा। मुझे बहुत दुख है कि प्रिजुडिस से ऐसी बातें कह दी जाती हैं। आचार्य जी ने कहा कि माननीय चरण सिंह जी थर्ड रेट के वकील हैं, जब तक वह उस दल में थे तब तक तो वह फर्स्ट रेट के वकील थे लेकिन इस तरफ आने से अब वह थर्ड रेट के हो गये। मैं नहीं समझता कि इस तरह की बातें कह कर क्या स्टैंडर्ड है उनका और किस तरह से वह विरोधी दल की भूमिका अदा करते हैं। हमारी बात तो यह है कि हमने एक बात श्री नवल किशोर जी को अच्छा आदमी कहा तो हम उनको बुरा नहीं कह सकते, न हम उस स्टैंडर्ड पर उतरना ही चाहते हैं। अच्छा होता कि अच्छे सुझाव उधर से आते कि हमने ढाई मास में जो काम किया उसमें क्या गलत किया, क्या अच्छा किया और क्या भलाई हम जनता की कर सकते हैं जो हम ने अभी नहीं की है।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का यह बजट रिएक्शनरी है लेकिन साथ ही मैं उसी दल के श्री नवल किशोर जी का बड़ा आभारी हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कोई नया काम नहीं किया है बल्कि जो स्वास्थ्य समीक्षा ६५-६६

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रताप सिंह]

की थी उसी में उन्होंने कुछ पन्ने और जोड़ दिए हैं। उन्होंने मेरी बात को आसान कर दिया यह कहकर कि पुरानी नीतियों में तब्दीली करनेकी इसमें कोशिश की गई है। लेकिन आचार्य जी की बातमें क्या कहूं। जिस दिन से यह सरकार बनी है उनको उनके ही मंत्री जब मुख्य मंत्री हो गये तो थर्ड रेट के एडवोकेट लगने लगे और जिस बजट के बारे में माननीय नवर किशोर जी की एक राय है वही बजट उनको रिएक्शनरी लगने लगा। इस दृष्टिभेद को मैं क्या कहूं? जिन आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक सिस्टम्स की अभी तक २० साल से अवहेलना होती रही थी उनको हम क्या दे रहे हैं वह आप इन आंकड़ों से देखे। सन् ६५-६६ में आयुर्वेदिक सिस्टम के लिए ७२,२७,९०० रुपया रखा गया और होम्योपैथिक के लिए ३,२१,९०० रुपया रखा गया, सन् ६६-६७ में आयुर्वेदिक के लिए ७८,९९,८०० रुपया और होम्योपैथिक के लिए ३,३३,२०० रुपया रखा गया था और इस साल ६७-६८ में हमने आयुर्वेदिक के लिए ८९,५८,००० रुपया और होम्योपैथिक के लिए ४,४८,३०० रुपया रखा है। उनका कोई तो माकूल मापदण्ड होना चाहिए था बजट को रिएक्शनरी कहने का। जो हमारे इनडिजिनस सिस्टम २० साल तक उचित प्रोत्साहन उनके हाथ से न पा सके उनको हमने प्रोत्साहित किया और जिस आयुर्वेदिक कालेज में वह शांति न स्थापित कर सके उसको हम अन्य मेडिकल कालेजों के समकक्ष लाना चाहते हैं, हम विशेषज्ञों का सम्मेलन बुलाना चाहते हैं कि किस तरह से हम इन सिस्टम्स की तरक्की करें लेकिन भूतपुर्व मंत्री जी को बजट रिएक्शनरी दिखाई दिया। चार्ज लगाने से ऐसा मालूम होता है कि अभी १०० साल तक वह इसी तरह हुकूमत करते रहते तो उनकी सरकार रिएक्शनरी न होती। राज छिन गया तो आज हम उनको नजर में रिएक्शनरी हो गये। हम तो आपसे रोशनी चाहते हैं, आप हमें सुझाव दें।

मेडिकल कालेज का जिक्र छेड़ दिया गया। हम तो चाहते थे कि आज उसका जिक्र न करें क्योंकि मुख्य मंत्रीजी उसका जिक्र कर चुके हैं और जिस दिन उसकी ग्रांट होगी उस दिन वह चीज जायगी और सुझावों पर विचार हो जायगा, हमें जिद्द नहीं है हम आपके सुझाव पर गौर करेंगे।

तीन प्रकार की यहां आलोचना हुई। कहा गया है कि देहात में दवाओं की कमी है यह गरीबों का बजट नहीं है, जिला परिषद् की डिस्पेन्सरी ठीक नहीं है। लेकिन जब हमारी प्लान को पैसा कम हो गया और केंद्र ने कम दिया तो प्लान तो छोटी होना ही थी, हर अनुदान में उसी हिसाब से कमी हो गई। हम चाहते थे कि जिला परिषदों की जितनी भी डिसपेंसरीज हैं और जिन को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनकी हालत खराब है उनको हम अपने हाथ में लेना चाहते थे और जब भी हमारे साधन इजाजत देंगे हम ऐसा करेंगे। लेकिन वहां भी दवायें पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

यहां पर रूरल मेडिकल कालेज खोलने की बात कही गयी। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से अवश्य खोलेंगे। मेरे एक दोस्त ने सुझाव दिया कि स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव के नाम से एक मेडिकल कालिज खोला जाय लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब मौका आयेगा हम इस पर विचार कर सकते हैं।

जहां तक दवाइयों का प्रश्न है जितनी धनराशि हमारे पास होगी उतनी ही हम अधिक से अधिक दवाइयें खरीदने का प्रयास करेंगे। मैंने अपने भाषण में यह कहा कि हम अधिक से अधिक इस ओर प्रयास करेंगे। आप हमारा जवाब तलब करें तो हम बतायेंगे। हम चाहते ह कि जनता और सरकार के बीच में ठीक से समन्वय हो सके। हम चाहते हैं कि एक राज्य स्वास्थ्य सलाहकार समिति का निर्माण हो, जिला स्वास्थ्य सलाहकार समिति का निर्माण किया जाय ताकि वे जनता की शिकायतों को सुनें और सुझाव दें और जो जनता और सरकार के बीच में एक लिएजां का भी काम करे।

जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है मैंने यह नहीं कहा कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। बल्कि मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि मैंने अपने भाषण में शब्द भ्रष्टाचार का जिक्र भी नहीं

किया। कुछ ऐसा फैशन सा हो गया है कि भ्रष्टाचार के बारे में अवश्य कहो। मैं तो भ्रष्टाचार को अपने मुंह से कहने में भी अपनी बेइज्जती समझता हूं। एक बात मैं स्पष्ट किए देता हूं कि अगर हमारे साथी आगे की बेंचों पर बैठने वाले, मंत्री लोग ईमानदार होंगे तो हमारा विभाग कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकता। अगर हम अपने अधिकारियों से गलत काम करवायेंगे, तो हमारा विभाग जरूर भ्रष्ट हो जायगा।

हमारे बहुत से दोस्तों ने यह कहा कि डाक्टरों की कमी है लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि फलां जगह डाक्टर नहीं है और न उन्होंने यह लिखकर दिया कि उस जगह पर डाक्टर नहीं है।

जहां तक हमारी और जन-सेवी संस्थायें हैं जैसे राम कृष्ण मिशन आश्रम, सीतापुर में आंख का अस्पताल, फैजाबाद का अस्पताल और अलीगढ़ में आंखों का अस्पताल, हम उनको भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं। लखनऊ, जो हमारी राजधानी है, वहां एक बहुत अच्छा अस्पताल बन रहा है। यह अस्पताल १९६८ में बन जायगा। मैंने जो कुछ वहां पर देखा उससे यह आभास हुआ कि दुनिया के १० बड़े अस्पतालों में एक लखनऊ का अस्पताल भी होगा। इस प्रकार की संस्थाओं को सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए और वह देगी भी।

मेडिकल कालेज के जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, जिनको हम अपने परिवारों के सदस्य समझते हैं, उनकी समस्याओं की ओर भी ध्यान दिया जायगा।

डाक्टरों के तबादले के बारे में यहां पर कहा गया। वह जमाना चला गया जब किसी भी डाक्टर या अधिकारी का राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रोमोशन होता हो, या तबादला होता हो, वह व्यक्ति अगर ईमानदार है, लगन से काम करता है तो अवश्य प्रोमोशन पायेगा और आगे बढ़ेगा। मैं इस संबंध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जो ट्रांसफर किए गए हैं या कुछ का डिमोशन किया गया है, वह सब पोलिटिकल मोटिव्ज से किए गए हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो भी पदोन्नति हो वह सिनियारिटी और मेरिट के आधार पर हो। पहली बार आपको विभाग को बधाई देनी चाहिए इसलिए जो हमने नियम बनाया है उसके अनुसार डाक्टर जा रहे हैं। अगर किसी डाक्टर को कोई तकलीफ है तो वह हमको बता सकता है कि यह उसे तकलीफ है लेकिन अगर कोई डाक्टर सिफारिश करता है तो उसको हम नहीं सुनेंगे। १० साल से बड़े डाक्टर को जिला हेडक्वार्डर पर रखा जायगा, ५ साल से कम वाले को तहसील हेडक्वार्टर पर रखा जायगा और इसमें कहीं कोई कमी हो तो माननीय सदस्य बतायें। इसलिए यह कहना कि डाक्टरों की बदली नहीं होनी चाहिए थी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जो एमीनेंट डाक्टर हैं उनको ऐसे अस्पतालों में भेजना है जिन अस्पतालों की हालत खराब है और ऐसे डाक्टरों को हमें आगे बढ़ने का मौका देना है जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है।

पिछली सरकार के जमाने में जो २ रु० जनरल वार्ड में फीस लगायी गयी थी, मैंने कई अस्पतालों को देखा है कि सारी बेड्स खाली हैं, १३ लाख रु० की जहां आमदनी होनी चाहए थी पिछले ५ महीने के अन्दर वहां १ लाख रु० की भी आमदनी नहीं हुई है। तो हम विचार कर रहे हैं, और जो हमारे साथियों ने कहा उस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि जनरल वार्ड में फीस नहीं लेनी चाहिए चाहे प्राइवेट वार्डमें फीस बढ़ानी पड़े। कटौती के प्रस्तावक महोदय ने जिन बातों के बारे में बताया है उस ओर हमारा प्रयास पहले से है, इसलिए मैं समझता हूं कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे, मैं चाहूंगा कि आप हमारा सहयोग करें जिससे गरीब जनता को आगे बढ़ा सकें।

मेरे दोस्तों ने एक चीज कही है कि जो आबादी का फारमूला है उसे फिर दोहरा दिया जाय। १ घण्टे म ४०० बच्चे पैदा होते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि १ घण्टे में एक गांव बन रहा है और एक दिन में एक पंचायत तैयार हो रही है और एक सप्ताह में एक विकास क्षेत्र तैयार हो रहा है और ५ महीने के भीतर एक जिला तैयार हो रहा है। तो इतना बड़ा जब खतरा है,

[श्री प्रताप सिंह]

हमारा फर्ज हो जाता है कि यह जो खतरे की घन्टी बज रही है इसके निवारणार्थ आप सरकार को सहयोग दें और फेमिली प्लानिंग के कार्य में हमारी मदद करें।

चेचक की बात कही गयी कि उस ओर कुछ नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि हमारे मंत्रिकाल में अगर एक आदमी भी चेचक से मरता है तो दुख की बात है। पिछली सरकार ने चेचक के टीके लगाने वालों को निकाल दिया। तो एक तरफ कहा जाता है कि चेचक बड़ी खतरनाक बीमारी है और दूसरी ओर जब कांग्रेस सरकार सत्ता से गयी तो तमाम वैक्सीनेटरों को हटा दिया गया। हमने जानबूझ कर कोई उपेक्षा नहीं की है। हम महसूस करते हैं कि चेचक ऐसी बीमारी है जिस में प्रीवेन्टिव मेजर्स इन्सान को बचा सकते हैं। विभाग इस ओर सजग है और हमने आदेश दे दिया है कि चेचक की बीमारी को वार फुटिंग पर टैकिल करना चाहिए जिससे आगे कोई मौत चेचक से न हो। जिन माननीय सदस्यों ने आज के अनुदान पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं मैं उन सब का आभारी हूं।

एक बात डाक्टरों के बारे में कही गयी कि मद्रास सरकार से डाक्टर मंगाये गये तो उनकी भाषा समझने में दिक्कत होगी न जाने कितने कलेक्टर हमारे यहां काम कर रहे हैं जो मद्रास के रहने वाले हैं। फिर नवल किशोर जी ने राष्ट्रीय एकता का नारा लगाया था, यानी यहां का डाक्टर मद्रास जाय और मद्रास का डाक्टर यहां आये। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेलें।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)---

मैंने मंत्री जी के निदेशालय की एक शिकायत भेजी थी उनके पास, उस पर मंत्री जी ने क्या किया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या १९ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य (१) चिकित्सा प्रणाली को सस्ता तथा जन-साधारण को सुलभ करना।

(२) होमियोपैथिक, यूनानी तथा आयुर्वेदिक शिक्षाओं को सुलभ तथा एलोपैथिक के समकक्ष बनाने हेतु डाक्टरों के वेतन-क्रमों आदि में सुधार करना।

(३) देहाती क्षेत्रों में डाक्टरों की नियुक्तियां करना तथा मेडिकल कालेजों से निकले हुए छात्र तथा छात्राओं के लिए एक समय नियत करना जिससे देहातों में रह कर उपचार कर सकें।

(४) सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर सुविधायें प्रदान करना जिसमें हर समय वे जनता के लिए अस्पतालों में सुलभ हो सकें।

(५) देहाती क्षेत्रों के अस्पतालों में अनुदान में बढ़ोत्तरी कर दवा को आम जनता हेतु सुलभ करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष----

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९--- चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,१२,०८,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २०--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों का चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,९४,१४,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं एक कामरोको प्रस्ताव के संबंध में बताना चाहता हूं जो श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' का है । उसे मैंने अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय इस संबंध में लेना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है । उस पर आपको अब भाषण देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मैं यह बात अर्ज कर दूं....

श्री उपाध्यक्ष--

फिर आप क्यों समय ले रहे हैं ?

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

आपने अस्वीकृत किया, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि यह हमारी घोषित नीति है हिन्दी के संबंध में और अंग्रजी को हटाने के सिलसिले में, इसलिये मैं मुख्य मंत्री से कहूंगा कि जितने भी उन विद्यार्थियों के केसेज हैं वह अवश्य ले लिये जायं और अंग्रेजी में फेल हाई स्कूल और इंटरमीडियेट के विद्यार्थियों को पास कर दिया जाय, नहीं तो जनतंत्रीय परम्पराओं को धक्का पहुंचेगा और उनसे जनता की आस्था हटेगी ।....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राकेश जी, अब आप स्थान ग्रहण करें ।

## फैजाबाद जिले में घाघरा नदी के कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कल्पनाथ सिंह जी की एक सूचना नियम ५१ के अन्तर्गत आयी है । एक राज राजेश्वर जी की भी है । इसके अतिरिक्त नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें माननीय चन्द्र देव और माननीय लक्ष्मीरमण जी आचार्य की भी है । इसी तरह की एक बाबू बदरे जी की और एक माननीय मुक्तिनाथ राय जी की है । इनमें माननीय कल्पनाथ सिंह जी

[श्री उपाध्यक्ष]

की सूचना को मैंने स्वीकार किया है । और चूंकि एक स्वीकृत हुयी है इसलिये अन्य को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है । जो माननीय राज राजेश्वर जी की सूचना है उसे स्वीकार न करते हुये भी संबंधित माननीय मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिये गये हैं । इसी तरह से माननीय लक्ष्मीरमण जी आचार्य की सूचना को भी कार्यवाही हेतु माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया गया है ।

श्री बाबू बदरे--(जिला कानपुर)--

हमारा प्रस्ताव संबंधित भी माननीय मंत्री जी के पास भेज दीजिये ।

श्री रामायण राय--(जिला देवरिया)--

माननीय कल्पनाथ सिंह जी का प्रस्ताव पढ़ दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कल्पनाथ सिंह जी का जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है उसको मैं आपके समक्ष पढ़ देता हूं ।

"ग्राम देवारा गंज बरार, दशरथपुर और माझा कलां, तहसील टांडा, जिला फैजाबाद, में घाघरा नदी के कटने के बाद पुनः कई हजार भूमि बाहर आ गयी है । इस भूमि पर पुराने काश्तकार अपना कब्जा रखना चाहते हैं । किन्तु उस भूमि पर फैजाबाद एवं बस्ती के कुछ गोलबन्द एवं धनीमानी व्यक्ति अपना कब्जा करना चाहते हैं । इस संबंध में माल विभाग के कर्मचारियों ने चुप्पी साध रखी है । बावजूद इसके कि उपरोक्त ग्राम के काश्तकारों ने हाकिम परगना टांडा के आदेश के अनुसार पैमाइश के लिये पैसा भी जमा कर दिया है किन्तु लगभग ७ महीने के बाद भी आज तक पैमाइस नहीं हो सकी जब कि खरीफ की बोवाई प्रारम्भ हो गयी है । अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि व इसकी पैमाइस कराते । इसी बीच गत २८ जून, को फैजाबाद एवं बस्ती के कुछ लोगो ने उक्त भूमि पर कब्जा करने के लिये हजारों की संख्या में आये और जो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे उन्हें खदेड़ ही नहीं दिया बल्कि उनकी झोपड़ियो को भी उजाड़ कर फेंक दिया । उपरोक्त गांव में अब शान्ति व्यवस्था भी अब खतरे में पड़ गयी है । २८ जून की इस घटना तथा अधिकारियों की लापरवाही के कारण उस क्षेत्र में व्यापक रोष असंतोष एवं भय व्याप्त हो गया है ।

अतः मैं विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली के नियम ५१ के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं ।"

माननीय मंत्री जी इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

राजस्व उप मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह यादव)--

४ तारीख को वक्तव्य दे दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३७ मिनट पर सोमवार, ३ जुलाई, १९६७, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१ जुलाई, १९६७ ।

# नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ ८५२ पर)

---

अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के अन्तर्गत अन्य कटौती के प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये हुए माने गये।

| क्रम सं० | प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|
| १ | श्री रामायण राय तथा श्री राज बहादुर मिश्र। | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—मेडिकल कालेज को सरकार को ले लेने की नीति की आलोचना करना। |
| २ | श्री इन्द्रमणी | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—(१) यह चर्चा करना कि पर्वतीय जिलों में चिकित्सा की सुविधा देने के लिये कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है।<br>(२) समान कार्य करने वाले चिकित्साधिकारी को समान वेतन पाने से वंचित किया गया है ? |
| ३ | श्री प्रभूदयाल | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—जोगिया अस्पताल की बांधसी पर मंत्री महोदय का ध्यान खींचना। |
| ४ | श्री प्रभाकर त्रिपाठी | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—सरकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा ई० एस० आई० के अन्तर्गत संचालित चिकित्सालयों की नीति-रीति की आलोचना करना। |
| ५ | श्री लाली चरण अग्रवाल | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—(१) प्रदेश के अनेक अस्पतालों में डाक्टरों के न होने पर चर्चा तथा अस्पताल में दवाइयों की चोरी और व्यापक भ्रष्टाचार पर विचार करना एवं सुझाव देना।<br>(२) मेडिकल कालेजों के प्रबन्ध पर सुझाव देना। |
| ६ | श्री चन्द्रबली | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—नीति की आलोचना करना और सुझाव देना कि २०० रुपये से नीचे वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों तथा दूसरे पेशे के २०० रुपये से कम मासिक आमदनी वालों और रिक्शा चालक, खेत मजदूर, को मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की जाय। |

| क्रम सं० | प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|
| ७ | श्री रामायण राय तथा श्री राज बहादुर मिश्र । | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य--सामान्य चर्चा और आलोचना । |
| ८ | श्री चन्द्रसिंह रावत तथा श्री इन्द्रलाल । | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये की कमी की जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य--सरकारी नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना । |
| ९ | श्री माता प्रसाद | चिकित्सा के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य--जौनपुर जिले के शाहगंज अस्पताल का राष्ट्रीय करण हो जाने पर भी साज-सज्जा की व्यवस्था नहीं है तथा शाहगंज महिला अस्पताल में लेडी डाक्टर की नियुक्ति न होने से जनता में व्याप्त असंतोष की ओर ध्यान दिलाना । |
| १० | श्री कल्पनाथ सिंह | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपये की कमी की जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य--ग्राम डेरवा, असवनपार, ददरी और गोरखपुर के उन अन्य गांवों में जो ५ मील से अस्पताल से दूर हैं, अस्पताल के न होने के संबंध में चर्चा करना । |
| ११ | श्री चन्द्रबली | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य--इस विभाग के निदेशक के विरुद्ध जून १९६७ में मुख्य मंत्री और चिकित्सा मंत्री को दिये गये शिकायत पर, जिसकी जांच में देरी की जा रही है, चर्चा उठाना । |

---

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०-४९ एस० ए०--१९६७--८४६ ।